TITLE CODE : UPHIN49731

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 1, संयुक्तांक : 08-09 आजमगढ़ • फरवरी-मार्च 2022 • मूल्य : ₹30

यूपी चुनाव

कहां है निगाहे,
कहां है निशाना...

प्रयाग से पटना तक
दौड़ा दौड़ाकर मारा

80:20 बनाम 15:85

आउट सोर्सिंग में
कौन हो रहा आउट?

जाने यू.पी. की
जनता का मूड

डिजिटल चुनाव :
लोकतंत्र को खतरा तो नही?

विपक्ष पर भारी न पड़
जाए पोस्टल बैलेट...

कर्नाटक में हिजाब पर बवेला...

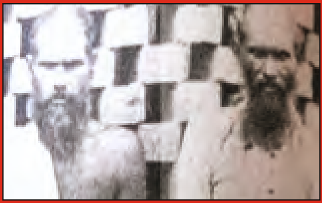

जरा याद इन्हें भी कर लो...

संपादकीय

जनता लड़ रही चुनाव- इस बार...

इस बार के चुनाव में लगता है दल और नेता नहीं, जनता और सत्ता के बीच मुकाबला चल रहा है और लोग तो तभी हारेंगे, जब कुछ खास 'जुगत' भिड़ाई जाये ! वरना'जनादेश' से तो जनता हारने से रही ! जनता 'हिन्दू-मुसलमान' भी नहीं बन रही है। जनता में बेरोजगार, बेहाल और परेशान लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गयी है कि वे 'हिन्दू-मुस्लिम' क्या और क्यों बनेंगे ? लोगों का आदमी के रूप में ठीक से जीना, बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना मुश्किल हो गया लगता है। पांच किलो अनाज और कुछ रूपये मिल रहे है, पर क्या इक्कीसवीं सदी में सम्मानजनक जीवन के लिए महज पांच किग्रा अनाज और एक बोतल तेल पर चुनावी बहस हो। यह क्या है ? आज़ादी के 70 साल बाद, खाने को अनाज देकर वे ख़ुश हो सकते हैं कि इसके बदले लोग उन्हें वोट देंगे। हो सकता है, कुछ लोग ऐसा करे भी। पर क्या लोग बेरोजगारी, बेहाली, अशिक्षा, पलायन और शासन का बुलडोजर सब कुछ भूल जायेंगे ? रातोंरात बिना परिवार को मुंह दिखाए लड़की का शव जला दिया गया। क्या इन सबका लोगों के मानस पर कोई असर नहीं होगा ? ताली-थाली जमकर बजाई, फिर भी महामारी घर के अंदर घुस आई और फिर जो हुआ, वह पूरी दुनिया ने देखा। हमारे श्मशानो और कब्रिस्तानो की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। पर आंकड़े छुपाये जाते रहे। लोगों के घर-बार उजड़ते रहे और कुछ अरबपतियों-खरबपतियों की सम्पत्ति सौ से दो सौ गुना बढ़ती रहीं। एक तरफ, स्कूल-कालेज ठप्प दूसरी ओर भव्य सरकारी भवनों को गिराकर 'हिन्दुत्व शैली वाले नये-नये भवन' बनाने का काम चलता रहा। लोगों की नौकरियां छिनती रहीं, सरकारी कंपनियां बिकती रहीं।

इन सबके बीच मुकाबले के लिए दलों या नेताओं द्वारा जिस तरह का मुकाबला या घेरेबंदी होनी चाहिए वह नहीं दिख रही। 80:20 की खुलेआम बात करके सत्ता दल के छोटे नेताओं ने चुनाव में खूब जहर उगलने का काम किया, जिसका शीर्ष नेतृत्त्व द्वारा विरोध या खंडन न करके उस पर मुहर लगा दी गई। मुँह से सबका साथ सबका विकास का नाम लेकर चलने वाले बगल में देश के हर पांचवें आदमी को खुलेआम अलग करके ना केवल चल रहे हैं, बल्कि उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 80 भाग वोट हमारा है, बाकी में बंटवारा है का नारा लगाया जा रहा है। चलो आप सारा वोट ले लो, 20 भाग वालो को चुनाव में टिकट भले ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकि जगह यानी नौकरी, पुलिस, सेना, कारपोरेट में क्या देंगे ? कैसे देंगे। कितना देंगे, बताइए 1, 2, 5 या कि 10 या नहीं देना चाहते तो सबका साथ कीबात तो झूठ साबित होगी, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। सबके नाम पर हिन्दुओं को एक करने के दौरान ही यह जोर-जोर से बताया जा रहा है कि अमुक सरकार में एक जाति ने सारी मलाई खाई, कितनी खाई ये गिन कर नहीं बता पाए, लेकिन चिंता कि बात यह है कि विरोध का झंडा उठाये सपा, कांग्रेस या बसपा इन मामलों पर ना केवल साफ्ट दिख रहे हैं बल्कि कई बार उन्ही की पिच पर बैटिंग करते दिखते हैं। सत्ताधारी दल के छुट भैया नेता मुसलमानों की वोट ना लेने की बात भी कर रहे है, अनु 370, मंदिर, तीन तलाक, बुरका-हिजाब, से लेकर बुलडोजर तक पर चुनावी सभाओं में चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे हैं।

जबाब में कोई विपक्षी दल या नेता जबाबी मुकाबला करता नहीं दिख रहा। कई बार तो उन्ही की पिच पर जबाब देते हैं या और आगे बढ़कर जबाब देते हैं, जैसे कि मंदिर और भव्य बनवा सकते हैं, या कि अपने क्रिया कलापों से सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रमाण देते नज़र आते हैं। यही नहीं सामाजिक न्याय जैसे मामलों पर विपक्षी पार्टियाँ खुलकर बोलने से कतराती हैं, जबकि मुकाबले के लिए सबसे ताकतवर और आजमाया हुआ तरीका यही साबित हो सकता था। जाति जनगणना, सामाजिक न्याय जिस पर सत्ता को घेरा जा सकता था, उस पर या तो किसी कमजोरी के कारण या फिर मजबूरी में कभी-कभी बोला जा रहा है। लेकिन जनता इन मामलों पर सत्ता को घेर लेती नज़र आ रही है, जिसका परिणाम हुआ कि प्राइमरी टीचर भर्ती में जनता के दबाव और आन्दोलन के आगे मजबूर होकर उत्तर प्रदेश में सरकार को आरक्षित वर्ग के लिए दोबारा भर्ती निकालनी पड़ी।

जनता की लड़ाई का दम तो किसानों ने चुनाव से पहले ही दिखा दिया था। नेता और दल तो नहीं लड़ पाए, लेकिन जनता ने कानून रद्द करवाया। सत्ता के नेताओं /पार्टियों की रैलियों/सभाओं में जनता की नाराज़गी भी कई बार और कई रूप में और कभी-कभी तो विद्रूप रूप में सामने आईं। प्रधानमंत्री के काफिले के आगे आना और खाली कुर्सियों ने सत्ता और जनता की लड़ाई को नए अंदाज़ में पूरे देशही नहीं दुनिया ने देखा। यह अलग बात है कि मामले ने दूसरा रूप ले लिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी तंत्र के उपयोग और तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद लोगो की भीड़ नहीं जुट रही। कहा तो यह जा रहा है कि चुनाव घोषणा के ठीक पहले लखनऊ में एक विशाल रैली होनी थी, जो नहीं हुई। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इज्जत तो चुनाव आयोग ने बचा ली, जिसने रैली/सभा में कितने लोग होंगे, इस पर लगातार लगाम रखी। दूसरी ओर नेताओं/पार्टियों के कम संसाधनों/कम मुखर रहने के बावजूद भीड़ अच्छी दिख रही है। शायद जनता में यह भी सन्देश है कि ED, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर विपक्ष की कमजोरी है।

आगामी 10 मार्च को सत्ता और जनता की लड़ाई में जीत तो किसी दल/नेताओं की ही होगी, लेकिन आने वाले समय में अगर जनता के मुद्दों की अनदेखी हुई तो जनता को लोकतान्त्रिक लड़ाई के बजाय लोकतंत्र के लिए लड़ने, आगे आना होगा, जो यूरोप में कई सदियों पहले लड़ लिया गया था।

नरेन्द्र

TITLE CODE : UPHIN49731
आजमगढ़ (उ.प्र.) ▪ संयुक्तांक : फरवरी-मार्च
सन् - 2022 ▪ वर्ष - 1 ▪ अंक : 8-9

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप

सह-सम्पादक
डॉ. नरेश कुमार साहू

प्रबंध सम्पादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
डॉ. प्रमोद कुमार
विक्रमजीत
बिनिका दुर्गम
कमलेश यादव
मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - परिभाषा
लखनऊ - देशराज (एडवोकेट)
बिहार - आलोक नाथ 'भंटू'
छत्तीसगढ़ - डॉ.जितेंद्र सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादुर
महाराष्ट्र - आकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कानपुर - सुनील कुमार सुनील
कुशीनगर - कोमल प्रसाद
वाराणसी - विजय कुमार
बलिया - विनय कुमार

विधिक सलाहकार
अमरजीत चक्रवर्ती
रविशंकर यादव

डिजाइन एंड ले-आऊट
प्रभाकर प्रिंट हाऊस
+91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वारा, आजमगढ़
उत्तरप्रदेश पिन - 276 001
संपर्क : +91 9453171770
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 9453171770

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप द्वारा मेट्रो प्रिंटिंर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व तथागत शहीद द्वार, सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन - 276 001 से प्रकाशित।

इस अंक की झलकियां

घटनाचक्र - बसावन इंडिया डेस्क 9
आज़ादी की लड़ाई की झांकी को पछाड़, काशी धाम नंबर वन 12
आउट सोर्सिंग में कौन हो रहा आउट? 15
जाति को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने संरक्षित सूची में जोड़ा 19
ऐसा चाहूँ राज मैं 25
समृद्ध भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स बहुजनों का चैंबर बनाने की जद्दोजहद 26
रिटायर्ड/पेंशनर पुरुषों को ठगते वैवाहिक विज्ञापन 28
डिजिटल चुनाव : लोकतंत्र को खतरा तो नही? 30
गढ़ों में गढ़: प्रतापगढ़ 34
आधा सिलेबस गायब कर दिया सरकार! 37
फिल्मों में : दक्षिण से आती बयार 42

11 **प्रयाग से पटना तक दौड़ा दौड़ा कर मारा** - रेलवे की एनटीपीसी भर्ती में रिजल्ट की विसंगतियों को लेकर पटना...

12 **आज़ादी की लड़ाई की झांकी को पछाड़, काशी धाम नंबर वन** - तमिलनाडु की झांकी को इस बार राजपथ...

17 **लालू को जेल पर जेल** - अपरकॉस्ट हिंदू वर्चस्व की निर्णायक राजनीतिक चुनौती देना महंगा पड़ा...

37 **आधा सिलेबस गायब कर दिया सरकार!** - आजकल के समय को हम कोरोना का काल भी कह सकते हैं कोरोना...

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रुप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकाशित सामग्री में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं सहयोगी संपादकीय टीम इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान हेतु न्याय क्षेत्र आजमगढ़ होगा।

कहां है निगाहे, कहां है निशाना...

80:20 बनाम 15:85

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

80:20 की बात अब खुलकर, हल्ला बोलकर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने सीधे मुसलमान का नाम नहीं लिया और न ही भाजपा के किसी जिम्मेदार नेता ने लेकिन, मीडिया ने हाल में उत्तर प्रदेश के विपक्षी खेमे के मुखिया अखिलेश यादव से पूछा कि 80:20 यानि हिन्दू मुस्लिम की आपके पास क्या काट है? भारत के चुनाव में ऐसा होना, किस दिशा की ओर देश को ले जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यह बात तय है कि हिन्दू मुसलमान को आमने सामने रखकर चुनाव लड़ा जाना या हिन्दू बनाम मुस्लिम बना कर चुनाव लड़े जाने के परिणाम देश के लिए सुखद नहीं हो सकते। मुसलमानों की आबादी 20 प्रतिशत के आसपास है, लेकिन सत्ता, नौकरी, पुलिस, मीडिया, न्यायपालिका, बिजनेस, खेती कहीं भी न केवल खराब है बल्कि चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुसलमान को टिकट भी नहीं दिया है। नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह ने कहा कि मंदिर बन रहा है, अगर अखिलेश में हिम्मत है तो बुलडोजर चलवाकर देखें। उधर कुछ कथित अपराधियों के नाम पर मुस्लिम नेताओं के घरों पर बुलडोजर चलवाकर योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से अपनी चर्चा बढ़ा रहे थे, ऐसे में अखिलेश यादव ने भले ही किसी सवाल का जबाब सीधे नहीं दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि मंदिर हम और जल्दी बनवा सकते है।

80 बनाम 20 की गहराई में जाने के लिए बसावन इंडिया ने नौकरी, पुलिस, मीडिया, न्यायपालिका, बिजनेस आदि में हिन्दू बनाम मुस्लिम का पता लगाने कि कोशिश की। एक भी जिलाधिकारी नहीं, कप्तान नदारद, किसी आयोग में नहीं, पुलिस में नाम मात्र एक्का-दुक्का, थाने से में थानेदार नहीं तो फिर उनको 20 तक लाने की बात कहाँ हो रही है? उनकी आबादी 20 प्रतिशत है जिसे कम नहीं किया जा सकता। भागीदारी 20 प्रतिशत तक देना तो दूर की बात होगी। इसके लिये बसावन इंडिया ने सामाजिक न्याय शोध केंद्र बरेली के आंकड़ों का उपयोग किया है। इसमें मुसलमान नदारद है, पर चौकाने वाले आंकड़े कह रहे हैं कि भागीदारी के मामले में 15 बनाम 85 कि लड़ाई दिख रही है। डॉ. रोशन लाल का मानना है कि सरकार सारे क्षेत्रों में शायद सवर्णों को 80 प्रतिशत तक पहुंचना चाहती है और बहुजनों को 20 में समेटना चाहती है।

यह आंकड़े जनवरी 2022 के हैं जो चुनाव घोषणा के ठीक पहले एकत्र किए गए हैं।

बसावन इंडिया ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके पाया कि सामाजिक न्याय का धुवां या करंट अंदर अंदर जल या कि चल रहा था, जो चुनावी चिंगारी पाते ही ज्वालामुखी कि तरह फूट पड़ा है। एक ही तरह के इस्तीफा पत्र, लगता था जैसे एक ही जगह टाइप किए गए थे जिसमे पिछड़ों दलितों के हितों की अनदेखी करने की बात की गयी। अखिलेश यादव जो कभी जाति और आरक्षण पर बात करने से कतराते थे, उन्होंने जाति जनगणना और भागीदरी पर खुलकर बात करनी शुरू की और सामाजिक न्याय का नाइरेटिव भी चल निकला। कुछ बुद्धजीवियों को विशेषकर सोशल मीडिया पर

रजनीश कुमार (राजू पासी)
युवा नेता एंव सामाजिक कार्यकर्ता

अब किसी को जातिवाद दिखाई नहीं देता है। आज जब प्रदेश के 75 जिलों में लगभग आधे बेसिक शिक्षा अधिकारी और एक तिहाई जिलाधिकारी एक ही जाति से है। मैंने तो सुना था कि योगी की कोई जाति नहीं होती है लेकिन यहाँ तो योगी की जाति भी और जातिवादी भी। एक व्यक्ति जिसपर कई गंभीर मुकदमे है, खुले आम घूम रहा है क्रिकेट खेल रहा हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती क्यों की वह मुख्यमंत्री की जाति का है। योगी जी भी बहुत अहंकार के साथ दावा करते है कि वो क्षत्रिय जाति में पैदा हुए हैं। मैंने अबतक जातिवाद का इतना नंगा नाच नहीं देखा है।

बसावन इंडिया टीम ने आंकड़ों का विश्लेषण किया और अपने पाठकों के समक्ष सरल तरीके से प्रस्तुत कर रही है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी

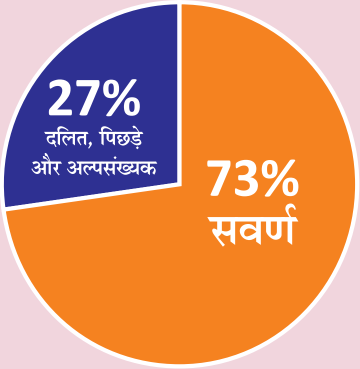

बेसिक शिक्षा अधिकारी में लगभग आधे क्षत्रिय यानी ठाकुर है। जिस जाति से मुख्यमंत्री स्वंय आते हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं और इस समय में शिक्षा मंत्री भी इसी जाति से आते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान एक चौथाई के लगभग हैं।

प्रदेश के 75 जिलों में से 55 सवर्ण जाति के हैं। 75 में से 36, लगभग आधे क्षत्रिय हैं, 14 ब्राह्मण और शेष पांच अन्य सवर्ण जातियां बनिया और कायस्थ शामिल हैं। 75 जिलों में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की संख्या मात्र 20 है। उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों में सवर्ण समूह की भागीदारी 73% और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक जनसमूह की भागीदारी 27 % ही है।

जिलाधिकारी अधिकारी

जिलाधिकारियों के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्थिति थोड़ी बेहतर है पर यहां भी 75 में से 24 यानी एक तिहाई जिलाधिकारी क्षत्रिय(ठाकुर) यानी मुख्यमंत्री की जाति से हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं जिनकी संख्या 9 है और एक उप मुख्यमंत्री भी इसी जाति से हैं। दिलचस्प है कि एक अन्य उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जाति से एक भी जिलाधिकारी नहीं है।

प्रदेश में तैनात जिलाधिकारियों में 24 जिलाधिकारी क्षत्रिय, 9 ब्राहमण और 14

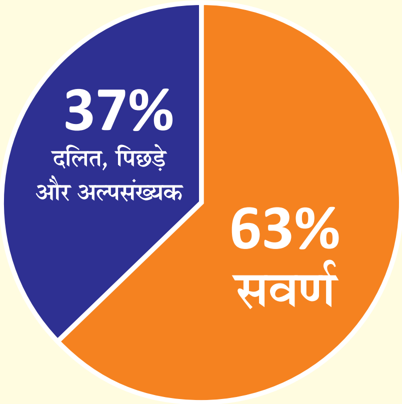

बनिया, कायस्थ जैसी अन्य सवर्ण जातियां शामिल हैं। शेष 28 दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। प्रदेश में तैनात जिलाधिकारियों में सवर्ण समूह की भागीदारी 63% है जबकि पिछड़े/ दलित/ अल्पसंख्यकों की भागीदारी मात्र 37% है

पुलिस कप्तान

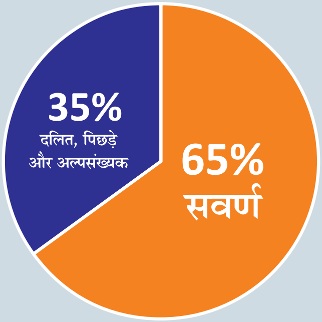

जिला कप्तानों की भी स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। उनकी स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। प्रदेश के 71 जिलों में से ब्राहमण कप्तानों की संख्या 18 है, क्षत्रिय 17 और अन्य सवर्ण जातियां जिनमें बनिया और कायस्थ शामिल है उनकी संख्या 11 है। शेष दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की संख्या 25 है। तीन पुलिस कप्तानों की जाति पता नहीं चल पाई। उत्तर प्रदेश में तैनात 71 जिला कप्तानों में सवर्ण समूह की भागीदारी 65% है जबकि पिछड़े/ दलित/ अल्पसंख्यक जनसमूह की भागीदारी 35% है

उत्तर प्रदेश के आयोगों की स्थिति

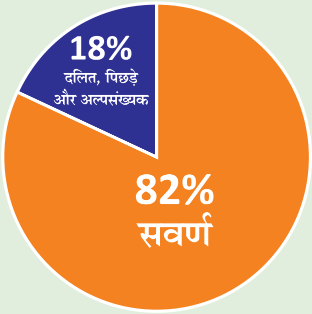

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोगों की बात करें तो वहां 82% पदों पर सवर्ण जातियों का कब्जा है शेष 18% पदों पर ही पिछड़े/ दलित और अल्पसंख्या जनसमूह की भागीदारी है। लोगों का मानना है कि इसके चलते इन आयोगों की विभिन्न भर्तियों पर विवाद रहा|

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

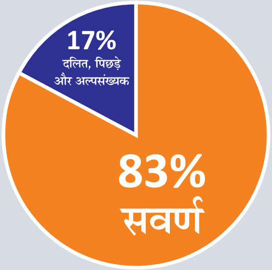

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और पांच सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष और एक सदस्य ब्राहमण हैं। शेष एक क्षत्रिय,एक बनिया एक कायस्थ और एक सदस्य अनुसूचित जाति से आती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के महत्वपूर्ण 83% पदों पर सवर्ण जातियों का कब्जा है शेष 17% पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।

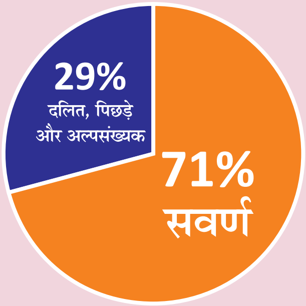

उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लोक सेवकों के चयन के लिए उत्तरदायी है। पिछले कई सालों से आयोग की कार्य पद्धति पर सवाल उठते रहे हैं। बसावन इंडिया ने अपने जनवरी अंक में आयोग की विवादों में रही भर्तियों का विस्तर से प्रकाशित किया था। खण्ड शिक्षा अधिकारी और पीसीएस 2017 और 18 के डिप्टी एसपी के अनारक्षित पदों आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की हिस्सेदारी न के बराबर रही।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष से लेकर सदस्यों का जातिवार विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि आयोग के अध्यक्ष क्षत्रिय जाति से आते हैं। छह सदस्यों में से चार सवर्ण जिसमे एक ब्राह्मण, एक छत्रिय एक बनिया और एक कायस्थ जाति से हैं। दो सदस्य कोइरी जाति से हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण पदों पर 71% सवर्ण और 29% पिछड़ों की हिस्सेदारी है। कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है।
नाम न छापने की शर्त पर आयोग के एक कर्मचारी ने बताया कि आयोग के गोपनीय और अन्य महत्वपूर्ण सेक्शन से ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दूर रखा गया है।

उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग

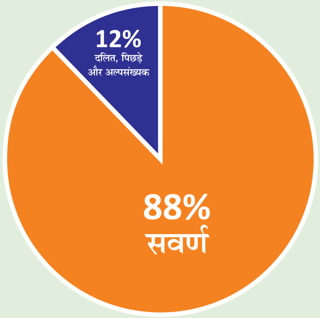

आने वाली पीढ़ियों के भविष्य निर्माण और उन्हें अवसर प्रदान किये जाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा सेवा चयन आयोगों की भूमिका बढ़ जाती है। ` प्रदेश में शिक्षकों के चयन के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी संस्थाएं है। लेकिन जब शिक्षकों के चयन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं में ही सामाजिक न्याय नहीं है तो इन संस्थाओं द्वारा चयनित शिक्षक सामाजिक न्याय कैसे स्थापित करेंगें|

उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर एक ओबीसी मात्र है। आयोग के सदस्य,सचिव,वित्त और लेखा अधिकारी सभी के सभी ब्राहमण शिक्षा मंत्री के जाति के हैं। आयोग के 88% पदों पर एक जाति विशेष का कब्जा है मात्र 12% पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व है।

माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड

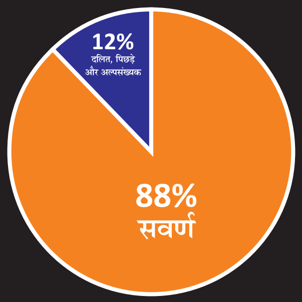

माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की स्थिति इससे कुछ अलग नहीं है यहाँ के अध्यक्ष ब्राहमण है। शेष 7 सदस्यों में से 5 ब्राहमण एक क्षत्रिय और 1 अन्य पिछड़े वर्ग से है। आयोग के 88% पदों पर सवर्णों का कब्जा है मात्र 12% पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व है।

महिला आयोग में अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश महिला आयोग और उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में भी स्थितियां कुछ अलग नहीं है। इन दोनों आयोगों में भी सवर्ण जातियों का कब्जा है।

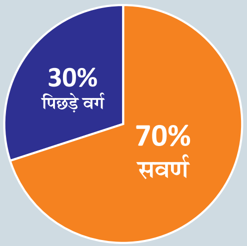

उत्तर प्रदेश महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 27 सदस्य हैं जिनमें 19 पदों पर सवर्ण जातियों का बोल बाला है जबकि शेष 8 पदों पर ओबीसी और एससी के लोग है जबकि अल्पसंख्यक जनसमूह से एक भी सदस्य नहीं है। अन्य शब्दों में 70 फीसदी पदों पर सवर्ण और 30 फीसदी पदों पर पिछड़े हैं। आयोग के अध्यक्ष पद पर सवर्ण का कब्जा है।

राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष

राज्य सूचना आयोग में कुल अध्यक्ष सहित 10 सदस्य है। अध्यक्ष पद पर सवर्ण जाति का कब्जा है शेष सात पदों पर भी सवर्णों जातियां हैं। मात्र दो पदों पर ओबीसी/एससी के लोग है। अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी नहीं है। अर्थात 80% सवर्ण जातियां और शेष 20 दलित और पिछड़े हैं।

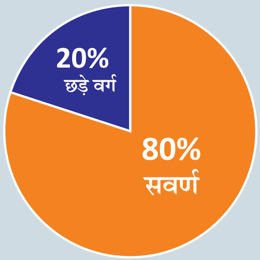

तो अखिलेश यादव में उत्तर का स्टालिन नज़र आने लगा। (ये अलग बात है कि समाजवादी परी के 22 संकल्पों में सामाजिक न्याय के नाम पर समाजवादी कैंटीन निकली और सामाजिक न्याय हवा निकलते दिखाई पड़ी।) ▪

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

क्या इस बार लखनऊ का सूरज पश्चिम से निकलेगा?

▪ **परिभाषा**

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रदेश की सत्ता पर क़ाबिज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व स्वयं देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अपने हाथों में ले रखी थी।

भाजपा ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फ़ौज उतार रखी है। जानकारों के मुताबिक़ भाजपा पश्चिम में मज़बूत दिखना चाहती है, क्यूँकि किसान आंदोलन के पश्चात भाजपा की स्थिति यहाँ पहले से काफ़ी कमजोर है। भाजपा इस कमज़ोरी को कम-से-कम करके यहाँ एक मज़बूत बढ़त लेना चाहती है जिससे प्रदेश के अन्य हिस्सों विशेषकर पूर्वांचल में एक प्रभावी संदेश दिया जा सके कि 'आल इज वेल'। यही कारण है कि देश के गृहमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कई वरिष्ठ मंत्री गाँव-गाँव, गली-गली जाकर मतदाताओं से वोट की अपील करते नजर आये।

भाजपा की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के कैराना में लोगों से जनसंपर्क किया तथा 2017 से पहले कैराना से पलायन हुए परिवारों से मुलाकात की। भाजपा के प्रचार अभियान से यह भी साफ़ झलक रहा है कि 2017 के चुनावों की तरह इस बार भी बीजेपी पलायन एवं कानून-व्यवस्था के मुद्दे को केंद्र में लाकर विपक्ष को घेरना चाह रही है जिससे सपा-रालोद गठबंधन द्वारा उठाए जा रहे बेरोज़गारी और किसानों की बदहाली के मुद्दे का डटकर मुक़ाबला किया जा सके लेकिन सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 'जिन्ना नहीं गन्ना' कहकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपने भाषणों में बेरोज़गारी और छुट्टा जानवर, महँगी बिजली, गन्ना भुगतान, जैसी तमाम किसानों की समस्याओं का मुद्दा ज़ोर-शोर से उठा कर मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को ध्यान अपनी ओर खींचा है और सत्तापक्ष को इन मुद्दों पर बोलने के लिए मजबूर किया है।

गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी में तीन कृषि कानून बड़ा मुद्दा था। हालाँकि केंद्र सरकार ने किसानों के भीषण विरोध और लम्बे आंदोलन के चलते तीनों क़ानूनों को वापस ले लिया है लेकिन गन्ना बेल्ट में आंदोलन के आफ़्टर इफ़ेक्ट्स को मैनेज करना अभी भी बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल किसान आंदोलन से पैदा हुए हालात को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में जुटे रहे।

जानें यूपी की जनता का मूड

बसावन इंडिया ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बुढ़ाना, धामपुर, नूरपुर, सहसवान और हसनपुर सीटों के मतदाताओं के एक बड़े बहुत बड़े संख्या वर्ग से संवाद कर यह पाया कि बीजेपी को यहाँ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि विपक्ष के लिए भी यहाँ की राह आसान नहीं है क्यूँकि क़ानून व्यवस्था के मुद्दे पर मतदाता अभी भी बँटे हुए हैं। अगर भाजपा इस मुद्दे को चुनाव के केंद्र में लाकर बेरोज़गारी और छुट्टा जानवरों की समस्या से बड़ा मुद्दा बनाने में सफल हो जाती है तो विपक्ष के चक्रव्यूह में दरार पड़ सकती है।

किसान आंदोलन को भुनाने की कवायद

अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रताप चौधरी का कहना है कि किसान आंदोलन से रालोद में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। चौधरी चरण सिंह के नाम पर जाटों की मजबूत घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरनगर में जाटों के ध्रुवीकरण को जयंत चौधरी धार देने में लगे हैं। सपा-रालोद गठबंधन किसान आंदोलन की नाराजगी से उम्मीद पाले है और इसको भुनाने की कवायद में जुटा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में हुए मुजफ्फरनगर कांड से जाट वोट रालोद-सपा से छिटका था। जिसका फायदा वर्ष 2014, 2017 और 2019 में हुए चुनाव में भाजपा को मिला था। आगरा में फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर सांसद बने। राजकुमार जाट समाज से आते हैं, जिन्हें किसान आंदोलन के दौरान भाजपा ने किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों में संदेश दिया। मुजफ्फरनगर में भाजपा के सांसद संजीव बालियान कमान संभाल रहे हैं।

इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद में जातीय गढ़ों को साधने की चुनौती

इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद जिले में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। 2017 में ऐसी लहर चली की सपा का गढ़ माने जाने वाले जिलों में भी भगवा परचम फहराया। इटावा की तीन सीटों में से भाजपा दो जीत गई, जबकि सपा के हिस्से सिर्फ जसवंतनगर सीट आई।

सबसे पहले बात चुनावी समरभूमि की। उसके भूगोल की और इतिहास की। इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद जिले में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। 2017 में ऐसी लहर चली की सपा का गढ़ माने जाने वाले जिलों में भी भगवा परचम फहराया। इटावा की तीन सीटों में से भाजपा दो जीत गई, जबकि सपा के हिस्से सिर्फ जसवंतनगर सीट आई। कन्नौज जिले की भी तीन सीटों में से सिर्फ कन्नौज सीट ही सपा जीत सकी, बाकी दो भाजपा के हिस्से में चली गईं। फर्रुखाबाद की चारों और औरैया की तीनों सीटों पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही थी। अलबत्ता, मैनपुरी में साइकिल तेज दौड़ी और चार सीटों में से तीन पर सपा ने कब्जा जमा लिया। महज एक सीट ही यहां भाजपा जीत पाई।

पश्चिम यूपी में जाटों की सियासत में जहां भाजपा और सपा-रालोद गठबंधन ताकत झोंक रहे हैं, वहीं दूसरे दल भी कसर नहीं छोड़ रहे। सभी जाट वोट में सेंध लगाने की कोशिश में हैं। जाट बहुल सीटों पर भाजपा और रालोद की जोर आजमाइश में हाथी को अप्रत्याशित सफलता मिल चुकी है।

पश्चिम के रण में जाटों के ठाठ हैं। आगरा और अलीगढ़ की 8 और मेरठ एवं सहारनपुर मंडल की 18 सीटों पर जाटों का प्रभाव है। चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, जाटों का वोट भी तय करता है। दिग्गज जाटों को साधने में जुटे हुए हैं। भगवा खेमा किसान आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई में जुटा है तो दूसरी तरफ सपा-रालोद गठबंधन आंदोलन की नाराजगी को भुनाना चाहता है।

आगरा मंडल में जिले की तीन सीटों फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़ व ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। मथुरा की चारों सीटें बल्देव, मांट, छाता और गोवर्धन जाट बहुल हैं। सहारनपुर और मेरठ मंडल में करीब 18 सीटों पर इनका प्रभाव है। ऐसे में दिल्ली में जाट नेताओं को साधने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मथुरा की याद आई। पहले 20 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में तैयारियां परखीं। उनके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने मोर्चा संभाला। एक-एक सीट को लेकर भाजपा ने मंडल में पूरी ताकत झोंक दी है। ▪

@+91 8826063330

सीट जहां जाटों का बहुलता

फतेहपुर सीकरी	1.10 लाख
आगरा ग्रामीण	60 हजार
मथुरा में मांट	1.30 लाख
मथुरा में बलदेव	1.20 लाख
मथुरा में छाता	50 हजार
मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र	70 हजार
हाथरस में सादाबाद क्षेत्र	1.30 लाख
अलीगढ़ में इगलास	1.05 लाख
अलीगढ़ की खैर सीट	1.05 लाख

(अखिल भारतीय जाट महासभा के अनुसार अनुमानित आंकड़े)

घोषणापत्रों में कुचला गया सामाजिक न्याय

सबका साथ सबका का विकास यानि सर्वजन् सुखाय की बल्ले बल्ले-यू पी में

- भाजपा के संकल्प पत्र में कहा गया ई.डब्ल्यू.एस. कल्याण बोर्ड का गठन कर ई.डब्ल्यू.एस. के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण एवं 10% ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय (सबका साथ सबका विकास) के तहत ओबीसी/ एस.सी. /एस.टी. समुदायों के सदस्यों को आवेदन के 15 दिनों के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र वितरण करने की व्यवस्था की जाएगी। इनके आरक्षण विसंगतियों पर कुछ नहीं कहा गया।
- सपा के 22 संकल्प में आरक्षण और जाति जनगणना के मामले पर कुछ नहीं था। बाद में जारी वचन पत्र में 'सामाजिक न्याय आयोग' के गठन की बात की गई, जो गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से निराश और संकटग्रस्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराई जाएगी। आरक्षण की विसंगतियों पर पार्टी ने कुछ नहीं बोला। जबकि 'सामाजिक न्याय आयोग' के गठन को गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से निराश और संकटग्रस्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उपाय सुझाने की बात करके पार्टी ने सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय में तब्दील कर गरीबी निवारण के रूप में पेश किया।

▪ **नरेंद्र प्रताप**

घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र यानि मनीफेस्टो अब सबके सामने है। भाजपा ने उप में 16 पेज का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमे 2017 से पहले और बाद की तुलना की है। सपा ने पहले 12 पेज का 22 संकल्प जारी किया और कुछ दिन बाद 88 पेज का वचन पत्र जारी किया। बसपा ने 6 पेज का बिन्दुवार विवरण जारी किया है जिसमे बसपा सरकार के दौरान किए गए कार्यो का विवरण है और कहा गया है कि सरकार बनने पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र तीन बार जारी किया जिसमे 'युवा विधान' 'शक्ति विधान' और 'उन्नति विधान' जारी किया।

सबका घोषणा पत्र पढ़ने पर, फ्री यात्रा, सस्ता खाना, युवा, महिला, आधुनिकीकरण, आधारभूत संरचना आदि की खूब लोक लुभावन बातें की गयी है, लेकिन सभी दल सामाजिक न्याय बच बचा कर निकाल जाना चाहते हैं, या सबका विकास /सर्वजन हिताय के नाम पर सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय में बदल देने की कोशिश कर रहे है। सपा ने 22 संकल्पों में सामाजिक न्याय में समाजवादी कैंटीन, सस्ती कैंटीन की बात की तो भाजपा ने सबका साथ सबका विकास के तहत माँ अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित करेगी जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था होगी।

सपा का सामाजिक न्याय -

सपा सामाजिक न्याय के तहत 'समाजवादी पेंशन योजना' को पुनः शुरू करेगी। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को 'प्रति वर्ष 18000 रुपए पेंशन' दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुँचेगा।इसके अलावा 'समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर' स्थापित किए जाएंगे जहां गरीब श्रमिकों, राजगीरों, बेघरों को सब्सिडाइज्ड दरों पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। इन कैंटीनों में '10 रुपए में समाजवादी थाली' की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य राज्य से भूख की समस्या को मिटाना है। आरक्षण और जाति जनगणना के मामले पर 22 संकल्पों में कुछ नहीं था।

बाद में 88 पेज के जारी वचन पत्र में सपा द्वारा 'सामाजिक न्याय आयोग' के गठन की बात की गई, जो गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से निराशऔर संकटग्रस्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उपाय सुझाएगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराई जाएगी। आरक्षण की विसंगतियो पर पार्टी ने कुछ नहीं बोला। जबकि 'सामाजिक न्याय आयोग' का गठन को गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से निराश और संकटग्रस्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उपाय सुझाने की बात करके पार्टी ने सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय में तब्दील कर गरीबी निवारण के रूप में पेश किया। बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर, दोपहिया वाहन यानि बाइक चालकों को हर माह एक लीटर मुफ्त पेट्रोल, ऑटो रिक्शा चालकों को मुफ्त तीन लीटर पेट्रोल/6 किलो सीएनजी, 'पीडीएस राशन वितरण की होम डिलिवरी की बात करके पार्टी ने सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय में तब्दील करने का प्रमाण दे दिया है। पार्टी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय योजना शब्द को भी लिया है जिसके तहत 'गेहूं, चावल, दाल और खाना पकाने के तेल के मुफ्त वितरण के लिए अंत्योदय योजना को दुबारा शुरू किया जाएगा।

सामाजिक न्याय के तहत वचन पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे शब्दों से बचाने का प्रयास किया गया है।

> एक व्यक्ति एक वोट से राजनैतिक न्याय तो मिल गया। मुफ्त शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, युवाओं को शिक्षा की अलग-अगल बड़ी-बड़ी बाते की गई है लेकिन, समान शिक्षा के मामले पर सभी चुप है। जो सामाजिक न्याय की दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है। सभी ने सामाजिक न्याय को गरीबी निवारण बनाने की भरपूर कोशिश की है।

भाजपा का सबका साथ सबका विकास-

भाजपा ने सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन सबका साथ सबका विकास चैप्टर में जिन मसलों पर बातें कि गईं हैं वे सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई हैं। पार्टी द्वारा सवर्णों के आरक्षण ईडबल्यूएस को प्रमुखता से लिया गया है, और संकल्प पत्र में कहा गया ई.डब्ल्यू.एस. कल्याण बोर्ड का गठन कर ई.डब्ल्यू.एस. के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण एवं 10% ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। पार्टी द्वारा 2017 के पहले और बाद कि तुलना की गयी है, पर 2017 के बाद पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में हुई विसंगतियों पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है की पार्टी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे सामाजिक न्याय की शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जाति, पिछड़ा व वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय (सबका साथ सबका विकास) के तहत पिछड़ा वर्ग समुदायों के सदस्यों को आवेदन के 15 दिनों के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र वितरण करने की व्यवस्था की जाएगी। माँ अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित कि जाएगी, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जातिवाचक रोजगार के अवसर जैसे कि

मछुआरा समुदाय के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए नदियों के पास लाइफगार्ड की नियुक्ति की जाएगी। संकल्प पत्र में ओ.बी.सी. युवाओं के लिए प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। ये अलग बात है कि इस हेतु पहले से स्थापित कोचिंगों का बुरा हाल है। सबका साथ सबका विकास के तहत जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था ओबीसी के साथ अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों को भी होगी, और आवेदन के 15 दिनों के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र दिया जाएगा। संत रविदास मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (ATS) स्थापित करेंगे।

लेकिन भाजपा द्वारा भी सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय में यानि गरीबी निवारण में तब्दील करने कि कोशिश खूब कि गई है। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 प्रतिमाह किया गया है जो सपा के 18000 प्रति वर्ष के बराबर है। निर्माण श्रमिकों को 1 लाख तक का कोलैटरल फ्री ऋण प्रदान करने के लिए उन्हें श्रमिक क्रेडिट कार्ड, प्रत्येक संभाग में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय,निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा और और सबसे बढ़कर मुफ्त शिक्षा कि दोबारा बात करके निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक की भी मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का विस्तार करते हुए मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सभी शहरों में टाउन वेंडिंग कमेटी की स्थापना, स्ट्रीट हॉकर्स एवं ई-कॉमर्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ई-कॉमर्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज को विभिन्न लाभकारी योजनाओं में शामिल करना, शहरों में ई-रिक्शा एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट सुविधाओं के साथ ऑटो रिक्शा स्टैंड एवं पार्किंग स्थल और सभी ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा जैसी बातें की गयी हैं। श्रमिकों की बातें इतनी विस्तार से दी गयी हैं कि लगता है जैसे उत्तर प्रदेश लेबर कालोनी के रूप में तैयार करने का प्रयास हो रहा है। ▪

घटनाचक्र - बसावन इंडिया डेस्क

मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ में मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय की नीव रखी गई। 700 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस विश्वविद्यालय को नागर शैली में तैयार किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का डिजाइन मंदिर नुमा तैयार किया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार मंदिर नुमा बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय लिखा गया होगा। जहाँ मेजर ध्यान चंद का स्टेचू लगा होगा। खेल विश्वविद्यालय को राजनीतिक और धार्मिक रंग देने की कोशिश की गयी है। उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए चुनावों में मौर्या/ कुशवाहा/ शक्य/ सैनी वोटरों को साधने की कोशिश की गयी है। भाजपा सरकार की नीतियों से ये जातियां असंतुष्ट थी।

जिन्दा लौट आया हूँ सीएम को थैंक्स बोलना - प्रधान मंत्री

पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाई ओवर पर बीस मिनट फसे रहे,वे फिरोजपुर में रैली करने गये थे। खराब मौसम के कारण उन्हें सड़क मार्ग का चयन करना पड़ा, रास्ते में ही हुसैनी वाला के निकट उनके सुरक्षा काफिले में सेंध लग गयी। प्रधानमंत्री का काफिला लगभग बीस मिनट तक फ्लाई ओवर पर फंसा रहा। प्रदर्शन कारियों ने उनके रूट को जाम कर दिया था। प्रधान मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मुद्दा गंभीर मुद्दा माना जा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्यवाही करने को कहा है। सोनिया गाँधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं उनकी सुरक्षा के मामले में पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मनाना है की प्रधानमंत्री के फिरोजपुर रैली में भीड़ नहीं थी जिसके कारण मामले को दूसरा रुख दे दिया गया। किसान आंदोलन के कारण रैली स्थल पर किसानों द्वारा प्रधानमंत्री के विरोध की प्रबल सम्भावना थी।

कोरोना के कारण लगातार बंद रहे स्कूल

उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों में अचानक वृद्धि 2038 नए मामले, दसवीं तक के स्कूलों को अचानक बंद करने का निर्णय लिया गया। कोरोना के बढ़ाते हुए मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया। बाद में धीरे धीरे स्कूलों को बंद किये जाने की तारिख बढ़ती रही। पूरे जनवरी भर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान बंद रहे।

एनईईटी (नीट) पर कोर्ट

एक अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 के लिए एनईईटी स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति दे दी। इसके साथ ही डॉक्टरों की भर्तियों में हो रही देरी की समस्या सुलझने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा है कि ओबीसी का 27 फ़ीसदी कोटा और आर्थिक रूप से कमज़ोर (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण बरकरार रहेगा। ईडब्ल्यूएस कोटा निर्धारित करने के लिए जो मानदंड इस्तेमाल किए गए हैं उनकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट मार्च ने विस्तृत सुनवाई करेगी।

चुनाव आचार संहिता लागू

08 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के साथ चुनाव आचार संहिता लागू, उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों की विधान सभाओं का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने इस बार के चुनावों में रैलियों और रोड शो पर रोक लगा राखी है। यह चुनाव आयोग का एक नया और अनूठा प्रयोग माना जा रहा है। केन्द्रीय चुनाव आयोग के इस फैसले को किसान आंदोलन और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों के दृष्टिगत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैलियों में कम भीड़ जुटाने और प्रबल विरोध की संभावना को देखते हुए सत्ता रूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हित में बताया जा रहा है।

सपा में आने वालों का लगा ताता

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद और सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर के सपा में जाने की घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी में अन्य दलों के नेताओं की लाइन लग गयी। मामला तब गरम हो गया जब भाजपा सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने इस्तीफा दे दिया। उनके साथ तीन और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धरम सिंह सैनी सहित आठ विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया। वन एंव पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भाजपा छोड़ दी। इसी के साथ ही भाजपा में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट से विधायक अवतार सिंह बढ़ाना ने भाजपा छोड़ लोक दल में शामिल हो गए। चुनाव आचार संहिता के बाद अन्य दलों में सुरक्षित ठिकाने तलाशने की होड़ मच गई। मुलायम सिंह यादव के समधी फिरोजाबाद की सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो गए। सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अर्पणा बिष्ट यादव भाजपा में शामिल। विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। भाजपा विधायक जितेन्द्र वर्मा ने पार्टी छोड़कर सपा की सदस्यता ली। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी एन सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

तीन महीने के भीतर जातीय जनगणना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना कराये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने के तीन महीने के भीतर जातीय जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। इस गणना के आधार पर सभी समाजों की समानुपातिक भागीदारी तय हो सकेगी। जातीय जनगणना की मांग देश में लम्बे समय से उठ रही है। केंद्र सरकार ने 2011 में जाति सम्बंधित आंकड़े तो एकत्र किये लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया। अभी तक 1931 में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े की प्रयोग में लाये जा रहे है जिसके कारण समाज के वंचित तबके को समुचित भागीदारी नहीं मिल पा रही है।

जितनी चाभी भरी टेलीप्रॉम्प्टर में...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दावोस अजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे कि इस दौरान एक समय वह रुके और फिर इधर-उधर देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हों ने सबसे पूछा कि ठीक से सुनाई दे रहा है या नहीं... विपक्ष के कई नेताओं ने यह वीडियो शेयर कर दावा किया कि मोदी के सामने मौजूद टेलीप्रॉम्प्टर जवाब दे गया था।

राहुल गांधी ने ट्वीट में ताना मारते हुए कहा, 'इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया।' विपक्ष की ओर से अक्सर मोदी पर 'जुमलेबाजी' का आरोप लगाया जाता रहा है।

ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस

स्टालिन ने गणतंत्र दिवस के दिन ये घोषणा की है कि वे ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस बनाने की पहल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें तमाम राज्यों के पिछड़े वर्गों के नेता होंगे और ये एक साझा मंच की तरह काम करेगा।

बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति को सफलतापूर्वक हिंदू बनाम मुसलमान और सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में सीमित कर दिया है।

इनमें से किसी के भी एजेंडे पर सामाजिक न्याय नहीं है, जबकि सामाजिक न्याय की राजनीति, जिसे पत्रकार जाति की राजनीति या पहचान की राजनीति भी कहते हैं, ने उत्तर भारत के दो बड़े राज्यों- यूपी और बिहार में एक समय बीजेपी के विस्तार को रोका था। उस दौर में मुलायम सिंह यादव, कांशीराम, लालू प्रसाद यादव और मायावती का बोलबाला था और इनमें से तीन तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर कांशीराम का भी जलवा हुआ करता था। दिल्ली तक में इनकी खूब सुनी जाती थी। 1989 और फिर 1996 में बनी मिली जुली सरकारों में, जब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल प्रधानमंत्री थे, तब ये नेता काफी असरदार हुआ करते थे और मीडिया में चर्चाएं होती थीं कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यहां तक कि यूपीए-1 में भी मुलायम सिंह, मायावती और लालू यादव का समर्थन काफी महत्वपूर्ण था। ▪

रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी भर्ती विवाद

प्रयाग से पटना तक दौड़ा दौड़ा कर मारा

प्रयाग में छात्रों की पिटाई

पटना में प्रदर्शन

▪ बसावन इंडिया डेस्क

रेलवे की एनटीपीसी भर्ती में रिजल्ट की विसंगतियों को लेकर पटना और प्रयागराज के छात्रों में उत्पन्न आक्रोश से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रयागराज पुलिस ने डेलीगेसियों में जा कर छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण कार्यवाही में कई छात्र चोटिल हो गये। घटना का विडिओ वायरल होने पर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से नॉन टेक्नीकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) भर्ती सीबीटी-1 परीक्षा के रिजल्ट 14 व 15 जनवरी, 2022 को जारी किए गए। परीक्षा में लगभग एक करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार पंजीकृत हैं, इस परिणाम के आधार पर सीबीटी-2 यानी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना था मगर उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि आरआरबी एनटीपीसी परिणाम में धांधली हुई है। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेनिंग क्लर्क, टिकट क्लर्क, ट्राफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड समेत कुल 35277 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए पहले चरण में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 15 से 19 फरवरी 2022 तक दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उपस्थित होना है।

क्या चाहते थे छात्र-

- **परीक्षा परिणाम को नये सिरे से संशोधित किया जाय**
- **उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी सभी स्लाट में चयनित हो गए**
- **स्क्रीनिंग टेस्टमें 20 गुना अभ्यर्थियों को जों वाइज क्वालीफाई कराया जाय।**
- **एक ही चरण नोटिफिकेशन जारी हुआ था बाद में दो चरण का नोटिफिकेशन जारी हो गया।**

रेल मंत्री का बयान-

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) श्रेणी के पदों एवं ग्रुप डी के रक्ति पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया को लेकर विवाद के संबंध में अब तक एक लाख से अधिक ज्ञापन प्राप्त हो चुके हैं और सरकार उन शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि एनटीपीसी के लिए टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज और ग्रुप डी के लिए एनएसई को चुना गया था। हमने एक समिति तुरंत गठित कर दी है जिसमें बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं। समिति के पास एक लाख से अधिक ज्ञापन आ चुके हैं। समिति को तीन सप्ताह में उसका निष्पक्षता से समाधान करना है। ग्रुप डी के लिए एक ही परीक्षा हो या दो, एनटीपीसी के दूसरे चरण में क्या किया जाए, टेस्ट का लेवल कैसा हो, इसका एक तय समय सीमा में समाधान किया जाएगा। छात्रों की भावना के अनुरूप पारदर्शी समाधान किया जाएगा। ▪

वीरेंदर कुमार गंगवार

प्रतियोगी छात्र

लंबे समय से जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में कटौती और परीक्षाओं में धांधली हो रही है, उससे बेरोजगारों की विकराल फौज में आक्रोश चरम पर है। उसका विश्वास, टूटने लगा है। वह समझ रहा है कि उसे ठगा जा रहा है या नौकरियां देना नहीं है, महज उलझाए रखना है, दूसरी ओर रेलवे तंत्र, नौजवानों में विश्वास कायम नहीं कर सका है। रोजगार देने के झूठे विज्ञापनों से बेरोजगारों का दर्द कम नहीं हो रहा। धर्म और व्हाट्सएप भुलावे, जमीनी हकीकत से दूर हैं। इसलिए बिहार में उपद्रव जारी है। स्थिति गंभीर है और लगता है किसान और बेरोजगारों की समस्याएं, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेंगी। इसको ईमानदारी से हल किया जाना चाहिए जिससे सरकारी सम्पतियों को नुकसान न पहुंचे।

आज़ादी की लड़ाई की झांकी को पछाड़, काशी धाम नंबर वन

उत्तर प्रदेश की झांकी

तमिलनाडु की झांकी

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

तमिलनाडु की झांकी को इस बार राजपथ पर दिखाने से मना कर दिया। आरोप लगा कि उसमें केंद्र सरकार अपनी पसंद थोपना चाहती थी। तमिलनाडू सरकार ने पहले तो उस झांकी को चेन्नई के गणतंत्र दिवस समारोह में रखा और बाद में इस झांकी को प्रदेश की जनता के बीच प्रदर्शित किया गया। लोग फूल बरसाये। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की परेड में इस बार तमिलनाडु की झांकी को शामिल न करने पर राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दक्षिणी सूबे के सीएम ने झांकी को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की और दावा किया कि ऐसा जानबूझकर किया गया।

क्या था झांकी मे- झांकी में आजादी की लड़ाई के दौरान तमिलनाडु के फ्रीडम फाइटर्स को दिखाया गया था, जिनहोने अंग्रेज़ो का बहदुरी से मुक़ाबला किया था। 10 जुलाई 1806 को हुई वेल्लुर क्रांति के बारे में प्रदर्शित किया गया था। झांकी में पुलिथेवन, विरपिल्ला कोट्टबोम्मन, वीरान सुंदर लिंगम, धीरन चिन्नामलाई, मरुथु ब्रदर्स, जैसे लोगों को दिखाया गया था जिनका इतिहास में नाम कम सुनाई पड़ता है।

दरसअल, केंद्रीय चयन समिति ने इस वर्ष दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि की झांकियों को परेड में शामिल करने की इजाजत नहीं दी है। बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी के राजपथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के लिए रक्षा मंत्रालय के पास राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से 56 जिनमें से सिर्फ 21 का चयन किया गया है, जबकि 36 प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है।

जबकि गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade 2022) में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, और भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी तीनों सेनाओं में शीर्ष पर रही। उत्तर प्रदेश की झांकी 'एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम' विषय पर आधारित थी। दूसरा स्थान कर्नाटक को 'पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने' पर आधारित झांकी के लिए मिला, जबकि तीसरा स्थान मेघालय को मिला। ▪

साइकिल पर बम...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साईकिल पर बम रखने की रखने वाला बयान देकर यूपी चुनावों में संप्रदायिकता का असफल प्रयोग किया। प्रधानमंत्री के इस बयान की निंदा बुद्धिजीवियों द्वारा की जा रही है वरिष्ठ सामाजिक चिंतक दिलीप सी मंडल ने अपने ट्विटर हंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री के भाषण में जो भी ऊटपटांग, बेवकूफी, सांप्रदायिक जहर होता है, उसके लिए प्रधानमंत्री नही, आशुतोष जिम्मेदार है। वही लिखता है। नरेंद्र मोदी पढ़ देते हैं तो दोषी कौन हुआ? अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी सूर्यप्रताप सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के नफरत भरे भाषण का जिस संजीदगी से अखिलेश यादव ने जबाब दिया है वो हर साइकिल वाले के दिल को छू जाएगा।

कर्नाटक में हिजाब पर बवेला...

समाज और राजनीति के हिन्दुत्वीकरण का कोई न कोई बहाना खोजने वाले संगठनों ने कर्नाटक के कुछ विद्यालय-महाविद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं के सिर ढंक कर आने या हिजाब लगाने पर भारी बावेला मचाया है। कर्नाटक का मौजूदा लिबास-विवाद पूरी तरह राजनीति के हिन्दुत्वीकरण का नतीजा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आदि के विधानसभा चुनाव में अगर सत्ताधारी दल को जनता की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता तो आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों को हिजाब पर ऐसा उपद्रव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती। विवाद उत्तर प्रदेश से सैकड़ो किमी दूर कर्नाटक में उठाया गया है। पर उस विवाद की आंच में उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही। ▪

विपक्ष पर भारी न पड़ जाए पोस्टल बैलेट...

इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट का दायरा बढ़ा दिया है, पहले यह सुविधा निर्वाचन कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए ही थी लेकिन अब इसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यंगों को भी शामिल कर लिए गया है। जिसके दुरूपयोग की शिकायते मिल रही हैं। प्रथम चरण के चुनाव में गाजियाबाद और कैराना के कई बूथों पर वोटर लिस्ट में उनके नाम के ऊपर PB की मुहर लगी थी। गाजियाबाद में पहले चरण के मतदान में भारी शिकायतें सामने आई हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो आज मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं और वहां उन्हें पता चला कि पोस्टल बैलट से पहले ही वोट डाली जा चुकी है। पहुंचे सैकड़ों मतदाताओं का मत पहले ही पड़ चुका था, जबकि न तो वो अस्सी वर्ष के थे और न ही दिव्यांग। कैराना में कई बूथों पर ऐसी शिकायतें आई।

बीएचयू में हिंदू अध्ययन और गोबर से उपले बनाने का पाठ्यक्रम

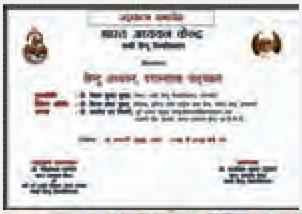

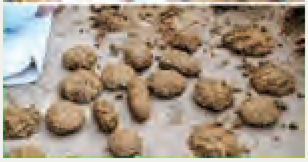

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन संस्थान ने हिन्दू अध्ययन परास्नातक पाठ्यक्रम को आरम्भ किया। पाठ्यक्रम समन्वय प्रो श्री प्रकाश पाण्डेय और समन्वयक प्रो. सदाशिव कुमार द्विवेदी हैं। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालयमें राजनीति विज्ञान के प्रो कौशल किशोर मिश्रा ने विद्यार्थियों को उपले बनाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने गोबर के महत्त्व को समझाया।

चर्चा में चेहरे ...

ओम प्रकाश राजभर : गठबंधन को अमलीजामा पहनाने का श्रेय

अपनी बेबाक और तल्ख टिप्पड़ियों की वजह से जाने जाने वाले सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मान्यवर कांशीराम के सहयोगियों को एक मंच पर इकट्ठा किया। किसानों की समस्या, साड़ों की समस्या,जाति जनगणना, आरक्षण, बेरोजगारी, महगाई, महिला सुरक्षा के मुद्दे, छात्रों की समस्याएं को चुनाव में मुद्दा बनया। बार बार हिंदु मुसलमान और साम्प्रदायिकता का राग अलाप रही भाजपा इन मुद्दों पर ला खड़ा किया|

चंद्रशेखर रावण : उभरता बहुजन नेतृत्व

भीम आर्मी प्रमुख चन्द्र शेखर रावण के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद और अधिक चर्चा में आ गये हैं। चंद्रशेखर रावण ने समाजवादी पार्टी से शुरुआत में गठबंधन करने की कोशिश की लेकिन सीटों के मुद्दे पर बात नहीं बन सकी। चंद्रशेखर रावण दलितों/ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ रखा है देश के किसी भी कोने में दलितों/ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उत्पीडन के मुद्दों पर खुलकर विरोध करते हैं।

डॉ पल्लवी पटेल : गठबंधन नया कुर्मी चेहरा

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के सिराथू विधान सभा सीट से अपना दल की डॉ. पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ा कर नया कुर्मी चेहरा बनाया है। पल्लवी पटेल से केशव प्रसाद मौर्य को कड़ी टक्कर मिल रही है। कुर्मी वोटरों ने यदि उनका साथ दिया तो पल्लवी पटेल का कुर्मी जाति में एक नया और बड़ा नेता होगा।जो अपना दल (सोनेलाल) की अनुप्रिया पटेल के साथ संतुलन स्थापित करेगा।

शैलेन्द्र यादव ललई: पिछड़ों को एक मंच पर लाने के सूत्रधार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 का नारा दिए जाने से पहले ही 85 बनाम 15 की भूमिका तैयार हो गयी थी। सपा विधायक और पूर्व मंत्री शैलेन्द्र यादव ललई ने पहले ही ओबीसी के कई नेताओं को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करा कर इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी। अंबेडकर नगर के दो कद्दावर नेताओं राम अचल राजभर और

लालजी वर्मा, दारासिंह चौहान, स्व. सुखदेव राजभर को ले जाकर अखिलेश यादव से मिलवाया। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी मछली शहर की रथयात्रा के दौरान जनसभा में खुले मंच से इस बात का श्रेय दिया था। शैलेंद्र यादव ललई को पूर्वांचल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नेता माना जाता है। इनकी 2004 में मुलायम सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उत्तर भारत में मान्यवर कांशीराम के बाद यह पहली बार हो रहा है कि बसपा के अपने मूल कर्तव्य से भटक जाने के बाद उत्तर प्रदेश कि उत्तर भारत के प्रमुख ओबीसी नेता अधिकतर एक मंच पर आ कर अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं यह अलग बात है कि अखिलेश यादव उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरते है या नही।

गुलशन यादव :फूल खिलेगा गुलशन में

पिछले तीस सालों से सामंतवाद का गढ़ रहे कुंडा में समाजवादी पार्टी द्वारा अपना उम्मीदवार उतारे जाने से यह सीट काफी चर्चा में है। सपा ने गुलशन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। गुलशन यादव द्वारा कुंडा में वर्षों से एकछत्र राज कर रहे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को कड़ी टक्कर मिल रही है। कुंडा विधायक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह पहली बार अपने महल से निकलकर जनता के बीच आना पड़ा। राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को टिकट देकर सपा ने यह स्पस्ट संकेत दे दिया है अब वह सामंती ताकतों से दो दो हाथ करने के मूड में है। यदि कुंडा से गुलशन यादव चुनाव जीतकर जाते हैं तो कुंडा से अन्य जातियों के लोग भी उम्मीदवारी कर सकेंगें सही मायनों में वहां लोक तंत्र की स्थापना होगी। राजा भैया के पूर्व में कुंडा विधानसभा सीट पर पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का कब्जा रहा है, नियाज हसन और जयराम यादव विधायक रह चुकें हैं।

आलमबदी : न कोई भौकाल और न ही कोई प्रोटोकाल

आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट से विधायक अलामबदी को जनता विधायक माना जाता है। अपनी ईमानदार और साफ सुथरी छवि के कारण वे कई वर्षो से निजामबाद से लगातार विधायक बनाते आ रहे है। जहाँ आज विधायकों और जन प्रतिनिधियों से मिलने के लिए बड़े बड़े भौकाल और प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है वहीँ उनसे मिलना उतना ही आसान है। राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय/ राजनैतिक / सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले आलामबदी आजमगढ़ शहर में दैनिक देवव्रत प्रेस कार्यालय पर कुर्सी पर दोनों पैर ऊपर किए आराम से बैठे मिल जायेंगे। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस में साधारण कपड़ों में आपको यात्रा करते हुए मिल जाएंगे। आलामबदी जी अपनी चुनाव तैयारियों के लिए कोई कार्यालय नहीं बनाते है। जनता से सीधा संवाद रखते हैं।

राजेश्वर सिंह

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही पार्टी ने उन्हें लखनऊ की सरोजनीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है।

राजेश्वर की पत्नी लक्ष्मी सिंह वर्तमान में लखनऊ रेंज के आईजी के पद पर तैनात हैं। जिसको लेकर विपक्षी पार्टियें ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा कि लखनऊ आई जी रेंज रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। दिल्ली मुख्यालय में रहने के दौरान उन्होंने 2जी घोटाला, जगन रेड्डी केस, कोलगेट केस, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील केस, ओपी चौटाला जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की। बड़ी-बड़ी जांचों के साथ बड़े-बड़े विवाद भी उनसे जुड़े। उनके खिलाफ कई बार सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई। ▪

बसावन इंडिया हिंदी मासिक पत्रिका का संचालन सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। पत्रिका को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संपादक मंडल की हर संभव कोशिश है कि खबरों को निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुँचाया जाए। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह जाति है तो हम अपने सम्मानित पाठकों से आशा करते हैं कि वे हमारा ध्यानाकर्षण करेंगें। साथ ही आप अपके लेख और विचार basavanindia@gmail.com पर स्वागत करतें हैं। बसावन इंडिया की कोशिश होगी कि वह आपके लेख और विचार संपादन के बाद प्रकाशित करे। यदि जगह के आभाव और मुद्दों के प्राथमिकता में आपके विचार और लेख छूट जाते हैं तो उसे अगले अंक में लेनें की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमे इंतजार रहेगा।

▪ नरेन्द्र प्रताप

आउट सोर्सिंग में कौन हो रहा आउट?

धीरे–धीरे पांव दबाये सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिये कर्मियों को लेने का चलन शुरू हुआ, तो बढ़ता ही गया, और बढ़ाते बढ़ते अब तो इस हाल तक पहुच गया कि सरकारी नौकरी के नाम पर युवा आउट सोर्सिंग के के लिए भी सोर्स लगाने के लिए चप्पलें घिस रहा है। इसके फायदे -नुकसान और विभिन्न पहलुओं पर पड़ताल करने पर पता चला कि अकेले उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से जुलाई 2021 तक आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगभग 2.73 लाख लोंगों को सेवायोजित किया गया। योगी सरकार द्वारा साढ़े चार लाख लोगों को चार साल में रोजगार देने में आउट सोर्सिंग ने बड़ी मदद की. आज कि तारीख में विभिन्न विभागों में टाइपिस्ट, ड्राईवर, डाटा इंट्री आपरेटर, चपरासी से लेकर सफाई कार्य जैसे कम के लिए एजेंसी के माध्यम से यानि आउट सोर्सिंग द्वारा कर्मी लिए जाने लगे, जिन्हें हायर और फायर के तौर पर रखा जाता है।नीति आयोग द्वारा वर्ष 2017 अप्रैल में यह सुझाव दिया गया कि सरकारी सेवाओं पर निर्भरता को कम करते हुए विभिन्न सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएं। जिसके साथ ही नीति आयोग द्वारा विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री के माध्यम से लिए जाने का परामर्श भी दिया था, जिससे ब्यूरोक्रेसी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी का तर्क दिया गया।

क्या है आउट सोर्सिंग ?

आउटसोर्स कर्मियों की विभिन्न विभागों में तैनाती की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण तथ्य है कि तात्कालिक आवश्यकता तथा कई बार शासन/प्रशासन की सिफारिशों के आधार पर अधिकांशतःचतुर्थ श्रेणी में/ ड्राइवरों इत्यादि के पदों पर विभिन्न विभागों सीधे संविदा/ दैनिक वेतन पर भर्तियां की गयी। कालांतर में इन पदों पर कार्य करने वाले अधिकांश कर्मियों को कोर्ट के निर्णय के आधार पर नियमित करते हुए विभिन्न विभागों को पूर्व में इन कर्मचारियों को 15 से 20 वर्ष तक का वेतन नियमित कर्मचारियों कि भाति देना पड़ा। इस समस्या के समाधान के तौर पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कर्मियों को सेवायोजित करने की व्यवस्था अस्तित्व में आई। इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी से क्रेता विभाग अपनी आवश्यकतानुसार अहर्ता तय कर कर्मियों को स्वयं निर्धारित भुगतान के आधार पर कर्मियों की सेवाएं प्राप्त कर सकता है और सेवाएं संतोषजनक न होने पर उन कर्मियों को वापस आउटसोर्सिंग एजेंसी के सुपुर्द किया जा सकता है और नए योग्य कर्मियों की मांग की जा सकती है।

> संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश मल्ल का कहना है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को कभी भी समय से वेतन नहीं मिलता EPF एवं ESI का समय से भुगतान नहीं होता जब चाहे पुराने कर्मियों को हटाकर नए को रख लिया जाता है सरकार को आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त कर कर्मियों को शोषण से मुक्त करना चाहिए

इस व्यवस्था में मुख्य रूप से तीन कोण है। पहला क्रेता विभाग इसे सेवाएं प्राप्त करनी है, दूसरा आउटसोर्सिंग एजेंसी जिसे कर्मियों को उपलब्ध कराना है। जिसके एवज में उसे नियमानुसार सेवा शुल्क देय है,जो प्रायः प्रतिस्पर्धा के कारण 5% तक हो सकता है। तीसरा कोण - आउट सोर्स कर्मचारी है जिसका

धर्मेंद्र यादव
युवा नेता

नेता बेरोजगारी की समस्या के समाधान में आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए मानदंडों हेतु एक रोड मैप लेकर आएं, जिसमें जहां एक ओर योग्य कर्मियों के चयन की पारदर्शी व्यवस्था हो, वहीं दूसरी ओर वेतन भुगतान, सेवा शर्तें ठीक और तार्किक हों, सभी वर्गों कि समुचित भागीदारी हो, और अवकाश आदि विषयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

भुगतान भुगतान प्रायः 10 हज़ार से लेकर 25 हज़ार तक है। आउटसोर्सिंग कर्मियों में भी प्रायः दो प्रकार की श्रेणियां स्पष्ट हैं, पहला जिनकी तैनाती किसी शासन/प्रशासन की सिफारिश के आधार पर की गयी, दूसरे जिनको योग्यता तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी को सुविधा शुल्क देने के उपरांत जिनको आउटसोर्स कर्मी के रूप में रखा गया। इन तीनों श्रेणियों में सर्वाधिक प्रभावित योग्य व गंभीर आउटसोर्स कर्मी हैं। प्रायः देखा गया है कि जिन कर्मियों की तैनाती किसी सिफारिश के आधार पर हुई है वे प्रायः कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। उन्हें ना तो कार्य की जानकारी है न ही कार्य में रुचि। उसके पश्चात भी उनकी प्रभावी पृष्ठभूमि के कारण उन्हें पूरा भुगतान समय से प्राप्त हो जाता है। जबकि वे आउटसोर्स कर्मी जो तुलनात्मक रूप से अधिक गंभीर और योग्य हैं वे भुगतान की तुलना में न केवल अधिक कार्य करते हैं बल्कि व्यवस्थागत शोषण के भी शिकार है। उदाहरण स्वरूप मानव संसाधन को 'जेम पोर्टल' से अनिवार्य करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2 का दिनांक 25 अगस्त 2020 का शासनादेश अवकाशों, मातृत्व अवकाशों, भुगतान की स्थितियों पर अस्पष्ट है तथा यह निर्धारण करने की जिम्मेदारी क्रेता विभाग पर छोड़ता है। जबकि आउटसोर्स कर्मियों के अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं भुगतान का अस्पष्ट होना उन्हें शोषण के लिए आसान शिकार बनाता है फलतः अधिकांश युवा महिला कर्मियों को गर्भावस्था/ प्रसव पश्चात की अवधि में या तो नौकरी छोड़नी पड़ती है अथवा भुगतान के बिना आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ती है। शिकायत यह भी है कि EPF व ESI जमाएं भी अधिकांश आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन से कटौती कर एवं क्रेता विभाग से प्राप्त कर ली जाती है। जो धन राशि समेकित रुप से प्रायः कई लाख रुपए होती है, किंतु संबंधित आउटसोर्सिंग कर्मियों की अनभिज्ञता व क्रेता विभाग द्वारा लापरवाही/ अनदेखी के कारण EPI/ESI की धनराशि भी जमा नहीं करायी जाती है जिसमे इन कर्मियों को बड़ी आर्थिक हानि होती है।

इसी प्रकार आकस्मिक अवकाश जैसे किसी अवकाश की स्पष्टता ना होने के कारण अधिकांश विभागों द्वारा किसी आकस्मिकता के कारण कार्यालय न आने पर भुगतान में कटौती कर ली जाती है। अथवा कोई सुविधा शुल्क देकर उपस्थिति अंकित की जाती है जिसके कारण पुनः आउटसोर्सिंग कर्मी विशेषकर महिला कर्मियों को शोषण का शिकार होना पड़ता है, जो समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुए।

अगर हम क्रेता विभाग की स्थिति देखें तो आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में स्पष्ट मानदंड ना होने के कारण जिस प्रकार की योग्यता के कार्मिक लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग की एक निर्धारित चयन प्रक्रिया मानदंड के कारण प्राप्त होती है उसकी तुलना में आउट सोर्स एजेंसी से प्राप्त कर्मियों की योग्यता क्षमता अपेक्षित स्तर से काफी से काफी नीचे होती है। जिसके कारण विभाग की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है साथ ही साथ आउट सोर्सिंग कर्मियों एवं क्रेता विभाग का एक दूसरे के साथ स्पष्ट रिश्ता कायम नहीं हो पाता जो उत्तर दायित्व के बोध से वंचित कर्मी उपेक्षापूर्ण रवैया झेलता रहता है।

आउटसोर्सिंग भर्तियों में सभी वर्गों की भागीदारी नहीं-

शासकीय सेवाओं के योजन जैसी कोई निर्धारित व्यवस्था स्पष्ट व्यवस्था ना होने के कारण एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। भारत के संविधान में उल्लिखित हम भारत के लोग में से बहुसंख्यक लोग भागीदारी का स्वाद नहीं चख पा रहे हैं। इस हेतु ना तो किसी राजनीतिक दल द्वारा और ना ही किसी कर्मचारी संघ द्वारा कोई आवाज उठाई जा रही है।

स्वामी प्रसाद मौर्य
पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश

बेरोजगार नौजवानों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से बहलाने फुसलाने की कोशिश की गई। हमने कैबिनेट में भी आउटसोर्सिंग भर्ती का विरोध किया। हमनें कहा कि जब सरकार के आर्थिक भार में कोई कमी नहीं होती है पूरा पैसा खर्च होता ही होता है तो आउटसोर्सिंग भर्ती क्यों सीधी भर्ती क्यों नही? बेरोजगार नौजवान नौकरी तो पता ही लेकिन वेतन कितना पाता है 7 हज़ार/ 8 हज़ार/ 9 हज़ार या फिर 10 हज़ार। पैसा कहाँ चला जाता है बिचौलिए को। हमने बिचौलिए को खत्म करने को कहा था। सरकार नहीं मानी। आखिर बिचौलिए को खत्म क्यों नहीं कर रही है सरकार? पता लगा कि आउटसोर्सिंग के जो मालिक है बड़े नेताओं के इर्दगिर्द घूमने वाले लोग है।

यदि हम वर्ष 2017 से नौकरियों में भर्ती का विश्लेषण करें तो यदि विचारणीय है कि क्या आउट सोर्सिंग कर्मी नियमित कर्मियों का विकल्प है ? अथवा आयोगों के स्तर पर नियमित भर्ती ही बेहतर विकल्प है। स्पष्ट दिखाई देता है कि अधिकांश विभागों में लगभग 40 से अधिक हिस्सेदारी आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों की है जिनका कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। समय रहते इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए वर्ना लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए महंगा पड़ेगा।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद छोड़ते हुए जब हुंकार भर रहे थे तो सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि आउट सोर्सिंग करके सरकार का राजस्व जा रहा है जो बिचौलिए ले जा रहे हैं। ▪

@+91 9453171770

चारा घोटाले का खेल- अपरकॉस्ट हिंदू वर्चस्व

बनाम

लालू को जेल पर जेल

▪ **नवल किशोर कुमार**

चारा घोटाला से संबंधित पांचवे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी 2022 को फैसला सुनाया। इसकी अपेक्षा पहले से की जा रही थी कि लालू प्रसाद एक बार फिर से दोषी करार दिए जाएंगे। और यही हुआ भी। उनके साथ 74 अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषी माना। वहीं 25 आरोपियों कोर्ट ने निर्दोष माना। लालू प्रसाद को पहले ही चार मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है और सजा के तौर पर उन्हें 14 साल की जेल व 60 लाख रुपए का दंड दिया जा चुका है। हालांकि लालू प्रसाद ने हार नहीं मानी है और उन्होंने सीबीआई कोर्ट के फैसलों को रांची हाई कोर्ट में चुनौती दी है। परंतु, हाई कोर्ट में उनकी अपील को तवज्जो नहीं दी जा रही है, लिहाजा उनके मामले लंबित हैं।

चारा 'घोटाले' के घोटाले का एक पेंच और घोटाले का नायक

बहरहाल, उपरोक्त सूचनाएं वे सूचनाएं हैं, जिन्हें याद रखा जाएगा, लेकिन इसके पीछे की बातें शायद ही इतिहास संरक्षित रखेगा। चारा घोटाला के संबंध में कुछ दस्तावेजों और रपटों की पड़ताल मैंने वर्ष 2012 में की थी। हालांकि जब पहली बार सीबीआई कोर्ट के भूमिहार न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद को दोषी करार दिया था, तब अमित खरे नामक एक नौकरशाह, जिसे चारा घोटाले का नायक कहा गया था, उसने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था– "अंत में ही सही, इंसाफ हुआ है"। लेकिन वह कौन था, जिसने खरे को सबसे पहले पशुपालन विभाग के कार्यालयों में छापा मारने को कहा था?

आज इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 105 के रूप में अमित खरे ने लालू के वकीलों द्वारा किए गए क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया कि 19 जनवरी, 1996 को सबसे पहले वित्त विभाग की ओर से उसे एक अलर्ट फैक्स के जरिए एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें पशुपालन विभाग में अधिक निकासी की बात कही गयी थी। खरे की स्वीकारोक्ति इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि चाईबासा के उपविकास आयुक्त होने के कारण जिले में होने वाले सभी सरकारी खर्चों पर बिना उनके हस्ताक्षर के किसी प्रकार का सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता था। इसमें पशुपालन विभाग के खर्चे भी शामिल थे। तो सवाल उठता है कि उन्होने पशुपालन विभाग में अवैध निकासी की जांच क्यों नहीं की? न तो सीबीआई और ना ही जज प्रवास कुमार सिंह ने उसे इसके लिए उन्हें जिम्मेवार माना।

सीबीआई कोर्ट ने भी अमित खरे को कन्फेस करने के लिए नहीं कहा। जबकि अदालत में यह बात खरे द्वारा लिखित रूप में रखी जा चुकी थी, कि केवल दो महीने के अंदर बीस करोड़ रुपए की निकासी की गई है, जो पूरे वर्ष के लिए आवंटित निकासी से भी बहुत ज्यादा है। प्रथम जांच अधिकारी होने के नाते अमित खरे को सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन उनकी नींद तो तब खुली जब राज्य मुख्यालय ने उसे अलर्ट किया। बेशक अमित खरे ने अदालत में यह स्वीकार किया उन्होने चाईबासा केस में एफआईआर कराया, लेकिन यह तब हुआ जब राज्य मुख्यालय में बैठे उसके सीनियर अधिकारियों ने उसे ऐसा करने के लिए दिनांक 31 जनवरी, 1996 को कहा। बाद में यह बात सामने आयी कि यह निर्देश मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में दिया गया था। लेकिन खरे ने इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद 20 फरवरी, 1996 को एफआईआर दर्ज कराया। ..शेष पेज नं-29 में..

अपरकॉस्ट हिंदू वर्चस्व की निर्णायक राजनीतिक चुनौती देना महंगा पड़ा

सिद्धार्थ रामू
स्वतंत्र पत्रकार एवं चिंतक

लालू यादव का सबसे बड़ा अपराध- अपरकॉस्ट हिंदू वर्चस्व को निर्णायक राजनीतिक चुनौती देना और ऐसी भाषा बोलना जो अपरकॉस्ट को चुभने वाली थी। लालू यादव की चारा घोटाले में कोई भूमिका थी या नहीं, इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यदि लालू यादव ने चारा घोटला से कई गुणा बड़ा घोटाला पक्के तौर किया होता, लेकिन उन्होंने राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व की राजनीति और अपरकॉस्ट राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती नहीं दिया होता और उनसे मेल-मिलाप करके रहते और सांस्कृतिक तौर पर अपरकॉस्ट को चुभने वाली भाषा न बोलते, तो उन्हें सजा नहीं होती। वे आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। जगदेव प्रसाद के शब्दों में अपरकॉस्ट-अपरक्लास हिंदू मर्द चाहते हैं कि पिछड़े-दलित राजनीति करें, लेकिन जैसे उनकी हलवाही करते थे, वैसे करें यानि उनके राजनीतिक हलवाहा बन जाए या कांशीराम के शब्दों में उनके चमचे बन जाए। लेकिन यदि पिछड़े-दलित निर्णायक तरीके से अपरकॉस्ट वर्चस्व को चुनौती देते हैं, तो उन्हें उसका परिणाम भुगतना होगा,जब भी शासक वर्ग मौका पाएगा, छोड़ेगा नहीं। कर्पूरी ठाकुर को गालियां सुनकर, बाबू जगदेव प्रसाद को अपनी जान देकर और लालू यादव को जेल की सजा काटकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

म.प्र. में शिवराज सरकार को पिछड़ा वर्ग आरक्षण क्यों लागू करना पड़ा?

▪ तेजबहादुर

मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के करीब 15 महीने बाद मार्च 2020 में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़तोड़ कर अपनी सरकार बनाने वाली भाजपा आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को लेकर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई देने की जी-तोड़ कोशिश कर रही है। पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण देकर हाथ जलाने वाली शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अब प्रदेश की सीधी भर्ती में 27% आरक्षण लागू किया है। इसके लिए जनवरी के अंत में बकायदा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस नए आदेश से राज्य में नौकरियों में आरक्षण का कुल दायरा 73% हो गया है। अब क्या इसे कोर्ट में चुनौती नहीं मिलेगी? यह बड़ा सवाल फिलहाल अनुत्तरित है, लेकिन पंचायत चुनाव आरक्षण की इसी गुत्थी के कारण जिस तरह से उलझे, उसे देखते हुए पिछड़ों के मन में सरकार के इस आदेश पर संदेह है। इस संदेह को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने यह कहकर और हवा दे दी है कि पिछड़ा वर्ग विरोधी भाजपा को आखिरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण को क्यों लागू करना पड़ रहा है। कहीं यह आरक्षण का सिर्फ दिखावा तो नहीं है।

फिलहाल शिवराज सिंह चौहान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में कुल 73% आरक्षण दिया जाएगा। यह लाभ सीधी भर्ती में मिलेगा। इसमें अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण शामिल है। ओबीसी को आरक्षण 8 मार्च 2019 और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू किया गया है। यानी उस समय से रिक्त पदों के आधार पर आरक्षित सीटों की गणना करके पदों को भरा जाएगा। अब भाजपा सरकार के इस आदेश को लेकर संदेह उठने के कारण है। 2018 के चुनाव से पहले भी भाजपा की सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान करीब 14 साल से मुख्यमंत्री थे। इस अवधि में न तो भाजपा और न ही शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ों के 27% आरक्षण देने की चिंता की। दरअसल प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% ही लागू था। 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने पर पिछड़ों के आरक्षण को 27% करने का सैद्धांतिक फैसला किया गया था। इससे पहले ही कांग्रेस सरकार इसे लागू कर पाती, उसकी सरकार को भाजपा ने जोड़तोड़ करके गिरा दी और मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर चौहान के हाथ में आ गई। अब राज्य में करीब डेढ़ साल यानी 2023 में चुनाव होने हैं। भाजपा की नजर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के वोटों पर हैं। इसे लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव कहते भी हैं कि भाजपा सरकार की पिछड़े वर्गों के खिलाफ साजिश की पोल खुलने लगी है। अब मजबूरन उसे तमाम जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर 8 मार्च 2019 को प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा लागू किए गए पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लागू कराना पड़ रहा है। भाजपा ने करीब दो दशक तक पिछड़ों के वैधानिक अधिकारों को दबाकर रखा था। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों की लड़ाई अदालत से लेकर जमीन तक लड़ी। अब भाजपा सरकार की टाल-मटोली नहीं चल पा रही है और इन वर्गों को आरक्षण देने के लिए आदेश जारी करना पड़ा है। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न विभागों में दो लाख से अधिक पद खाली हैं। कुछ विभागों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। लेकिन अब आरक्षण की नई व्यवस्था और 100 बिन्दु रोस्टर निर्धारण के बाद यहां नए सिरे से व्यवस्था करना होगी।

आरक्षण की सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था बनती है बाधक

जातिगत आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की है। हालांकि 2019 में केंद्र की भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में पारित करवा लिया। इससे आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 से बढकर 60%हो गई। जब-जब इससे अधिक आरक्षण लागू करने के प्रयास हुए इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने के कारण यहां आरक्षण की सीमा 60% से भी बढ़कर 73% हो जाती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब प्रदेश के जिन विभागों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहां सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% यानी पहले की स्थिति में बरकरार रखा है। अन्य विभागों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया है। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव मुक्तेष वार्ष्णेय की यह बात इस आशंका को बल देती है। वे कहते हैं कि जब तक आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नई गाइड लाइन जारी नहीं होती, तब सरकार सीधी भर्ती के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आरक्षण व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 पैरामीटर तय किए हैं, सरकार को उसका पालन करना ही होगा। ▪

@+91 9406955327

क्या है आरक्षण को लेकर दिशा-निर्देश : एक नजर में

- 8 मार्च 2019 के पहले जो पद रिक्त रह गए थे, उन्हें अलग समूह माना जाएगा। उनको आगे की भर्ती में कैरीफारवर्ड कर उसी वर्ग के उम्मीदवारों से भर्ती की जाएगी।
- 8 मार्च 2019 की स्थिति में ओबीसी को 14% बढ़ाकर 27%आरक्षण रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रहेगा। सभी श्रेणी में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू माना जाएगा।

अमेरिका में जाति भेद भाव को रोकने का अनोखा प्रयास

जाति को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने संरक्षित सूची में जोड़ा

दुनिया के तमाम अविष्कार में भारत की इकलौती जाति व्यवस्था का आविष्कार मानव समुदाय के लिए कितना उपयोगी है इसपर आज तक रिसर्च हो रहा है, लेकिन हाल ही में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने जाति को संरक्षित सूची में जोड़ दिया है, जिससे यूनिवर्सिटी में अध्ययन अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हर सदस्य को जातिभेद से दूर रखा जाएगा, यह सब एकाएक नहीं हुआ बल्कि एक वृहद् रिसर्च के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन को यह विचार आया कि अगर जातिभेद को संरक्षित सूची में नहीं जोड़ा गया तो जैसी स्थिति भारत के शिक्षण संस्थानों की है और जिस तरह भारत में सस्थानिक हत्या और जाति के नाम से कम नंबर देने जैसे घिनौने कृत्य भी शामिल है अगर वैसा कुछ हुआ तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का स्तर घट जाएगा, और शिक्षा का महत्त्व भी नहीं रह जाएगा।

▪ **डॉ. जितेंद्र सोनकर**

जाति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अकादमिक मंचो पर कैसे पहुंची इसकी यात्रा भी बड़ी रोचक है, दरअसल 4 अगस्त 2020 को इसाबेल विलकिरसन की पुस्तक पब्लिश हुई, जिसका शीर्षक था CASTE the origin of our discontents .इस किताब को पढ़ा जाने लगा और अमेरिकी टीवी की सबसे बड़ी स्टार ओपरा विनफ्रे ने अपने बहुचर्चित ओपरा बुक क्लब में इस किताब को शामिल कर लिया। ओपरा विनफ्रे ने इसे अपने बुक क्लब की सबसे महत्वपूर्ण किताब बताते हुए अमेरिका के 500 कंपनियों के सीईओ और देश के प्रमुख लोगों को ये किताब भेजी|इस किताब में भारत और भारत की जाति व्यवस्था का जिक्र विस्तार से और बार-बार आता है।

इसमें एक पूरा चैप्टर भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में है। भारत का जिक्र इस किताब में 136 बार आता है। जाति का जिक्र लगभग 1500 बार। भारतीय नायक ज्योतिबा फुले, बीआर आंबेडकर, गांधी और नेहरू तक की चर्चा की गई है इसमें उस प्रकरण का भी जिक्र है जब मार्टिन लूथर किंग अपने भारत दौरे में जब केरल पहुंचे तो तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में शिक्षक ने उनका परिचय कराते हुए कहा कि जिस तरह हमारे यहां अछूत होते हैं, वैसे ही ये अमेरिका के अछूत हैं। विलकिरसन ने इस किताब को लिखने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए दलित बस्तियों में घूम घूमकर देखने के बाद लिखी गई किताब है जो जाति की सच्चाई और जातिभेद से देश की स्थिति पर विस्तार से चर्चा शामिल हैं।

भारत का एक पूरा चैप्टर होने पर स्वाभाविक बात है कि अमेरिकी दलित नागरिक भी इस किताब की चर्चा जरुर करेंगे, अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सोशल वर्क विभाग में इस तरह के अध्ययन होते रहते थे, प्रवासी भारतीयों के लिए भी जाति एक गंभीर विषय बन चुका है, कलिफोर्निया में दलित नागरिक अधिकार संगठन 'इक्वेलिटी लैब्स' जातिभेद को लेकर बहुत समय से मुहीम चला रहें थे, पुलित्ज़र प्राइज विजेता अमेरिकी पत्रकार और लेखिका इसाबेल विलकिरसन की किताब को आधार

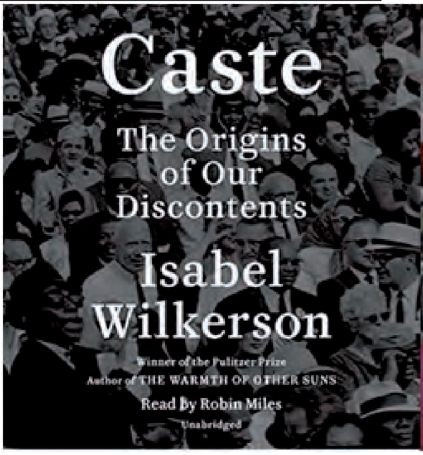

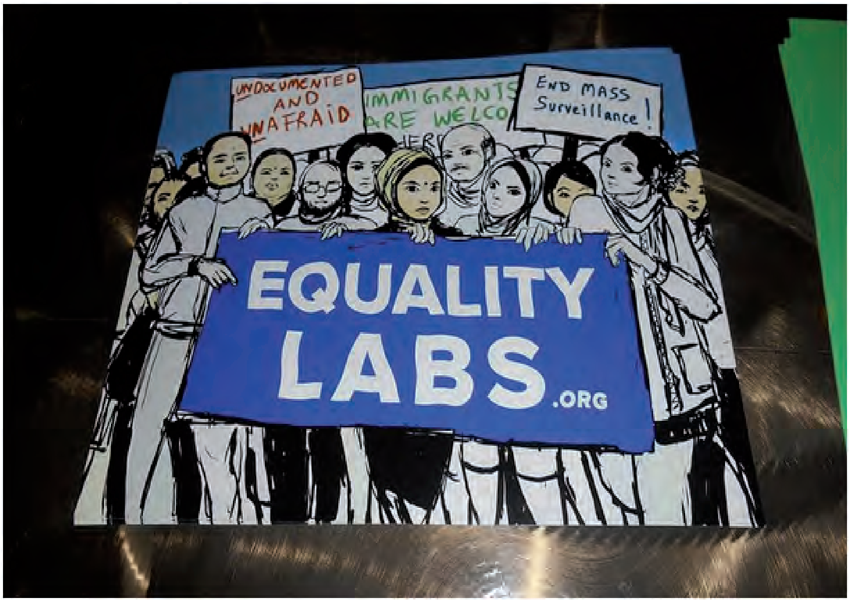

बनाते हुए 'इक्वेलिटी लैब्स' की कार्यकारी निदेशक थेनमोजी सौंदरराजन ने कैलिफ़ोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी (CSU) बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ के सामने रखा जिसमे उनकी संस्था द्वारा किया गया अध्ययन और दक्षिण एशियाई नागरिको पर किए गए जातिगत भेदभाव का दस्तावेज भी सबके सामने रखा।

इक्वॉलिटी लैब्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण 'कास्ट इन द युनाइटेड स्टेट्स' में इस बात का पर्दाफाश किया कि चार दलित छात्रों में से एक ने शारीरिक या मौखिक हमले का अनुभव किया है, जबकि एक तिहाई ने शिक्षा के स्थान पर भेदभाव की सूचना दी है। यह एक ऐसा मुद्दा था जो भारत की व्यवस्था में रच बस गया है, इसलिए अमेरिकी विश्वविद्यालय में जातिवाद की व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये सब जरुरी था अंततः दुनिया भर में तेजी से बढ़ते जाति आधारित भेद-भाव पर लगाम लगाते हुए कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी पहली ऐसी संस्था बनी है जिसने भेदभाव-विरोधी नीति में जाति जोड़ा है मतलब जाति आधारति भेद -भाव विरोधी नीति बनाया है। इसके साथ ही पूरे कैलिफोर्निया में 23 परिसरों में, जाति-उत्पीड़ित छात्र अब दलित विरोधी पूर्वाग्रह की रिपोर्ट करने में सक्षम होंगे।

अमेरिका में बसे भारतीय नागरिको में कुछ समुदाय के लोग इस नीति के लागू होने का विरोध कर रहे हैं विभिन्न तरीके से तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति भारत की देन है अगर ऐसे में जाति को एक विशिष्ठ और संरक्षित श्रेणी में जोड़ा जाता है तो सिर्फ भारतीय पर लागू होगा, यह एक तरह का अनोखा जोखिम है जिससे अस्तित्व पर खतरा बढ़ जाएगा, इससे पहले हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) के वकीलों, सुहाग शुक्ला, समीर कालरा और निखिल जोशी ने भी सीएसयू बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, सीएसयू ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल, सीएसयू चांसलर और कैलिफोर्निया फैकल्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष को विरोध पत्र भेजा था। दरअसल एक ही जाति समूह के शिक्षक अधिक होने की वजह से उन्हें लगने वाला है कि ये एक डाइवर्सिटी नीति से शिक्षको की नियुक्ति में भी जाति को ध्यान रखा जाएगा, इक्वेलिटी लैब्स' की कार्यकारी निदेशक थेनमोजी सौंदरराजन की टीम ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि जातिभेद करने वालों की बहुलता के कारण ये स्थिति बन रही है, इसलिए जाति को संरक्षित श्रेणी में रखा जाना बहुत जरुरी है इसके लिए लगभग 500 संबद्ध शिक्षाविदों, कई नागरिक अधिकार संगठनों और श्रमिक संघों के साथ 112 कैल स्टेट फैकल्टी ने कैल स्टेट नॉन-डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में जाति को जोड़ने के लिए समर्थन पत्र प्रस्तुत किए और सीएएल स्टेट ट्रस्टियों से बिना देरी के पुष्टि करने का आग्रह किया।

भारत में हर दूसरे दिन विश्वविद्यालय में जाति उत्पीडन की घटना होते रहती है सन 2015 में एक शिक्षक को बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया गया तो उसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से अपने जातीय उत्पीडन पर ट्वीट किया था, कुछ शिक्षक और छात्र अपने ऊपर होने वाले अत्याचार पर बोलने के लिए इतना हिम्मत भी नहीं कर पाते|

हैदराबाद विश्वविद्यालय के सांस्थानिक हत्या जिसमे रोहित वेमुला की जान चली गई और एक तरह से शिक्षण संस्थानों में जातिभेद पर खुलकर बात होना शुरू हुआ, इसी तरह JNU, DU, वर्धा और इलाहबाद विश्वविद्यालय में भी जाति उत्पीडन और आरक्षण नियमों का पालन नहीं कर पाना जैसे घिनौने कृत्य शामिल हैं, भारत के विश्वविद्यालय में जाति एक महत्त्वपूर्ण विषय नहीं बन पाया और न ही इस पर कोई ठोस पहल करने की कोशिश की गई, इसलिए भारत के विश्वविद्यालय अध्ययन के क्षेत्र में कोई ख़ास पहुँच नहीं बना पाए, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में जगह नहीं बना पाया, भारत के शिक्षाविदो और सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य कर रहे संगठन के लिए यह मुद्दा सोचने समझने के लिए छोड़ा जा रहा है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत के विश्वविद्यालय में जाति एक जरुरी मुद्दा कब बनेगा और देश के शिक्षण संस्थानों को जाति भेद से मुक्ति कब मिलेगी? ▪

@+91 98919 03531

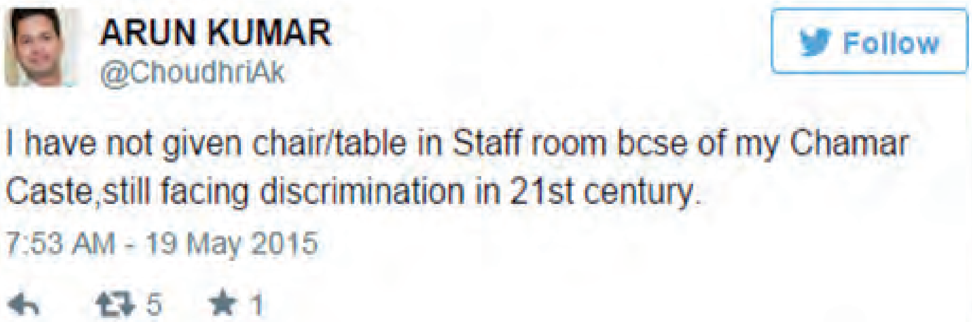

जातीय जनगणना रिपोर्ट

ग्राम–मुड़ाव, जिला–जौनपुर

देश में विभिन्न जातियों को लेकर फैलाये गये भ्रम को स्पष्ट करने के लिए बसावन इंडिया लगातार जातीय जनगणना के आकड़ों का प्रकाशन कर रही है। अब तक बसावन इंडिया उत्तर प्रदेश के पांच जिलों के पांच गांवों का रेंडमली चयन करते हुए जातीय जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन किया है। बसावन इंडिया द्वारा आजमगढ़ जिले की भरमा-डढ़िया ग्राम सभा, संत रविदास नगर के भक्तापुर ग्राम, अम्बेडकर नगर जिले की सेहरी लहिया ग्रामसभा, महाराजगंज जिले की महादेवा काशीराम और गाजीपुर जिले की खरगपुर ग्राम सभा की रिपोर्ट का प्रकाशन किया। बसावन इंडिया ने अपने इस अंक के जौनपुर जिले की मुड़ाव ग्राम का चयन किया है। जिसकी रिपोर्ट मुड़ाव ग्राम के रहने वाले अच्छेलाल ने तैयार की है।

जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए। बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा।

मुड़ाव ग्राम में कुल मतदाताओं की संख्या 1295 है। जिसमे लोनिया, अहीर, पासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और चमार सहित कुल 06 जातियां रहती हैं।

मुड़ाव ग्राम में सबसे अधिक आबादी पिछड़ों की है जिनमें सिर्फ दो जातियां लोनिया और अहीर शामिल हैं। पिछड़ी जाति के कुल मतदाताओं की संख्या 815 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का 62.93 फीसदी है। जिसमे सबसे अधिक संख्या लोनिया की है जिनकी कुल संख्या 591 है। इसके बाद अहीर हैं जिनकी संख्या 224 है।

मुड़ाव में अनुसूचित जातियों में, पासी और चमार मतदाता हैं जिनकी संख्या 246 है जिसमे पासी मतदाताओं की संख्या 189 है और चमार मतदाताओं की संख्या 57 है। मुड़ाव में अनुसूचित जातियां का कुल मतदाताओं की 18.99 फीसदी है, जो सवर्ण मतदाताओं के बराबर ही हैं।

मुड़ाव में सवर्ण मतदाताओं में ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता है जिनकी कुल संख्या 234 है। जो 18.06 फीसदी है। सवर्ण मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की 132 है। क्षत्रियों की संख्या 102 है। ▪

अच्छेलाल
मो. नं. : +91 8418815442

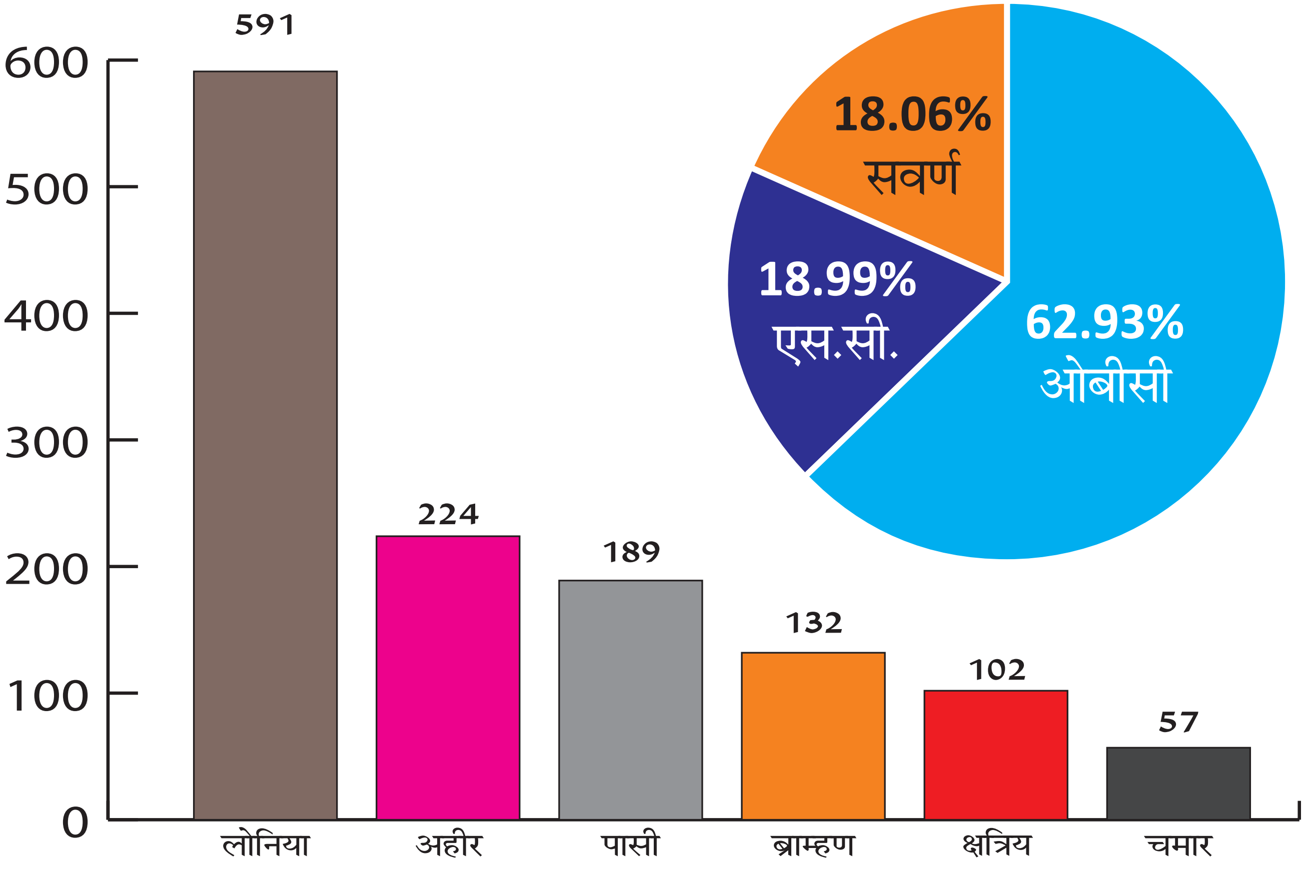

ग्राम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 के अनुसार ग्राम-मुड़ाव, जिला-जौनपुर

चौरी चौरा मामले में लाल मुहम्मद सैन और काजी, 22 सितंबर, 1922 को सेशन कोर्ट के बाहर

▪ राजेश प्रधान

जरा याद इन्हें भी कर लो...

चौरी चौरा के 100 साल और आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता आंदोलन के सभी इतिहासकारों ने चौरी चौरा की घटना का उल्लेख किया है, लेकिन प्रमाणिक तथ्यों, इतिहास के सभी दस्तावेजों और जनता के बीच इस घटना की स्मृतियों को आधार बनाकर सुभाष चंद्र कुशवाहा ने एक मुकम्मल इतिहास प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया है कि ये बगावत अंग्रेज़ों के खिलाफ तो थी है, साथ ही मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की ज़मींदार समर्थक नीतियों के भी खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने तथ्यों, देशी-विदेशी दस्तावेज़ों और लोक में चौरी चौरी की स्मृति को आधार बनाकर एक विश्वसनीय इतिहास लिखा। चौरी चौरा की घटना को देखने परंपरागत नज़रिए को चुनौती दी और पूरे घटनाक्रम को बहुजन परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया। तथ्यों के साथ इस बात को स्थापित किया गया कि चौरी चौरा विद्रोह मुख्यतः दलित, पिछड़े, और मुस्लिम गरीब किसानों की क्रांतिकारी बगावत थी। 4 फरवरी 1922 के दिन दलित बहुल डुमरी खुर्द गांव के गरीब और सामाजिक तौर पर अपमानित दलितों-बहुजनों और मुसलानों ने उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के गठजोड़ को खुलेआम चुनौती दी और कुछ समय के लिए ही सही चौरी चौरा के इलाके पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया।

चौरी चौरा की घटना की घटना को 4 फरवरी को 100 वर्ष पूरे हो रहे है। केंद्र सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना न केवल भारतीय इतिहास, बल्कि विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। आज से 100 वर्ष पहले 4 फरवरी 1922 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) के गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटी। आक्रोशित ग्रामीणों ने चौरी चौरा थाने को फूंक दिया आक्रोशित ग्रामीणों ने चौरी चौरा थाने को फूंक दिया जो ज़मींदारों और ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक था। इसमें अंग्रेज़ी सरकार के 23 सिपाही मारे गए गए। पर लोगों के नाम प्रकाश में नहीं आने दिया। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित असहयोग आंदोलन (1 फरवरी 1920 से 12 फरवरी 1922) इस हिंसा के बाद वापस ले लिया गया और आंदोलनकारियों को' गुंडा' और 'मवाली 'की संज्ञा से नवाजा गया। 'इतिहास की विडंबना ही कही जा सकती है कि सरकारी नियंत्रण में खुदे शिलालेख पर से डुमरी खुर्द गांव का नाम ही गायब कर दिया गया जहां के मुसलमानों, चमारों, अहीरों सहित तमाम निम्न कही जाने वाली जातियों की अगुवाई में चौरी चौरा विद्रोह ने दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया।

सेसन कोर्ट द्वारा 9 जनवरी 1923 को 172 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई 19 लोगों को फाइनली फांसी दी गई जो 2 जुलाई 1923 से आरंभ होकर 11 जुलाई तक चली।'19 लोगों को फांसी देने के साथ ही, 14 लोगों को आजीवन कारावास और 96 लोगों को अलग-अलग तरह की सज़ाएं दी गई थी। सबसे अधिक चौरा गांव के 5 लोगों को फांसी की सजा हुई। चौरी चौरा की बगावत के लिए जिन 19 लोगों को फांसी दी गई थी। उनमें अब्दुल्ला, भगवान अहीर, बिकरम अहीर, दुधई, कालीचरन कहार, लवटू कहार, रघुबीर सुनार, रामस्वरूप बरई, रूदली केवट, संपत चमार आदि को फांसी दी गई थी।' जातिवार देखें तो अहीर जाति के 4, कहार 3, मुसलमान 3 और केवट जाति के 2 लोगों को फांसी दी गई|इस विद्रोह में चौरी चौरा के 40 किलोमीटर के दायरे के 60 गांवों के गरीब किसान शामिल हुए थे। इनकी संख्या 2 से 3 हज़ार के बीच थी। आजीवन कारावास की दारुण सजा भोगे कैदियों में भगवान दास, विश्वनाथ सिंह, चि नगी, द्वारका गुसाईं, मनराज प्रधान, द्वारका पांडे, उग्रह, तीर्थराज के नाम प्रमुख है।

जब तक जन आकांक्षाएं अधूरी हैं,जन की समस्याओं का पूर्ण समाधान व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता चौरी चौरा विद्रोह की प्रासंगिकता बनी रहेगी और शहीदों की कुर्बानियों का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा।

जिन किसानों ने इस विद्रोह में भाग लिया और खासकर जिन लोगों ने इसका नेतृत्व किया वे लोग स्वयं को कांग्रेस का स्वयंसेवक मानते थे और गांधी जी के स्वराज का अर्थ ज़मींदारों और पुलिस के अन्याय और अत्याचारों से मुक्ति भी मानते थे। ग्रामीण आबादी के सबसे नजदीक ब्रिटिश सत्ता के केंद्र के रूप में थाना ही था, जहां वे अपना विद्रोह जता सकते थे। 4 फरवरी, 1922 को उन्होंने उस सत्ता को न केवल चुनौती

क्या है आजादी का अमृत महोत्सव

15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में प्रवेश कर रहे भारत का अपना एक सपना है, साथ ही उसे साकार करने का दृढ संकल्प भी। आजादी के अमृत महोत्सव के इस यादगार वर्ष में भारत अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर अगले 25 साल की रुपरेखा बना रहा है, ताकि स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह के समय भारत एक बार फिर विश्व गुरु की भूमिका में दिखे। लेकिन इसके लिए मजबूत नींव की जरूरत है, जिसे ध्येय बनाकर केंद्र सरकार ने ज्ञान-विज्ञान, तर्क और विश्वास को सहेजते हुए रखी है 'नए भारत' की नींव आजादी का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता का 75 वां वर्ष, यह पीछे मुड़कर देखने और अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण करते हुए उसे संजोने का अवसर भी है।

इसके लिए महान क्रांतिकारियों और जन साधारण ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। यह संविधान सभा के उन सम्मानित सदस्यों को भी याद करने का वर्ष है जिन्होंने हमें अपने संविधान के द्वारा एक ऐसा मूलभूत अधिकार और शक्ति प्रदान की, जिस पर हर भारतवासी गर्वकर सकता है। यह आत्मनिरीक्षण का भी वर्ष है। साथ ही, एक बार फिर यह समझने का वर्ष है कि स्वाधीनता का अर्थ क्या है। हमारे लिए इसके मायने क्या हैं। पिछले सात दशकों में यह देश कितना आगे बढ़ा है और आने वाले वर्षों में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें क्या करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है 'आईडिया ऑफ इंडिया' यानी 'भारत की अवधारणा' जो कई दशकों तक सिर्फ अकादमिक बहस का हिस्सा बनकर रह गई थी।

लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति ही नहीं, कामकाज का तरीका और सोच में भी अभूतपूर्व बदलाव दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ही, "मेरी भारत की अवधारणा' न केवल सहिष्णुता पर आधारित है बल्कि यह विचारों की विविधता का प्रसन्नतापूर्वक समावेश करती है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की संवेदना का सम्मान किया जाता है। भारत की अवधारणा' के केन्द्रीय सिद्धांत का सृजन सत्य, शांति और अहिंसा से होता है। हमारे शास्त्र 'सत्यमेव जयते' की शिक्षा देते हैं, जिसका अर्थ है कि विजय सत्य की ही होती है। मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रतिबद्ध हूं जहां न्याय का चक्र वर्ग, जाति या पंथ से प्रभावित हुए बिना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए तेजी से और सामान रूप से घूमता हो। एक ऐसा भारत जहाँ अन्याय के लिए किसी भी तरह की कानूनी और नैतिक वैधता न हो।

इतिहासकारों ने कभी इस सामाजशास्त्र पर विचार नहीं किया कि फटेहाल गरीब किसान, जिनमें से अधिकांश बेहद भूखे और मजबूर थे, वे किस प्रकार की गुंडई करने चौरा थाना गए थे। आखिर गुंडई करने का उद्देश्य क्या था? क्या वे अपने निजी स्वार्थ के लिए गुंडई कर रहे थे या जुल्मी शासकों को सबक सिखाने के लिए हिंसक हो गए थे? दारोगा को मारना, पीटना या थाना जलाना ही उनका उद्देश्य था तो उनका जुलूस चौरा थाने के द्वार से आगे, चौरा बाजार की ओर क्यों निकल गया था? उन्हें तो थाने पर पहुंचते ही थाने को घेर लेना चाहिए था या उस रणनीति पर कार्य करना चाहिए था, जिससे उनका मकसद, बिना गोली खाए आसानी से पूरा हो जाता? अगर उनकी योजना पूर्वनियोजित थी तो पहला आक्रमण उन्हीं की ओर से होना चाहिए था या आक्रमण की तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी न कि थाने पर पहुंच कर मिट्टी का तेल, लाठी, लबदा', चैला','कोरो' या खर' का इंतजाम करना चाहिए था। ऐसे सवालों का उत्तर इतिहासकारों के वर्गाधार पर निर्भर करेगा।

(सुभाष चंद्र कुशवाहा की पुस्तक चौरी चौरा विद्रोह और स्वतंत्रता आंदोलन से)

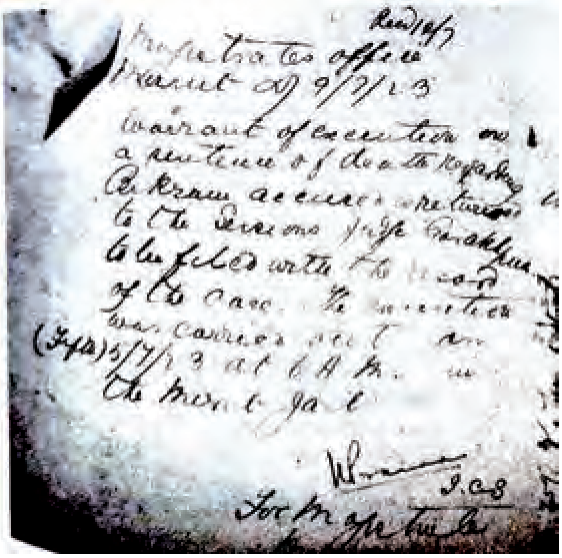
Magistrate's office
Meerut 9/7/23
Warrant of execution on a sentence of death regarding Vikram accused returned to the Sessions Judge Gorakhpur to be filed with the record of the case. The execution was carried out at 6 A.M. [illegible] the Meerut Jail
(Sd.) 9/7/23
For Magistrate

विक्रम अहीर को फाँसी दिए जाने के संबंध में मेरठ के मजिस्ट्रेट द्वारा पत्र लिखा गया। पर इतिहास के पन्नों में विक्रम अहीर का नाम दर्ज नहीं है।

दी, बल्कि विद्रोह की रात, चौरी चौरा रेलवे स्टेशन और डाकघर पर तिरंगा फहरा कर, अपने संघर्ष का मकसद समाज के सामने रखा

चौरी चौरा या ऐसे अनेक विद्रोह जिसमें जन ने जिन पीड़ाओं से छटपटा कर, जान की बाजी लगा मुक्त होने का प्रयास किया, क्रांति की उनकी हलचलों का कथित चेतना युक्त महानुभावों ने अपने अनुकूल, स्वयं या वर्गों के हित साधन में भी कम प्रयोग नहीं किया। मोटा मोटी मेरी यही समझ बनती है कि चौरी चौरा विद्रोह, स्वाधीनता आंदोलन या अन्य क्रांतियों को जान, सुन, समझ या पढ़कर।

चौरी चौरा की घटना पर फांसी दे देना, आजीवन कारावास दे देना या गोली चला देना युक्तियुक्त न्याय नहीं माना जा सकता। शोषित जनों ने व्यवस्था के जिस अन्याय से पीड़ित होकर यह कदम उठाया जब तक उसका न्याय नहीं हो जाता तब तक फासीवादी न्याय अधूरा ही रहेगा और चौरी चौरा की घटना हमें अनवरत उस अधूरे न्याय की याद दिलाती रहेगी। अब तो देखना यह है कि यह सनातन जालिम परंपरा कभी खत्म भी होती है की अनंत काल तक अनंत जिंदगियों को बेवजह और बेकसूर निगलती रहती है। ▪

@+91 9696949828

मनखे - मनखे एक बरोबर गुरु घासीदास जयंती

▪ सिओक

छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती या मेला 18 दिसंबर से लेकर एक-दो माह तक मनाते हैं। जयंती का मुख्य उद्देश्य गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन को समाज के बीच प्रचार -प्रसार का होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन मेल सके।

18 वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में जन्म लिए गुरु घासीदास शोषितों, दबे कुचले, सताये हुए समाज का नेता बनकर सामने आए। उस दौर में घोर जातिवाद, छुआछूत, असमानता, अन्याय और अत्याचार अपने चरम पर था। समाज के ऊपर हो रहे ऐसे अत्याचार की घटनाओं को देखकर उन्होंने समाज में अधिकार के प्रति चेतना जगाने का काम किया। लोगों को सम्मान से जीने के लिए उनमें आत्म सम्मान, स्वाभिमान पैदा किया। उनको नवजागरण काल के प्रथम व्यक्ति माना जा सकता है।

उन्होंने गांव-गांव जाकर सभाएं, रैलियां और पदयात्रा के द्वारा लोगों को जागरूक कर संगठित करने का काम किए। लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। उस समय की जातिवाद, छुआछूत को देखकर उन्होंने मानव-मानव एक समान (मनखे- मनखे एक बरोबर) का संदेश दिया इस नारा के माध्यम से उन्होंने ऊंच-नीच, जात- पात, छुआछूत का कड़ा विरोध किया। गुरु घासीदास जी के कार्यों से प्रभावित होकर लोग उनसे जुड़ने लगे।

अब उनके पास बहुत बड़ी लोगों का जत्था हो गया तब उन्होंने सतनाम आंदोलन चलाया। इस आंदोलन से जुड़े लोगों को अब सतनामी समुदाय के नाम से जानते हैं। इसी समुदाय के द्वारा गुरु घासीदास जयंती मनाई जाती हैं ताकि गुरु घासीदास बाबा जी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन को समाज तक पहुंचाया जा सके।

मुख्य अतिथि और चंदा बनी चिंता का सबब

आयोजकों द्वारा इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खर्चों को वहन करने के लिए सवर्णो को मुख्य अतिथि बनाकर उनको नेता बना रहे हैं, इन सवर्ण नेताओं को स्वागत के साथ फूल माला पहनाने के लिए होड मचा रहता है। अगर किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए नाम नहीं पुकारा जाता है तो वह नाराज हो जाता है। इन नेताओ साथ युवा के साथ बुजुर्ग भी फोटो खीचने के लिए धक्का-मुक्की करते हैं। आयोजक अपनी राजनीतिक पहचान बनाने या चेहरा चमकाने के लिए सामाजिक भीड़ का इस्तेमाल करता है। सवर्ण व्यक्ति यही भीड़ के वोट से नेता बन कर इन्हीं के अधिकारों पर डाका डाल देता है, इसका परिणाम यह हुआ की समाज में आज नेता या प्रतिनिधित्व करने वालों का अभाव नजर आ रहा है। जयंती अब समाजिक कम और राजनीतिक ज्यादा नजर आ रहा है। इन सवर्णों को मुख्य अतिथि बनाने से तत्काल रोका जाना चाहिए।

21वीं सदी में जयंती का उद्देश्य बदल सी गई है। पहले भी समाज के लोगों के द्वारा कम संसाधन में भी अपनी आपसी सहयोग से जयंती मनाते थे, लेकिन अब रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के चक्कर में गुरु घासीदास जयंती सामाजिक न होकर राजनीतिक ज्यादा नजर आने लगा है। लगभग 2 माह तक चलाने वाले कार्यक्रमों में आजकल सवर्णों को मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, वीआईपी के रूप में बुलाने का प्रचालन बढ़ रहा है। और कई बार जयंती में मुख्य अतिथि नहीं मिलते तो जयंती कार्यक्रम को आगे बढ़ा देते हैं। हर जगह लोग बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आते हैं। सवर्ण नेता मानवता का संदेश देकर भीड़ का हितैषी नेता बनकर चला जाता है। लोग अपना नेता भी मान लेते हैं और उनको चुनाव में जिता भी देते हैं। लेकिन इन्हीं सतनामी समुदाय के ऊपर जाति भेदभाव, अत्याचार, छुआछूत, निर्मम हत्या, बहन बेटियों के साथ रेप छेड़खानी, आस्था के प्रतीक जैतखाम को क्षति पहुंचाया जाता है,इनकी जमीन षड्यंत्र पूर्वक छीनी जाती है। विकास के नाम पर इनको घर से बेघर कर दिया जाता है। आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एससी एसटी एक्ट के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तब यह सवर्ण नेता इनकी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने सड़क पर नहीं आते, तब हितैषी नेता नहीं बनते बल्कि यही सवर्ण नेता आरोपी के पक्ष में खड़े मिलते हैं। हाल ही में कबीर धाम जिले के धर्मपुरा गांव में गुरु घासीदास के नाम पर बन रहे गुरुद्वारा को ढहा दिया गया। जैतखाम को जलाया गया, तब कोई नेता दिखाई नहीं दिए। मुंगेली जिला के ग्राम झझपुरी में जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा आस्था के प्रतीक जैत स्तंभ को काटकर मिट्टी तेल डालकर जलाया गया। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उस पर पेशाब किया। तब यह सवर्ण जाति के नेता कहीं नजर नहीं आए।

जयंती में मुख्य अतिथि बनकर आए सवर्ण नेता राजनीति को अपने समाज के लिए उपयोग करता है। ठीक इसके विपरीत आयोजक समाज को अपने निजी स्वार्थ पूर्ण राजनीतिक के लिए इस्तेमाल करता है। सवर्ण नेता वैचारिक और उच्च जाति होने के पराकाष्ठा से बाहर नहीं आते। जयंती के आयोजकों और सतनामी समुदाय के लोगों को विचार करना चाहिए की। उनका हितैषी नेता कौन है। सामाजिक मंच समाज के युवाओं की कला निखारने के लिए होना चाहिए जो आगे चलकर वक्ता नेता या कलाकार आदि बनकर उभरे और समाज को गौरवान्वित करें। समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। इसका परिणाम यह होगा कि आज जो सवर्ण नेता को मुख्य अतिथि बना रहे हैं, वह बंद हो जाएगा। समाज को अपना हितैषी प्रतिनिधित्व करता मिल जाएगा जो हर परिस्थिति में समाज के साथ खड़े रहे। ▪

(लेखक के विचार अपने निजी हैं।)

@+91 7898905503

ऐसा चाहूँ राज मैं

▪ अमरजीत चक्रवर्ती

बेगमपुरा की कल्पना करने वाले रविदास भारत के बड़े चिंतको और दार्शनिको में होते अगर उनका साहित्य, बोल, भाषण, लेखन हमारे बीच होता। आज उनकी कुछ लाइन, चलती फिरती हमारे बीच सामने आ जाती है लेकिन उनकी बातें दबा दी गयी, खत्म कर दी गयी, और भारत को बेगमपुरा बनाने का सपने को साकार रूप देने के लिए कई सौ साल बाद डॉ. आंबेडकर द्वारा निर्मित भारत का खाका सामने आया। बेगमपुरा अर्थात ऐसा देश/ समाज जो बिना गम के हो। रविदास की ये लाइन आज भी लोगों के जेहन में है कि जात–जात में जाती है,ज्यो केलन को पात, रविदास मानुष नहीं जुड़ सके, जब तक जाती न जात... एक अर्थ में रविदास की यह कल्पना अदितीय है, जो अंबेडकर के उस भाषण कि याद दिलाता है जो हो न सका लेकिन बाद में खूब पढ़ा जा रहा है, यानि ''जाति का उच्छेद''। जब तक जाति का विनाश नहीं होगा, रैदास का भारत, बेगमपुरा नहीं बन सकता। जब तक जाति नहीं जाएगी, तब तक ''भारत के लोग'' लोग नहीं बन पाएंगे और सच्चे अर्थों वाला लोकतन्त्र तो बहुत दूर कि बात है। यदि बेगमपुरा का अर्थ महिलाओं के सन्दर्भ में लिया जाय तो उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी। उनके बेगमपुरा का मतलब, बेगमों से था या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बादशाहो कि हुकूमत तो उन्होने देखी थी, और इस अर्थ में महिलाओ के राज/भागीदारी के बारे में रविदास क्या सोचते थे ये कहना मुश्किल है, क्योकि उनका सारा चिंतन हमारे सामने नहीं आ पाया है। बेगमपुरा की संकल्पना की झलक उनकी चौपाई ' ऐसा चाहूँ राज मै, जहाँ मिले सबन को अन्न,छोट बड़ा सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न' में मिलती है। समाजवादी, समतावादी जैसे आधुनिक विचारों को कहने के लिए यूरोप अमेरिका का माना जा सकता है, पर रविदास के चिंतन में बिना कोई स्पष्टीकरण दिए देखा जा सकता है। बेगमपुरा में ऊँच नीच, जातीय भेद, हिंसा, जातीय श्रेष्टता का को जगह नहीं होती।

रविदास बनारस के रहने वाले थे लेकिन आज वाराणसी से रविदास गायब हो चुके हैं। रविदास के साहित्य को गायब कर दिया गया। जिस तरीके से बुद्ध साहित्य को गायब किया गया। आज जब कि हम प्रिंटिंग दौर में है अम्बेडकर के साहित्य को उत्तर भारत कि हिन्दी पट्टी से कैसे गायब किया गया। प्रसिद्ध सामाजिक चिंतक अर्जक रामस्वरूप वर्मा ने आंबेडकर साहित्य कि जब्ती और बहाली शीर्षक लेख में लिखा है कि ''ब्राह्मणवादियों कि सदैव यह कोशिश रही कि बाबा साहब का साहित्य जन- जन तक न पाहुच पाये।'' उत्तरभरत कि हिन्दी पट्टी में अंबेडकर का साहित्य आज भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस नजरिए देखेंगे तो आपको रविदास जैसे विचारक के विचार गायब हो जाने पर आश्चर्य नहीं होगा। फुटकर रूप से जहाँ तहां उनके विचार मिल जाते है। सिक्खों के धार्मिक ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहब में संत रविदास की वाणी मिलती है, जो उसी प्रकार है जैसे स्वतन्त्रता, समानता कि बात फ्रांस कि क्रांति से भले ही निकले, लेकिन आज भारत सहित दुनिया भर के लोगों में ये विचार संचारित हो रहे हैं। उसी तरह रविदास के बेगमपुरा के विचार हिन्दी पट्टी से भले ही गायब हो गए, बुद्ध के विचारों कि तरह पर, गुरुवानी में उनके विचार पाँच नदियो वाले प्रदेश के सरदारों के बीच संचारित हो रहे हैं। सिख समाज वर्ण/ जाति की परंपरागत बीमारियों से थोड़ा मुक्त हुआ, जिसका नतीजा है की कोई सिख भीख मांगते नहीं दिखता, और आज चल रहे किसान आन्दोलन को इतने व्यवस्थित ढंग के आन्दोलन के मूल में संत रविदास की वाणी संचारित हो रही है।

जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक कटु सत्य है। रविदास चमार जाति से आते थे उन्होंने खुल कर कहा कि मै चमार हूँ (कह रविदास ख़लास चमारा) लेकिन इसे लेकर कोई हीन भावना मन में नहीं थी। आज का ग्रेट चमार या कि पेरियार का आत्मसम्मान का उद्घोष का संचार रविदास से ही चला आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चमारों की बसावट को आज भी चमरौटी या हरिजन बस्ती कहा जाता है, जो बेगमपुरा से बहुत दूर है, जिसमे कभी आग भी लगा दी जाति है तो कभी चित्कारें निकलती है पर आवाज कमजोर होती है। रविदास का खुद को चमार कहने के पीछे कोई हीन विचार नहीं था। वो समता के पुरज़ोर लड़ाकू थे। उन्हे मिटाने की लाखों कोशिश के बाद भी रविदास आवाज दुनिया को बेगमपुरा बनाएगी एक दिन...ऐसा राज चाहने के लिए आपको, हमको पूरी दुनिया को आगे आना होगा। ▪

@+91 9415088452

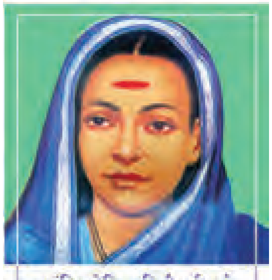

क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले

भारत के प्रथम महिला शिक्षिकाओं के जन्मदिवस की धूम

भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और उनकी सहयोग फातिमा शेख का जन्मदिन क्रमशः 3 जनवरी और 9 जनवरी को मनाया गया।

भारत का पहला कन्या स्कूल खोलने में फ़ातिमा शेख़ ने सावित्रीबाई फुले की मदद की थी। फ़ातिमा शेख प्रथम मुस्लिम शिक्षिका थी। उस ज़माने में अध्यापक मिलने मुश्किल थे। फ़ातिमा शेख़ ने सावित्रीबाई के स्कूल में पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी संभाली। इसके लिए उन्हें समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा।

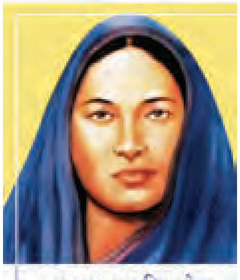

राष्ट्रमाता फातिमा शेख

समृद्ध भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स बहुजनों का चैंबर बनाने की जद्दोजहद

▪ **परिभाषा**

समृद्ध भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसबीसीसीआई)मे देश के उद्योगपति इंजीनियर, नौकरशाह से लेकर राजनीतिक सामाजिक चिंतक शामिल हैं। एसबीसीसीआई द्वारा व्याख्यानों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षणों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, जागरूकता शिविरों का आयोजन होता है जिसमे चैंबर नौकरशाहों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों, सफल पेशेवरों और व्यवसायियों से जुड़ने के लिए मंच प्रदान करता है। बसवान इंडिया की संवाददाता परिभाषा ने (एसबीसीसीआई) के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की की है-

नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में समृद्ध भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 'एम.एस.एम.ई. सेक्टर और वित्तीय समावेशन' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र की कई प्रबुद्ध एवं गणमान्य हस्तियों ने भाग लेकर विषय पर अपने अनुभव साझा किए और भविष्य की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम में जहाँ एक तरफ एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों के लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में लगातार हो रही अवसरों की कमी, नौकरी न मिलने की समस्या और उससे निबटने के तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि, "राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इशारों पर नाचने वाली केंद्र की भाजपा सरकार एक सुनियोजित तरीके से पिछड़ों और वंचितों के लिए उपलब्ध अवसरों को ख़त्म करने का षड्यंत्र रच रही है। इसलिए आर्थिक असमानता और सामजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पिछड़ों और दलितों को अपनी लड़ाई ख़ुद लड़नी होगी।

क्या है एसबीसीसीआई?-

फिक्की, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई, एसोचैमआदि जैसे अधिकांश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समाज के सभी वर्गों में वाणिज्य, व्यापार और उद्योग समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन व्यवहार में वे ज्यादातर व्यापार और सेवा के नाम पर जाति/ वर्ग और समूह के हित का प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं। उनका स्वामित्व, नेतृत्व और प्रबंधन देश के व्यापारिक जाति के लोग करते हैं। उन्होंने केवल अपनी जाति/ वर्ग के हितों के लिए काम किया है और काम करते रहे हैं। अन्यथा, इस बात का कोई विशेष कारण प्रतीत नहीं होता है कि देश की 60% से अधिक आबादी को रोजगार देने वाली जातियों (कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र) का पेशा घाटे में चलने वाला पेशा क्यों बन गया है? जबकि कृषि वस्तुओं (माल) का व्यापार और वाणिज्य हमेशा एक लाभदायक उद्यम रहा है। व्यापार कम कीमतों पर खरीदने और उच्च कीमतों पर बेचने पर पनपता है जो इन स्थापित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने नीतिगत समर्थन के माध्यम से किया है।

संगठन की आवश्यकता क्यों?-

जब महात्मा फुले से 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की आवश्यकता के बारे में पूछा गया कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि जैसे कई सामाजिक सुधार संगठन पहले से ही काम कर रहे थे तो आपने इसे क्यों बनाया? इसके उत्तर में महात्मा फुले ने कहा था कि वे संगठन शूद्र समाज द्वारा नहीं बल्कि उच्च जाति के ब्राह्मणों द्वारा गठित, नेतृत्व और प्रबंधित किए जाते हैं और शूद्र/ बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा बहुसंख्यक/ शूद्र समाज के नेताओं द्वारा ही बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। शायद ही कोई फोरम/ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो उत्पादक वर्ग/ जातियों और मजदूर वर्ग/ जातियों के विशाल बहुमत के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो। बहुसंख्यक समाज (एससी, एसटी, एसईबीसी) के स्वामित्व, नेतृत्व और प्रबंधन के लिए वाणिज्य और उद्योग का कोई मंच नहीं है। एसबीसीसीआई का गठन बहुसंख्यक समाज के इस विशाल बहुमत की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें देश की समृद्धि में भागीदार बनाने के लिए किया गया है। जब देश का बहुसंख्यक समाज समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध और उन्नत बनेगा।

आर्थिक न्याय के लिए काम करने का क्या अर्थ है?

देश के संविधान में निहित सभी के लिए उचित और न्यायपूर्ण आर्थिक अवसर की बात की गई है। वर्तमान में निवेश पर अधिक लाभ देने वाले आर्थिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक उच्च जातियों का भारी नियंत्रण है जो आबादी का लगभग 10% है लेकिन 90% का आर्थिक संपत्ति पर अनुपातहीन नियंत्रण है। आर्थिक गतिविधियों का परिणाम समाज के सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिला है। इसलिए आर्थिक न्याय के लिए सकारात्मक प्रयास और अन्य तरीकों से काम करने और सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

क्या हैं कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रमें ऋृणात्मक लाभ देने का कारण हैं?

कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के घाटे में चल रहे पेशे/ व्यवसाय बनने का मुख्य कारण वाणिज्य और उद्योग के किसी भी चैम्बर की अनुपस्थिति है जो उत्पादक वर्ग और उस पर निर्भर श्रमिकों के हितों की देखरेख करेगा। उत्पादन लागत के साथ-साथ मुद्रास्फीति के साथ संबंध के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य के परिणामस्वरूप कृषि वस्तुओं का, चाहे वह चावल, गेहूं, दूध या जो कुछ भी दशकों से जारी है, का बाजार मूल्य लागत मूल्य से भी कम हो गया है। जब एक उपभोक्ता के रूप में हम चावल खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, तो चावल की गुणवत्ता, किस्म और चावल के अन्य गुणों के आधार पर चावल की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है। लेकिन, जब सरकार

कैसे काम करेगा?

एसबीसीसीआई की योजना मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और सिख सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए काम करने की है। ये वे समुदाय हैं जो परंपरागत रूप से कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में लगे हुए हैं। एसबीसीसीआई पारंपरिक व्यवसायों में बहुसंख्यक समाज के ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता का लाभ उठाने तथा आधुनिक ज्ञान एवं आईटी आधारित समाधानों के उपयोग के साथ इन क्षेत्रों के उत्पाद का उपयोग करके व्यापार और वाणिज्य में उस सामाजिक पूंजी का उपयोग करने की कल्पना करता है।

द्वारा किसानों से चांवल खरीदा जाता है, तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाता है। इस नीति के परिणामस्वरूप उपज और किस्म की गुणवत्ता और उसके लिए किसानों को अतिरिक्त बिक्री मूल्य पर कोई विचार नहीं किया गया। साथ ही, गुणवत्ता की परवाह किए बिना समान खरीद मूल्य (same purchase price) से सरकारी खरीद के तहत खरीदी गई उपज की स्वच्छता, शुद्धता आदि के मामले में गुणवत्ता कम हो जाती है। चावल की प्रीमियम किस्म के निर्यातकों के साथ-साथ विक्रेता भी अच्छा मुनाफा कमाते हैं लेकिन उत्पादक किसानों को ज्यादातर कीमत या तो एमएसपी पर मिलती है या निजी व्यापारी/ मिलर द्वारा दी जाती है। केवल एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के स्थान पर गुणवत्ता समर्थन मूल्य (क्यूएसपी), प्रीमियम समर्थन मूल्य (पीएसपी), जैविक समर्थन मूल्य (ओएसपी) आदि भी होने चाहिए थे तथा सभी समर्थन मूल्य अनिवार्य रूप से लागत मूल्य के साथ-साथ मुद्रास्फीति से जुड़े होने चाहिए।

व्यवसायों, वाणिज्य, उद्यमियों आदि के लाभ के लिए मौजूदा योजनाओं में इस अर्थ में संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है कि सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें उप-विभाजित श्रेणीवार किया जाना चाहिए। योजनाओं के तहत लाभार्थी की संख्या संबंधित श्रेणियों की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया योजना (जैसे काल्पनिक/ नाममात्र खंड) की कम से कम एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्य का चयन किया जाना चाहिए, की निंदा करने और सीधे खारिज करने की आवश्यकता है और उसके स्थान पर भारत सरकार की सभी योजनाओं में समानुपातिक हिस्सा डालने की आवश्यकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में बहुसंख्याक पीढ़ी 'एक्स' और पीढ़ी 'जेड' को शिक्षा, सरकारी एजेंसियों और उनके सामान को व्यवसाय, व्यापार, निर्माण, वाणिज्य, सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने हेतु कार्यशालाओं, सेमिनारों, संगोष्ठियों, जागरूकता शिविरों आदि के माध्यम से मार्गदर्शन, समर्थन, प्रशिक्षित और जागरूक बनाने की आवश्यकता है। स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं में कृषि-व्यवसाय को उद्यमों के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है ताकि देश की पीढ़ी' एक्स' और पीढ़ी 'जेड' बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आवश्यक ऋृण प्राप्त कर सकें और नौकरी के बजाय नौकरी देने वाले बन सकें। देश की पीढ़ी 'X' और पीढ़ी जेड द्वारा ज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारंपरिक कौशल सेट का उपयोग कृषि से अधिशेष जनशक्ति को स्थानांतरित करने के अलावा उन्हें अच्छी कमाई और लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद करेगा। ▪

@+91 88260 63330

रिटायर्ड/पेंशनर पुरुषों को ठगते वैवाहिक विज्ञापन

▪ देशराज (एडवोकेट)

विगत कुछ दशकों में बढ़ती चिकित्सा सुविधाओं पोषण में सुधार आदि के देश ही नहीं पूरी दुनिया में आयु प्रत्याशा बढ़ी है। इस कारण एक बड़ी आवादी ऐसे लोगों कि उभरकर सामने आई है, जो 60 वर्ष से अधिक के हैं और जो सेना रेलवे, या राज्य सरकार से रिटायर होकर सम्मानजनक पेंशन ले रहे हैं। भारत में अनुमानतः 5 करोड़ लोग पेंशनधारी है जो लगभग 15000 से लेकर 1 लाख के आसपास तक पेंशन पाते हैं।

प्रत्येक रविवार के वैवाहिक विज्ञापनों में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन कुछ महिनों से विशेष रुप से दिखाई दे रहा है। वर चाहिए के कालम में 50 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी महिलाओं के विज्ञापन जो अपनी आय/ पेंशन/ नौकरी से अकेले/ रिटायर्ड/ पेंशनर धनवान पुरुषों को प्रायः आकर्षित करने में सक्षम है। ये विज्ञापन उत्सुकता पैदा करने के साथ ही हैरान करने वाले भी लगते हैं, क्योंकि भारतीय समाज की परिस्थितियों को देखते हुए एकल/ विधवा/ परित्यक्ता महिलाएं 50/55 या 60/65 वर्ष की उम्र में विवाह का विज्ञापन देना कुछ पचता नहीं है। शायद हीअपने आसपास हम किसी इस वय की महिला को विवाह के लिए खुले/घोषित तौर पर तैयार देखें। अधिकांश उत्तर भारतीय महिलाएं यदि 40 वर्ष की उम्र तक अविवाहित हैं तो प्रायः विवाह न करने का निर्णय ले लेती

31/5'1" MSC ALIED PCS हेतु वर चाहिए अविवाहित, तलाकशुदा, बि सन्तान, Govt. Job वाले को प्राथमिकता

9794421376, 9450021602

48-/ गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर /5"4"/M.COM,PGDCA / वेतन-80,000/-हेतु वर चाहिए, तलाकशुदा, विधुर बच्चे वाले 8115688967, 8736014878

जाति बंधन नहीं/ 50/"5'4"/ सरकारी टीचर 85,000 सुंदर महिला हेतु वर चाहिए अन्तर्जातीय, तलाक शुदा, विधुर सभी मानवीय। 8808179881

38-"M.A./ B.Ed गवर्नमेंट टीचर आय 65,000/- हेतु वर चाहिए।

ठगो द्वारा भेजी गई फोटा और पूरा विवरण

Naam-- Sangeeta Singh
Age-- 68
Height-- 5.5
Education-MA, BED
Occupation -- Govt Teacher
Salery. 45,000
City-. Deoria
Cast-- Rajput
Married Status -- Widow

है। अब सवाल ये है कि कौन है ये महिलाएं जो 59/60, 62/65 की उम्र में सरकारी नौकरियों में या तो कार्यरत है या सरकारी स्तरीय नौकरियों जैसे- सरकारी प्रवक्ता/एसबीआई बैंक मैनेजर/ जीएसटी ऑफिसर/ गवर्नेंस पीएनबी बैंक से रिटायर इत्यादि जैसी नौकरियों से रिटायर्ड है, जिनकी पेंशन या आयप्रायः50000 सेअधिकहै। ये विज्ञापन लगभग सभी प्रमुख हिंदी दैनिक समाचारपत्रों में आसानी से देखे जा सकते हैं। इन विज्ञापनों के साथ दिए गए नंबरों पर बात करने पर वे आपको किसी भी महिला का नंबर देने

82-वर्ष/5"4"/SBI बैंक मैनेजर /M.COM/सैलरी-75,000/ हेतु वर चाहिए। अन्तर्जातीय, किशोरी, विधुर, बच्चे वाले, परवाह नहीं 8269210091, 7898990754

महानगरीय

SM 4 Beautiful Girl 27/5'4" working in Uppcl as a SDO/ required well educated, well settled class-I officer in Govt. Cast no bar.

ठगो द्वारा भेजी गई फोटा और पूरा विवरण

Name _ deepa parshad
Age= 50
Education= graduate
Job= shopkeeper business
State = uttar pradesh
City= aligarh, jamalpur

से पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दो हजार से पांच हजार रुपए की धनराशि किसी खाते मेंजमा कराने हेतु कहते हैं, जो आप के राज्य के बाहर का होगा। यदि आप चतुर हैं तो कुछ छोटे-मोटे तर्क जैसे शादी करनी है तभी तो बात कर रहे हैं, पैसा तो दूसरे पक्ष ने जमा ही करवाया है। आदि के आधार पर इस प्रारंभिक स्तर पर जमा की जाने वाली धन राशि में कटौती करा सकते हैं। किसी महिला से आपकी बात भी कराई जाएगी

Ch. Balakrishna
Psychologist & Skill Development Trainer

वही मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ठगी में शामिल बेरोजगारों ने मनोवैज्ञानिक रूप से अकेले रहने वाले पुरुषों जिनके पास एक निश्चित आमदनी है और परिवार के साथ अधिक संवाद नहीं है, स्त्रियों के प्रति उसकी कमजोरी को देखते हुए की जाती है, को टारगेट किया है क्योंकि ऐसे लोग प्रायः इस प्रकार की ठगी को कहीं किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करते हैं और न ही वह उम्र के इस पड़ाव पर पुलिस कंप्लेंट व पुलिस के सवाल जवाब के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार। ठगी का यह स्वरूप अपेक्षाकृत सुरक्षित देखा गया है।

जो बात करते ही आपके करीब आने और आपकी शरीकेहयात (हमराही/पत्नी) बनने को व्याकुल दिखाते हुए आप से सवाल भी करती है 'मेरे पति बनोगे?' और हां यह फोन रिसीव करने पर किसी कॉल सेंटर की भांति शोर की आवाजें आने लगती हैं, मानों कितने ही लोग आसपास फोन पर शादियों के लिए पूछताछ कर रहे हैं। फिर शुरू होता है फोन करने वालों की डिटेल प्राप्त करने की कोशिश, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि/ उसकी आय/ पुरानी नौकरी का ब्यौरा आदि आदि। एक महिला अपनी सुविधानुसार आप से वार्ता करेंगी किंतु आपके द्वारा फोन किए जाने पर फोन नहीं उठाया जाता है क्योंकि व्यक्ति को महिला के स्तर से बात करने का एक निर्धारित समय होता है। कुछ भावी सपनों की 8/10 वार्ताओं के बाद, महिला के रिश्तेदार को कोई गंभीर बीमारी होगी। जिसके लिए एटीएम ना होने के कारण आपसे थोड़ा-थोड़ा करके बड़ी धनराशि मांगते हैं और चूंकि बीमारी/ ऑपरेशन/ एक्सीडेंट और फिर अधिक पैसों के लिए उस महिला का ही एक्सीडेंट और साथ ही कुछ लोगों की मृत्यु। टारगेट भावुक और शाक्ड। पैसे देते समय कोई प्रश्न ही नहीं कौंधता, प्रायः चूँकि महिला पहले ही स्वयं को पेंशन धारक बता चुकी है। उसे पैसे की कोई कमी नहीं है और जैसे ही वह ठीक होकर वापस जाएगी, पैसे वापस देने की बात बार-बार करती है फिर जब यह लगने लगता है कि अब टारगेट पैसे नहीं दे सकता या नहीं दे पाएगा। महिला की इस कहानी में मृत्यु हो जाती है और फोन हॉस्पिटल के पास होता है। शिकार व्यक्ति ठगा जा चुका होता है कि वास्तविकता को जान समझ ही नहीं पाता और जान भी ले तो उम्र कि थकान, समाज का भय उसे कुछ करने नहीं देते. इस प्रकार कि ठगी के लिए समाजशास्त्री कई कारण बताते हैं। बढ़ती बेरोजगारी, कम समय में कम मेहनत में अधिक कमाने की चाह, जिसमें शामिल महिलाएं प्रायः परिवारों के पुरुषों के साथ व सहमति से ही इस कार्य को रोजगार की भांति कर रही हैं।

ठगी गिरोहों द्वारा दिए जाने वाले खाते प्रायः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात व मध्यप्रदेश के विभिन्न जनपदों से संबंधित हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों बुजुर्गों को ना केवल सतर्क रहने कि जरुरत है बल्कि परिवार मित्रो और रिश्तेदारों को भी सचेत रहने कि जरुरत है। ▪

@ +91 9454411702

पेज नं-17 का शेष लालू को जेल पर जेल...

अमित खरे
रिटायर्ड आईएएस अधिकारी

वह भी तब जब इस बारे में उन्हें दुबारा स्मरण पत्र भेजा गया। इस प्रकार बीस दिनों तक वह क्यों और किसके इशारे पर रुके रहे यह अनुत्तरित है।

खैर, अमित खरे को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। वह दो साल पहले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। परंतु उन्हें दो सालों का सेवा विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने अपना विशेष सलाहकार बनाया।

बहरहाल, लालू प्रसाद दोषी हैं अथवा निर्दोष, इसके बारे में फैसला अदालतें करें। लेकिन यदि

अरविन्द सरोज
युवा नेता

लालू यादव ने बिहार में दलितों पिछड़ों को पहचान दिलाई। बिहार को सामंती जकड़न को शिथिल करने का पूरा प्रयास किया। बिहार दलित पिछड़े सवर्ण बस्तियों से गुजरते थे वो अपना चप्पल हाथ में उठा लेते थे लालू ने उन्हें चप्पल पहिनने का अधिकार दिया। देश के राजस्थान जैसे प्रदेश में दलित दूल्हा आज भी घोड़ी पर नहीं बैठ सकता है लेकिन बिहार में ऐसा नहीं क्यों? क्योंकि बिहार में लालू का शासन रहा है। उन्होंने बिहार के लोगों के दर्द को समझा, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने मुंबई, दिल्ली के लिए ट्रेने चलाई। मोदी के हवाई चप्पल वाले भले ही हवाई जहाज से चलें हो लेकिन लालू के गरीब रथ में हवाई चप्पल वालों ने सफ़र जरूर किया होगा। हमेशा घटे में रही रेलवे को दुधारू गाय बना दिया। लालू की वजह से देश के हजारों कुलियों की जिंदगी संवर गई। यदि लालू अहीर नहीं होते तो लालू को भारत रत्न दिया गया होता|

राजनीतिक और सामाजिक हालातों की बात करें तो यह बात तो साफ है कि लालू प्रसाद जहां एक ओर राजनीति में मिसाल स्थापित करने में कामयाब रहे तो अपने राजनीतिक कैरिअर को बचाने में असफल रहे हैं। उनकी यह असफलता दलित और पिछड़े वर्ग के उनलोगों के लिए एक संदेश है कि ऊंची जाति के जबड़े से सत्ता को खींचकर बाहर निकालना ही बहादुरी नहीं है, बल्कि उसपर पूर्ण नियंत्रण के लिए भी सर्तक रहना चाहिए। ▪

डिजिटल चुनाव : लोकतंत्र को खतरा तो नहीं?

कन्नन गोपीनाथन
पूर्व आईएएस अधिकारी

ईवीएम से चुनावों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग इसपर अपना जबाब देता रहा है और मामला न्यायलयों तक गया। दुनिया के विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में जब महीने भर तक का इंतजार किया जा सकता है तो क्या वीवीपैट की गणना करना, देश के लोगों के भरोसे को कायम रखना के लिए जरूरी नहीं है। ऐसे समय में जब दुनिया डिजिटल होती जा रही है, डिजिटल फ्राड, क्राइम भी हो रहे हैं। ऐसे समय में डिजिटल चुनाव का भारत में कैसा भविष्य होगा इसे लेकर तमाम तरह की चिंताएं हैं। उपरोक्त के बारे में बसावन इंडिया से अरविन्द कुमार ने पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन से विस्तार से बात की। पेश हैं बात चीत के अंश...

सवालः मतदान समाप्त होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी सभी पार्टियों के बूथ एजेंटों को कुल पढ़े वोटों की संख्या लिखित रूप से देता है लेकिन मतगणना के दौरान यह चेंज कैसे आता है?

जबाबः जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन रात को पोलिंग पार्टियां वापस आती है और इलेक्शन कमिशन को रिपोर्ट देना होता है इलेक्शन कमीशन के लोग फोन करके पूछते हैं कहीं पर फोन लगता है कहीं पर फोन नहीं लगता एक हड़बड़ी होती है लोग बोलते हैं कि 50 लोग और लाइन में खड़े हैं कुछ आता है कि जल्दी काउंट कर मुझे नंबर दो कि कितने लोग लाइन में है यह नंबर सब जगह से आते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं गलतियां होने की संभावना होती है पीठासीन अधिकारी डायरी जिस दिन लाते हैं रात में हम कलेक्ट कर लेते हैं उसके अगले दिन स्कूटनी होती है। कई बार कई सारे बूथ में लिखना होता वो सारे लिखे ही नहीं होते हैं यह सब मैन्युअल ऐरर है।

सवालः ठीक है सर मैनुअल ऐरर मान लिया लेकिन मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी ईवीएम की टोटल बटन दबाता है फिर वही संख्या वह जिला निर्वाचन अधिकारी को देता है लेकिन मतगणना के दौरान यदि वहीं संख्या यदि नहीं आता है तो?

जबाबः जी बिल्कुल 100% सहमत हूं कि ईवीएम में स्टोर काउंट सही आना चाहिए चेंज तो किसी हाल में नहीं आना चाहिए यदि चेंज आता है तो वह गलत है किसी भी हाल में वह गलत नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है तो इस पर कमीशन को अपना जवाब अवश्य स्पष्ट करना चाहिए। गलती कहां हुई है उसकी जांच करनी चाहिए कई बार तो ऐसा देखा गया है, आर ओ/ ए आर ओ जो बड़े साहब द्वारा प्रत्याशी या एजेंटों को कुछ भी बता दिया जाता है वह मान लेते हैं क्योंकि उन्हें उसी जिले में रहना है और बड़े अधिकारी से लड़कर कब तक रहेंगे इसलिए दोस्ती बनी रहनी चाहिए आगे भविष्य में उन्हीं अधिकारियों के सामने कई सारे काम कराने पड़ते हैं इसलिए अधिकारी जो बोल देते हैं वही सही मान लेते है।

सवालः- यदि मतगणना में चेंज आया तो लोकसभा / विधानसभा की मत संख्या भी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि पिछले चुनाव में में यह अंतर लगभग 7000 वोटों का आया था, जिस पर आयोग ने अब तक अपना जवाब स्पस्ट नहीं किया इस पर आप क्या कहेंगें?

जबाबः जी बिल्कुल, कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। उसको अपनी वेबसाइट से डेटा डिलीट नहीं करना चाहिए। ऐसी समस्या कैसे आयी? क्यों अंतर आया है किस बूथ पर कितना अन्तर आया है। यदि सात हजार का अंतर कैसे आया सभी पर आयोग को जांच कर अपना जवाब स्पष्ट देना चाहिए ।

सवालः- जब व्यक्ति विधानसभा/ लोकसभा का प्रत्याशी किसी निर्दल या क्षेत्रीय पार्टी से होता है तो वह अपने बूथ पर अपना मतदान करता है लेकिन मतगणना के दौरान जब वह अपने बूथ संख्या की मशीन चेक किया तो उसी को शून्य वोट कैसे आया?

जबाबः जो व्यक्ति वोट किया है। उसे आप क्या कहेंगे बाई डिफॉल्ट मै मानकर ही चलता हूं लेकिन उसको शक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी यदि शून्य आया तो इसका उत्तर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से जबाब बनाता है। उसको बताना भी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि एक भी वोट नहीं हुआ या वही ईवीएम या वही वीवी पैट लेकर दोबारा टाइप करके एक बार या 50 बार या हज़ार बार सबके सामने उसको बटन दबाकर दिखा कर भरोसा दिलाना चाहिए की ऐसा नहीं हो रहा है। जिसको लगता है उसने अपने आप को वोट दिया और उसको ही नहीं वोट मिला। यदि एक व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ जाता है तो उसपर उनको वापस ले आने के लिए पूरे सिस्टम को मेहनत करने की जरूरत है। उसको नहीं कहना चाहिए कि तुमने वोट नहीं किया होगा। ऐसे जो सात हजार का फर्क है। जनता को विश्वास दिलाना होगा कि हमारी अच्छाई पर भरोसा रखिए। परन्तु यदि कोई नागरिक कहे कि हमने तो सही वोट किया है तो उसपर आप बोलेंगें कि नहीं तुम गलती किए होगे तुम पर हम भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा एक दूसरे के लिए हो सकता है, प्रशासन पर जनता भरोसा करे,

जनता पर प्रशासन को भी भरोसा करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमने वोट नहीं किया होगा मैं समझता हूँ गलत है। आखिर क्या हुआ जितना उनको समझने की इच्छा है, उससे अधिक चुनाव आयोग को चिंता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? यदि ऐसा कुछ हुआ है तो यह बड़ा इशू है। इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा मशीन को चेक करके दिखाने का ये जो ब्लाइड ट्रस्ट है हम नागरिक पर शक करेंगे लेकिन मशीन पर शक नहीं कर सकते हम जो वोटर है खुद पर शक करेंगे हर एक चीज पर शक करेंगे लेकिन मशीन पर सवाल नहीं उठा सकते। ये तो भगवान टाइप हो गया लोग भगवान पर भी सवाल उठा देते हैं लेकिन हम पर मशीन पर सवाल नहीं उठा सकते बस मशीन ने जो बोल दिया तो बोल दिया बस।

सवालः गोपीनाथन सर आप जिला निर्वाचन अधिकारी रहते हुए जब कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट की बीच वीवीपीएटी को जोड़ा गया था तब आपने आयोग से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रूपी वीवीपीएटी पर सवाल किया था तो आयोग ने क्या जवाब दिया था और आप वीवीपीएटी को किस तरह से देखते हैं?

जबाबः यह मुख्य मुद्दा था इससे पहले तक मैं खुद भी ईवीएम को डिफेंड करता था। मैं बहुत क्लियर नहीं था कि ईवीएम मशीन पर शक करो ना करो जो प्रक्रिया थी उसमें चांसेस बहुत कम था। सही था या गलत था पर मुझे नहीं पता, पर मुझे यकीन था कि सही है उसके बाद जब मैं दूसरी बार ट्रेनिंग के लिए गया तो बताया गया कि ईवीएम तो स्टैंडलोन है इसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। यह बिल्कुल केलकुलेटर की तरह है। कैलकुलेटर को तो बिल्कुल हैक ही नहीं किया जा सकता। वह तो 1+1=2 ही होगा। मैंने भी यही यकीन माना, लेकिन इस बार जब मैं गया तो बताया गया बटन दबाने के बाद नाम और सिंबल प्रिंट करके देगा मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि ऐसा यह कर कैसे सकता है 15-20 दिन पहले किसी भी विधानसभा /लोकसभा में प्रत्याशी को भी नहीं पता होता है कि वह वहां का प्रत्याशी होने वाला है या हो चुका है। तब तक टिकट का मारामारी चल रही होती है। जब इसमें किसी डिवाइस को जोड़ा नहीं जा सकता तो यह प्रिंट कैसे करके दे रहा है। जब मैंने इसके बारे में पूछा ऐसा कैसे हो सकता है। बताया गया कि हमारे इंजीनियर आकर मशीन में फिट कर देते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यदि इसमें कुछ डालना है तो इसमें एस एल यू सिम्बल लोडिंग यूनिट की डिवाइस इसमें कनेक्ट किया जाता है। यह पता होता है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है किस विधानसभा में जाएगी कौन यहां का प्रत्याशी होता है। चुनाव कब होना है। यह सभी सूचनाएं होने के बाद यह कैलकुलेटर कैसे रहा। यदि इसमें कुछ भी जोड़ा जाता है और प्रोग्रामिंग की जाती है तो यह कैलकुलेटर कैसे रहा? अर्थात ये कहाँ बताया और कहा लेकर आ गये।यह सब हमने चुनाव के दौरान आब्जर्व भी किया भी। समझना यही है कि जो यूएसबी है उसमें कहां से डाटा आया ? इसके लिए लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। लैपटॉप को इलेक्शन कमीशन की साइड से इंटरनेट द्वारा कनेक्ट किया जाता है। उसमें डाउनलोड किया गया। जनता से इतना बड़ा झूठ बोला गया। हमें जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए बल्कि उसे सच बताना चाहिए क्योंकि एक ही बार जनता स्वयं को नागरिक समझती है, जब वह वोट करती है, बाकी शेष दिन तो उसे प्रजा की तरह ही रखा जाता है। उस दिन भी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं जो बिल्कुल गलत है।

सवालः- सर आपसे वीवीपैट पर एक और सवाल माक पोल 100 या 200 इसके बाद हर 50वां वोट किसी और को जाता है तो उससे 2% बेमानी संभव हो सकती है जिससे देश का परिणाम बदल सकता है?

जबाबः आप ज्यादा बता रहे हैं। माकपोल की रिक्वायरमेंट 100 -200 नहीं, बल्कि 50 वोट ही करते हैं। यह तो पता है कि घर में जब बच्चों को मम्मी पापा देख रहे हैं तो बच्चे एक तरह के व्यवहार करेंगे जब नहीं हो तो दूसरे तरह के व्यवहार करेंगे। यदि आप बोल रहे हैं 50 और तो 50 ही देगा। लोग टेस्ट करेंगे 50 वोट जो हमने दबाया सही आ रहा है। बहुत सारी टेस्टिंग के बाद मशीन यदि गलत वोटिंग करें तो हम कहते हैं कि मशीन मैलसनसन हो गया। अरे! मशीन मैलसनसन कैसे हो सकता है?आपने दो बार उसी मशीन पर टेस्ट करवाया। आयोग का खुद का कहना है कि हम सारे टेस्ट करके भेजते हैं। तो जब मशीन दो अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग व्यवहार करें अर्थात हम मशीन में एक बार किसी एक को वोट जिसको दिया लेकिन मशीन किसी दूसरे को वोट दिया तो हमें यह मान कर चलना चाहिए की मशीन में गड़बड़ी या खराबी है। इसके बाद प्रूफ करना चाहिए कि मशीन में गड़बड़ी नहीं है। हम उल्टा करते हैं कि मशीन पर भरोसा रखें। यह किसी भी हाल में मैनुपूलेट नहीं हो सकती। मशीन में कुछ गड़बड़ी है ही नहीं। फिर सामने वाले से उल्टा बोलते भी हैं कि तुम करके बताओ और वीवीपीएटी ईवीएम उनके हाथ में देंगे भी नहीं प्रूफ करने के लिए। और बोलते ऐसा नहीं हो सकता है। हम अपने नागरिक को सिर्फ अपनी अच्छाई पर भरोसा दिलाते हैं। जबकि हमे सच्चाई को बताने की जरूरत है। सबसे ज्यादा मैं इस बात से परेशान था कि 2019 के इलेक्शन से पहले जो चीफ इलेक्शन कमीश्नर है उन्होंने प्रेस कॉनफ्रेन्स करके कहा था कि ईवीएम मशीन को किसी से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। उसमें टेक्निकल कमेटी भी बैठी थी। दोनों इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे। तब हम दो महीने बाद उसे लैपटॉप और एस एल यू लेकर कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे हम खुले आम झूठ कैसे बोल सकते हैं या लोगों को पता नहीं है। अगर पता है तो आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। हम बताना चाहते है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी संस्था है जिसका काम वोट करवाना नहीं बल्कि हमें वोट करना है इसलिए हमने इलेक्शन कमिशन बनाया। दूसरा सवाल हमें पूछना चाहिए वोट आखिर क्या है? आपने जाकर वह वोट दिया। आपको एक पर्ची दिखाई दी जिसे दो जगह स्टोर कर दिया गया है। एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा वीवीपैट। मैं यदि सवाल करूं इसमें आपका वोट कौन सा है? ना कमीशन को पता है ना आपको। मान लीजिए इसमें डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस का पता लगाने के लिए ही तो कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट के बीच वीवीपैट लगाया गया है। लेकिन इसमें से आप किसको वोट मानेंगे? वीवीपैट को मानेंगे या फिर आपने जो देखा था या फिर कंट्रोल यूनिट को मानेंगे जो आपने देखा ही नहीं। यदि हम पर्ची को वोट मानते हैं तो हर पर्ची की गिनती होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट की जगह पर जो कंट्रोल यूनिट में सेव है उसको काउंट करेंगे। जो कंट्रोल यूनिट में सेव है वह वोट है ही नहीं।

सवालः गोपीनाथन सर आप ने जिला निर्वाचन अधिकारी रहते हुए इलेक्शन के दौरान कई बार देखा होगा कि ईवीएम की कंट्रोल यूनिट या बैलट यूनिट खराब हो जाती है तो आप कंट्रोल यूनिट में लगे माइक्रोकंट्रोलर को बाहर निकाल कर देखा है इसमें क्या खराबी है या आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी लेवल के अधिकारी को भी देखने पर प्रतिबंध कर रखा है ?

जबाबः जी हम उसे नहीं देख सकते ऐसा प्रासेस ही नहीं है कि उसमें लगे माइक्रोकंट्रोलर को बाहर निकाल कर देखा जा सके। जी आपने बहुत ही सही सवाल किया कि निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी

होती है कि अपने नागरिक को भरोसा दिलाना तो किसी न किसी की ये भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी को भरोसा दिलाए। हर कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मास्टर माइंड तो है नहीं। वे भी तो अलग-अलग विषय से होते है या बहुत सारी फिल्ड से आते है। वीवीपीएटी आने के बाद क्या हुआ कि जब रैण्डमाईजेशन हो चुका होता है कि मशीन कौन सी विधानसभा में जाने वाली हैं। जब फार्म 7A प्रत्याशी का लिस्ट बन चुकी है। तब इक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं लैपटॉप और एस एल यू के द्वारा जो आप की कस्टडी में भी नहीं होती है ना ही अपने स्ट्रांग रुम में रखते है। फिर कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है। और जो वीवीपीएटी है उसका बेसिक फंडामेंटल है कि उसका एक्टिव वेरिफिकेशन होना चाहिए जो आपने नहीं करते हैं। दूसरा एडिटिंग करते हैं तो यदि चार या पांच सौ तो छोड़ ही दीजिए सिर्फ दो सौ बूथ में सिर्फ पांच बूथ का अर्थात 2.5% देख रहे हैं 97.5% नहीं देख ही नहीं रहें हैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कम्प्लीट प्रासेस से ना डिजाइन से। हमने इलेक्शन के दौरान भी उठाए फिर सबसे पहले हम कोई हल्ला नहीं किया बल्कि तीनों इलेक्शन कमीश्नर को ही चिट्ठी लिखा था उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ इंक्वायरी करेंगे फिर ना मुझे कोई जवाब आयोग की तरफ से मिला। उसके बाद कुछ आरटीआई किसी ने फाइल किया तो बोला सब कुछ ठीक है लेकिन किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं सब कुछ ठीक है ऐसे बोलते हैं जैसे कोई दारु पीके बोलता है सब ठीक कर देंगे वैसे ही बोलते हैं सब ठीक कर देंगे लेकिन जवाब नहीं दे रहे बस सबको अपनी नौकरी बचाने की पड़ी है बस।

सवालः चुनाव आयोग अक्सर दो तरह की मशीनें चुनाव में प्रयोग करता है एम 2 और एम 3 दोनों मशीनों में क्या अंतर है?

जबाबः इक्जैक्ट अन्तर आई एम नाट वेरी क्लीयर लेकिन सिरियस बात है पर इतनी बार इस बात को उठा चुका हूं। हम ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पार्टी ने हैक कर दिया। लेकिन ये कह रहा हूं दरवाजा खुला है चोरी हुआ कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा लेकिन दरवाजा खुला है ये तो आप पहले ही देख सकते हैया कोई आपको दिखा सकता है कि दरवाजा खुला है।

सवालः 2019 का लोकसभा चुनाव यूपी और बिहार में एम 3 मशीनों से कराया लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में पुनः एम 2 मशीनो से कराया था अब 2022 यूपी में भी एम 2 मशीनों से कराने जा रहे हैं आयोग जिले वार मीडिया में दे चुका है कही ऐसा तो नहीं चुनाव में घपला करने के बाद मशीनें हटा दी जाती हो?

जबाबः ये रीजन क्या है कमीशन ही जवाब दे सकता है नार्मली पूरी की पूरी मशीनें नहीं बदलती क्योंकि मशीनें स्टांग रुम में रखते है जितना एडीसनल ईवीएम की आवश्यकता है उतनी ही मशीन मंगाते हैं। ईवीएम मशीनें किस आधार पर हटाई जाती हैं मात्र एक ही चुनाव कराने के बाद मुझे पता नहीं चल पाया था और मैं उस पोजीशन पर नहीं रहा हूं कि आपको एक सेटिस्फेक्ट्री आंसर दे पाऊं।

सवालः अब बड़ा सवाल है यूपी में होने वाली मतगणना को लेकर कि आयोग 403 सीटों की मतगणना करता है यदि 100 सीटो की मतगणना 2 या 3 बजे समाप्त कर दिया जिसमें 90 सीटो में हार जीत का अंतर पांच हजार से ज्यादा वोट का है सिर्फ 10 सीट पर हार जीत का अंतर पांच हजार से कम वोट का आया लेकिन लास्ट की 100 सीटो की मतगणना रात 8 बजे के बाद चलीं गईं तो उसमें 90 सीटों पर हार जीत का अंतर दो हजार से कम होता है और सिर्फ दस सीटों पर दो हजार से ज्यादा वोट का होता है तो हैकिंग का सवाल उठना लाजिमी है?

जबाबः आप ने अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है और ऐसा सवाल उठाने की जरूरत है तो मुझे लगता है। आपने रिजल्ट के बेसिस पर एक सवाल उठाया है और आप एक हाइपोथेसिस किए हैं। रिजल्ट के बेसिस पर लेकिन रिजल्ट के बेसिस पर जो स्टडी आपने किया है। वह स्टडी मैंने नहीं किया है। लेकिन रिजल्ट के बेसिस पर सवाल उठाना मैं सहमत नहीं हूं रिजल्ट के बेसिस पर हम शक करेंगे तो थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, क्योंकि रिजल्ट इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। रिजल्ट के बेसिस पर मैं अपने आपको पीछे खींचता हूं। यदि आपको लगता है तो आप मुझसे क्यों कर रहे है बल्कि आप को ये सवाल अपने कंसर्न निर्वाचन अधिकारी या प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी या इलेक्शन कमीशन से करना चाहिए कि ऐसा क्यों है जो इतना अधिक अन्तर क्यों आ रहा है? रीजन क्या है? समझना जरूरी है प्रोसीजर बहुत सारा हो रहा है कि ईबीएम होटल में पकड़ा जा रहा है। जीप में पाया जा रहा है। ये सब भी कही न कही लोगों का जो भरोसा है उस पर अटैक करते हैं।

सवालः जब सभी पार्टियां ईवीएम मशीन का विरोध की कुछ पार्टियां तो ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी हैं तो ऐसे में चुनाव आयोग e voting पर रिसर्च कर रहा हैं। ये e voting क्या है?

जबाबः वो किस तरह की e voting करना चाहते हैं मेरा कमीशन के साथ जितने भी कंसर्न है इलेक्ट्रॉनिक एडवांस का डिजिटल एडवांस जनरेट करते हैं तो उसको पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर अगर पब्लिश करें की ई वोटिंग हम इस तरीके से करने वाले हैं यह हमारा पेपर है कोई साइंटिफिक पेपर है तो उसको दो-चार दस लोग देखेंगे ये सही या ग़लत है ये देखेंगे वो पब्लिस करने लायक है इसके बारे में सोचेंगे ऐसा कोई प्रासेस करते हैं तो देखिए ये साइंस का भी मामला है। साइंस और टेक्नोलॉजी भरोसे पर नहीं चलता है। प्रमाणिकता पर चलता है। एविडेंस थियरी प्रूफ करने की जरूरत है और साइंस में ही एक प्रासेस डिफाइन किया है कि हम फेयर रिव्यू करेंगे इस तरीके का पब्लिसन कार्यरत हैं हम वो सब नहीं करते। बस जिनको मन किया तीन चार लोगों का एक कमेटी बना दिया और वो कमेटी जो बोलेगी वो हम करेंगे। कुछ भी सवाल हो कमेटी से ना आप सवाल पूछ सकते हैं और कमेटी ना एक्स एबल है, तो जो आपके सवाल है ना कि ई वोटिंग की ओर बढ़ेंगे तो अभी तक इस पर 40 पेपर इसपे आना चाहिए था

वह भी एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से आना चाहिए था कि ई वोटिंग की क्यो जरूरत है और इसके क्या इशू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छूपाके रखेंगे कौन सा माइक्रोकंट्रोलर है आप बताएंगे नहीं ऐसा तो नहीं है कि सबको पता नहीं है इसके बारे में जो बना रहा है जो इसकी असेंबलिंग कर रहा है जो इसकी डिजाइन की है उसको तो पता है अभी हमने क्या किया है कुछ लोगों को पता है बाकी किसी को नहीं पता है ऐसे ही रखा है जिसको कहते हैं एक्यूरिटी-टू-एक्सूरीटी अभी मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर लाते हैं तो वह ओपन हैकिंग चैलेंज देते हैं। तो कमीशन ने भी दिया तो बोला कि आप टच नहीं कर सकते ईवीएम को ।आप दूर खड़े रहो हो और वीवीपीएटी नहीं था यह दो रीजन है लोग यही सवाल पूछते हैं जब भी इसके बारे में इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं कि कमीशन ने हैकिंग को रखा था तब जाकर तुम लोगों ने हैक क्यों नहीं किया अगर कर सकते थे तो। इसमें यदि मान लीजिए कि मैं जाकर हैक नहीं कर पाया इसका मतलब यह प्रमाण है कि कोई हैक नहीं कर पाऐगा। पहली बात और हैकिंग वाली घटना तो कमीशन को थोड़ा समझना चाहिए एविडेंस के अप्रूफ नहीं था और वीवीपीएटी नहीं था उस वक्त दूसरी बात। तो वीवीपीएटी आने के बाद जब हर ईवीएम को केबल से सीधा कनेक्ट किया जा रहा है तो उसमें जो चेंज हुआ है तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तीसरी बात अगर हैकर मशीन को बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तब दुबारा हैकर टोन जब चलाएंगे तो मशीन का फिजिकल एक्सेस आप जैसे इलेक्शन के दौरान देते हैं वैसे तो जो चैलेंज करना चाहते हैं तो उनको भी वैसे ही देना चाहिए। जैसे ईवीएम में कनेक्ट करके आप करते हैं जिसकी उनको जरुरत है उसके बाद देखेंगे कि क्या कर रहे हैं पर वो तो किया नहीं है। ये जो हैकर टोन का इशू है ना प्रूफ हो सकता था जिस तरीके से वह प्रूफ कराया गया। जो हम प्रूफ करना चाहते हैं तुम लोग नहीं कर पाओगे। एक होता है कि इसमें कुछ भी गलतियां हैं तो सुधार करेंगे पर कमीशन यह मान कर बैठा है इसमें कुछ गलती है ही नहीं आप लोग फालतू के शक पैदा कर रहे हो आप लोग ईबीएम विरोधी लोग हो जैसे ईवीएम का देश है तो ईवीएम देशद्रोही हो।

सवालः भाजपा को छोड़कर बहुत सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई 25%पर्ची का मिलान कराने के लिए लेकिन आयोग 100%पर्ची मिलान कराने की जगह 25 % भी पर्ची का मिलान नहीं कराता है तो वह संवैधानिक संस्था होते हुए भी आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा है?

जबाबः प्रशासन को क्या आसान है, 5 आसान है तो पांच कर दो। पर ये जो चुनाव है देश की जनता अपनी शौवरंटी (सम्प्रभुता) ट्रांसफर करता है सरकार को हमारे विकास का अभी आप लोग निर्णय लो हमारे निर्णय वो रहे हैं अगर उस वक्त हम कहेंगे की कि आधा दिन और काम करने में हम सक्षम नहीं हैं क्योंकि प्रशासन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा क्या है पांच अगर कर सकते हैं तो 50 नहीं कर सकते वही करना है चार लोगों को और लेना है अगर नहीं कर सकते तो अगले दिन कर सकते हैं इसको ऐसा क्यों रखे हैं की ईवीएम करने के बाद ही वीवीपीएटी को करेंगे जब आप पोस्टल बैलट पहले करते ही हैं तो वीवीपीएटी का प्रोसीजर पहले शुरू कर लीजिए फिर ईवीएम से बाद में कर लीजिए पोस्टल बैलट पहले आता है अगर पोस्टल बैलट आप पहले शुरू कर ही लेते हो तो वीवीपीएटी से क्यों नहीं कर सकते पहले पूरा प्रासेस है जनता को भरोसा दिलाने का नहीं है बल्कि हमें भी खुद को भी मशीन पर भरोसा करने का है कि सही है या नहीं। मैं यही पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा कांसीट्यूएंसी है जिसमें आधा दिन डीले कोई कैंडिडेट एमपी या एम एल ए चुन के आया तो वह क्या बदल देगा या क्या बदला है ना।

सवालः अब आपसे आखरी सवाल चुनाव आयोग कहता है कि डिजिटल इंडिया के दौर में हम पुनः बैलट पेपर पर नहीं लौट सकते तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आयोग जब ईवीएम का पोल खुलता हुआ देख रहा है तो कहीं घपला करने का दूसरा तरीका e voting तो नहीं है जिससे संविधान भी कमजोर हो सकता है?

जबाबः देखिए e voting पर बहुत सारे कंसर्न है पर आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है जब इसका आनरेबलटी भी सामने आया तो इसको एड्रेस ना करके मतलब इस पर जवाब ना दे हम कहें कि छोड़ो यार आगे की बात करते हैं जो हुआ है उसको छोड़ दीजिए आगे की बात करते हैं वह एक ऐसे दिशा में जा रहा है तो उनके जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं जो भी सवाल हैं मुझे पता है कि जवाब है ही नहीं बात यह है कि जवाब नहीं आ रहे।

कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर से लेकर मैं किससे मिला हूं यह नहीं बताऊंगा पर जो हाईएस्ट में रहते हैं उनसे लेकर जितने भी हैं उन सभी से बात कर चुके हैं यह कुछ बोल सकते हैं कि उसके अंदर हार्डवेयर कुछ ऐसा है तो ये बोल सकते हैं पर बता नहीं रहे हैं आखिर क्या है जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई प्रशासनिक रीजन कोई टेक्निकल रीजन नहीं है सवालों का। जब एक मुद्दे को ना एड्रेस करते हुए दूसरे पर भागते हैं तो वह सारे सवाल वहां भी आएंगे ऐसा नहीं है कि वह सवाल वहां खत्म नहीं होगा।

आपने प्रासेस नहीं स्टेबिलिस किया है सबसे बड़ी बात है लोग बोलते हैं इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए मान लीजिए ठीक है ईबीएम गलत है तो बैलट पेपर में आना चाहिए मैं बस यही कहूंगा करंट प्रासेस में ही इतनी सारी सलूशन आ सकता है पर सबसे पहले आपको कुछ प्रिंसिपल स्टैबलिस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रिंसिपल क्या है या इलेक्शन का प्रिंसिपल क्या है या फिर ऐसा कोई लास्ट इंसान हो उसको एक ही दिन लगता है कि नागरिक महसूस करने का मौका मिलता है उस दिन उसकी जान उसकी नॉलेज या जानकारी का अगर हम कुछ करते हैं उस दिन भी उसको पूरा यकीन होना चाहिए जिस को वोट किया है उसी को गया है वो नहीं कर सकते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपने नागरिक को अपने लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं ये बात हम सभी को समझना है।

अरविंद कुमार– गोपीनाथन सर रहा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर डिजिटल इंडिया के दौर में ईवीएम की विश्वसनीयता पर हमारे सवालों का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिए। ▪

गढ़ों में गढ़: प्रतापगढ़

▪ उमेश कुमार

प्रतापगढ़ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक नगर है, इसे लोग बेल्हा भी कहते हैं, सई नदी के किनारे बना है। प्राचीन कल में यह असुर क्षेत्र के रूपमे प्रसिद्ध था। ऐतिहासिक कल में यहाँ बहुत सी अनार्य जातियां निवास करती थी जिन्हें राक्षस नाम से जाना जाता था।

सई नदी, बकुलई नदी और गंगा का उपजाऊ मैदान में बसा यह क्षेत्र कृषि और पशुपालन गतिविधियों के लिए उपयुक और महत्वपूर्ण है। उपजाऊ मिटटी और पानी की पर्याप्त उपलब्धता खेती और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण था। इस क्षेत्र में निवास करने वाली अधिकतर पशुपालक और खेतिहर जातियां थी, कुर्मी, पासी, अहीर, कोइरी, धोबी, नाई, जैसी जातियों के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त था।

प्रतापगढ़ की बसावट

प्रतापगढ़ पूर्व में बेल्हा नाम से जाना जाता था। पट्टी, जेठवारा, लालगंज, मांधाता, कुंडा, कालाकांकर इसके प्रमुख कस्बे हैं। सिरखोरी, धरमपुर, आममऊ, गरीबदास, गड़वारीपुर, परामनाथ पुर, सेतापुर, बिहारपुर, लोहंगपुर, चिलबिला, मझिलाहन, बैजलपुर, महुली, देवकली, कुलिया, पूरे चौखड़, जगदीशपुर, पुरेभैया शहर से सटे हुए गावं है। जिनकी अधिकाश जनसँख्या दलितों और पिछड़ों की है जो खेती पशुपालन और बागवानी से जुड़े हुए है।

इतिहास में प्रतापगढ़ सराय नाहरराय

पुरातात्विक अवशेष

सराय नाहरराय नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गोखुर झील के किनारे पर स्थित है। इस पुरास्थल की खोज के.सी.ओझा ने की थी। यह पुरास्थल लगभग 1800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सराय नाहर राय में कुल 11 मानव समाधियाँ तथा 8 गर्त चूल्हों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था। यहाँ की क़ब्रें (समाधियाँ) आवास क्षेत्र के अन्दर स्थित थीं। क़ब्रें छिछली और अण्डाकार थीं। यहाँ संयुक्त रूप से 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफ़नाये जाने के प्रमाण हमें सराय नाहर राय से मिले हैं। सराय नाहरराय से जो 15 मानव कंकाल मिले हैं, वे ह्ष्ट-पुष्ट तथा सुगठित शरीर वाले मानव समुदाय के प्रतीत होते हैं।

अजगरा

रानीगंज तहसील के अजगरा में कई महत्वपूर्ण मध्यपाषाणयुगीन व गुप्तकालीन पुरावशेष प्राप्त है। यहाँ से पाए गए 48 पांडुलिपियाँ व महाभारतकालीन शिलालेख और मूर्तियाँ पुरातत्वविद निर्झर प्रतापगढ़ी द्वारा अजगरा संग्राहालय में संरक्षित है।

स्वरूपपुर

मान्धाता विकासखंड के ग्राम सभा गौरा में स्वरूपपुर ग्राम में पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्राचीन शिलाखंड, बौद्धकालीन अवशेष तथा खंडित मुर्तियाँ प्राप्त हुए हैं, प्राप्त अवशेषो को पुरावशेष एंव बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत 28 जनवरी 2011 को पंजीकृत किया गया।

किसान देवता मंदिर

कटरा गुलाब सिंह

कटरा गुलाब सिंह के निकटवर्ती क्षेत्रों के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष बौद्ध संस्कृति के प्रतीत होते है। प्राप्त भग्नावशेषों को पंजीकृत कर इलाहाबाद संग्राहालय में संरक्षित रखा है। इस क्षेत्र के दो तीन कि.मी. परिधि में कम से कम आधे दर्जन से अधिक पुरातात्विक महत्व के स्थान है।

परसुरामपुर

रानीगंज तहसील के परसुरामपुर स्थित चौहर्जन धाम में प्राप्त प्राचीन अवशेषो से कृष्ण लोहित मृदभाण्ड संस्कृति का पता चलता है।

स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रतापगढ़

जिसका असर यह रहा कि अक्तूबर 1920 में यहां अवध किसान सभा गठन किया गया। प्रतापगढ़ जिले का खर गावं किसान सभा की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आन्दोलन हुआ।

किसान देवता मंदिर

प्रतापगढ़ जिले में विश्व का इकलौता किसान देवता मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह किसी एक धर्म या संप्रदाय का मंदिर नहीं बल्कि किसान देवता के नाम से एक ऐसा धार्मिक संस्थान है जहां किसी भी धर्म व संप्रदाय के लोग आ सकते हैं। इस मंदिर का उद्देश्य किसानों को सम्मान दिलाना है। किसान देवता मंदिर प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के सराय महेश ग्राम में निर्मित है।

आवले का गढ़

प्रतापगढ़ जिला देश में आवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देश के कुल आवला उत्पादन का एक चौथाई आवला केवल प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ आम आवले का मुरब्बा, आचार और सूखे आवले के उत्पाद गृह उधोग के तौर पर है। प्रतापगढ़ जिले में सामंती प्रभाव के कारण कोई बड़ा आधारभूत उद्योग नहीं पनप सका ट्रैक्टर और आंवले की फैक्ट्री होने के बावजूद इस शहर के लोगों के सामने रोजगार का संकट है। वर्तमान में दोनों ही फैक्ट्रियां होने से बंद हो चुकी हैं। जिसके कारण यह क्षेत्र पूर्ण रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, जिसके कारण यहां के स्थानीय लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों को रोजगार के लिये अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ रहा है। ▪

@ +91 8707069223

आवले का बाग

परिवर्तन

मानवता की यात्रा में साथ साथ रहने के लिए तमाम संस्थाएं बनी जिसमे परिवार सबसे महत्वपूर्ण रहा है। हज़ारों साल से चल भी रहा है। भारतीय परिवेश में दुनिया से कुछ अलग तरह की मान्यता बनी खास कर जन्म जन्म तक साथ चलने की। पुनर्जन्म होता है कि नही, आज विज्ञान के युग में इसपर विश्वास करना कठिन है इसलिए साथ साथ चलने के तरीके मानवीय संबंध और तार्किक रूप से आज के मानवीय मूल्यों के आधार पर चलने का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हमारे बसावन इंडिया के सहयोगी और साथी राजकुमार यादव ने अर्चना चौधरी से संवैधानिक मूल्यों को सामने रखकर संविधान की शपथ लेते हुए साथ साथ चलने की शपथ ली।न कोई दहेज़, न कोई परहेज़, न किसी की अनुकंपा, शायद अप्प दीपो भव यानि अपना दीपक खुद बनकर दिया- बाती की तरह राज कुमार और अर्चना ने साथ साथ चलने का फैसला किया।

▪ **बसावन इंडियन डेस्क**

यह एक प्रकार से आने वाली भोर की शुरुआत है। देश में जिस प्रकार से कबीर, फूले अंबेडकर जैसे लोगों ने भारत में जो स्वप्न देखे थे कि आदमी, तार्किक होगा,मानवीय होगा। तार्किकता और मानवीयता के इसी क्रम में जौनपुर जिले के शफीपुर निवासी राज कुमार यादव (ओबीसी)ने आजमगढ़ मूल की लखनऊ निवासी की अर्चना चौधरी (अनुसूचित जाति) से 22 जनवरी को एक सादे समारोह में संविधान की शपथ लेते हुए विवाह किया। अर्चना चौधरी प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक हैं।

उनके साथी रूद्र प्रकाश का मानना है कि आने वाले दस बीस सालों में जब इस प्रकार के वैवाहिक संबंध आम हो जाएंगे, इसका मतलब हुआ कि राज कुमार और अर्चना अपने समय से दस- बीस सालों आगे चल रहे हैं। आज से बीस साल पहले अपने विवाह के बारे में सोंचना भी हमारे समाज में सही नहीं समझा जाता था। आज लोग कर रहे कि नही। आज हमें यह देखने और सुनने में अटपटा जरुर लग रहा है, क्षेत्र में इसकी चर्चा हो रही है लेकिन कुछ दिनों में यह आम हो जाएगा। सोशल मीडिया के प्रभाव से दुनिया ग्लोबल हो गई है उन्नत समाजों में विवाह के लिए क्या चाहिए होता है एक पुरुष और एक महिला। यहाँ भी ऐसा ही हुआ दो बालिग लोगों ने अपने विवाह का निर्णय लिया और विवाह कर लिया। ▪

आधा सिलेबस गायब कर दिया सरकार!

▪ मैत्रेयी सिंह

आजकल के समय को हम कोरोना का काल भी कह सकते हैं कोरोना के कारण हर चीज में कटौती हो रही है चाहे वह नौकरियों में हो या कमाई में। इसी क्रम में सरकार ने की सिलेबस मैं कटौती। इस साल सरकार ने कक्षा 9 और 10 में 30% सिलेबस हटाया है लेकिन यह तो बस कहने के लिए 30% है। वास्तव में लगभग 50% सिलेबस कटा है। जैसे कि इतिहास विषय को लेते हैं इतिहास में 2 वर्ष पूर्व तक 8 पाठ थे पिछले साल 3 पाठ किताबों से पूर्णतः हटा दिए गए शेष 5 पाठ बचे थे। उसके बाद कोरोना के कारण 5 में से भी दो पाठ हटा दिए गए, कहने को तो बस 30% है लेकिन लगभग 63% सिलेबस इतिहास की किताबों से गायब किया गया है। आप यह प्रतिशत देखकर ही जान सकते हैं बच्चों के पास पढ़ने को अब बचा ही क्या है? और यह जान सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? यह बस एक विषय का हाल नहीं है लगभग सभी विषयों में 50% सिलेबस हटाया गया है। हटाए जाने वाले पाठों के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि वह कितने महत्वपूर्ण पाठ थे। दसवीं के एक छात्र अभिषेक का कहना है कि यह तो बस आज का हाल है, शायद भविष्य में किताबों और विद्यालयों की भी कटौती हो जाए। स्वयं सावधान रहें और कटे हुए पाठों को स्वयं पढ़ें और अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें हैं।

कक्षा 10 की नागरिक शास्त्र से कटे हुए पाठ

लोकतंत्र और विविधता :

यह वह पाठ है जो हमें यह बताता है कि लोकतंत्र में सारी सामाजिक भिन्नताओं, अंतरों, असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान कैसे निकालता है? इस पाठ से यह भी पता चलता है कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस पाठ में हमें धार्मिक जातीय लैंगिक एवं रंग के आधार पर भेदभाव के बारे में पता चलता है और उसके बाद उसके प्रति लोगों के कामयाब विरोधियों के बारे में बताता है। हमारे साथ हो रहे भेदभावों के प्रति हमें अधिकारों के बारे में बताता है और सरकार के कर्तव्यों को बताता है जो उसे हमारे साथ हो रहे भेदभाव के प्रति करना चाहिए। इस पाठ को हटाकर सरकार बच्चों को उनके साथ हो रहे भेदभावों से तो अपरिचित रखना ही चाहती है साथ ही उनके अधिकारों के बारे में भी जाने नहीं देना चाहती है।

बानगी के तौर पर हम कुछ का प्रकाशन कर रहे है

अपने समाज में आदर्श स्त्री के बारे में प्रचलित इन सारी धारणाओं पर चर्चा करें। क्या आप इन सबसे सहमत हैं? अगर नहीं तो तो बताइए कि आदर्श स्त्री के बारे में आपकी धारणा क्या है?

जाति, धर्म और लैंगिक मसले

41

2021–22

दूसरा पाठ है ***जाति धर्म और लैंगिक मसले***। इस पाठ को हटाकर सरकार ने सबसे बड़ा अन्याय किया है। यह पाठ हमारे भारतीय समाज के सबसे बड़े अवगुणों से परिचित कराती है। हमारे देश के हर कोने में किसी न किसी प्रकार का भेदभाव होता है ही रहता है। चाहे वह उच्च जाति वाले निम्न जाति वालों के साथ करें या भारतीय परिवारों में लड़कियों के साथ| यह पाठ सभी बच्चों को उससे अवगत कराता है एवं उनसे बचने और लड़ने के बारे में बताता है। हमारे देश की उन लड़ाइयों के बारे में बताता है जो इन भेदभावों के खिलाफ लड़ी गई। इससे यह पता चलता है कि सरकार बच्चों को उनके साथ हो रहे या भविष्य में उनके साथ होने वाले भेदभावों से अवगत ही नहीं कराना चाहती। सरकार यह नहीं चाहती कि बच्चे यह जाने कि अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा हो तो उन्हें पता हो कि उसके खिलाफ कैसे लड़ें? तभी तो उन्हें उससे लड़ना नहीं बताया जा रहा है।

खुद करें खुद सीखें

देश के छह राज्यों में 'समय का उपयोग' संबंधी सर्वेक्षण किया गया। इससे पता चलता है कि एक औरत औसतन रोज़ाना साढ़े सात घंटे से ज़्यादा काम करती है जबकि एक मर्द औसतन रोज़ साढ़े छह घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दीख पड़ता है क्योंकि उससे आमदनी होती है। औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है लेकिन उनका ज़्यादातर काम घर की चारदीवारी के अंदर होता है। इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता।

समय का उपयोग (दैनिक-घंटे और मिनट में)

गतिविधियाँ	पुरुष	महिला
आमदनी वाले काम	6:00	2:40
घर के काम	0.30	5:00
गप्पबाजी	1.25	1:20
बिना काम के/फुरसत	3:40	3:50
सोना, अपने शरीर की साफ़-सफ़ाई, पढ़ना वगैरह	12.25	11:10

स्रोत : भारत सरकार, *समय का उपयोग* सर्वेक्षण,1998-99

आप अपने परिवार में भी 'समय का उपयोग' वाला सर्वेक्षण कर सकते हैं। अपने परिवार के सभी वयस्क पुरुषों और महिलाओं के काम पर एक हफ़्ते तक गौर करें और यह दर्ज करते चलें कि निम्नलिखित कामों पर हर आदमी कितना समय देता है : आमदनी वाले काम [दफ़्तर, दुकान या कारखाना अथवा खेत वगैरह में काम], घरेलू काम [खाना बनाना, झाड़ू-पोंछा-बरतन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, बच्चों और बूढ़ों की देखरेख करना वगैरह], पढ़ना और मनोरंजन, गप-शप करना, अपने शरीर की साफ़-सफ़ाई, आराम करना या सोना। ज़रूरी लगे तो आप नयी श्रेणी भी बना सकते हैं। इसमें से हर काम में जो समय लगता है उसका हफ़्ते भर का हिसाब जोड़ लें और फिर उसे सात से भाग देकर प्रत्येक सदस्य का रोज़ का औसत समय निकालें। क्या आपके परिवार में भी महिलाएँ पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं?

बात बोले भेद खोले

नारीवादी : औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष।

© NCERT not to be republished

लोकतांत्रिक राजनीति

42

2021–22

इस सारणी के हटा दिये जाने से महिलाएं अपने योगदान को कमतर आंकेगी

प्रो सुधांशु कुमार
दिल्ली विश्वविद्यालय

किताबों में लोकतंत्र का पाठ क्यों रखा गया था व्यक्ति के नागरिक अधिकारों के प्रति आप अपनी मांगों को रख सकते है। आन्दोलन कर सकते है। बच्चों को यदि इस प्रकार की ट्रेंनिंग ही नहीं होगी तो आने वाले दिनों में मुस्किल होगा। भारत ने एक दौर इमरजेंसी का भी देखा है। इमरजेंसी जब कांग्रेस सरकार ने लगाया था तो लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे क्यों कि उन्हें पता था की सरकार ने हमारे संविधान के खिलाफ काम किया है। बच्चों को यह पता कैसे चलेगा? जब उसको पढाया जायेगा/ बताया जायेगा तभी तो पता चलेगा।

भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता

जनगणना में प्रत्येक दस साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर-घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएँ जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं, ठीक वैसा ही फार्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फार्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएँ हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट से देश के छह प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी के अनुपात का पता चलता है।

आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बढ़ी है पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है।

एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएँगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति (इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया) के आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा लेकिन अगले पचास सालों में भी यह बढ़वार 3-4 प्रतिशत तक ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलट-फेर नहीं होने वाला।

यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ दो विशिष्ट समूहों : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैंकड़ों जातियाँ और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ 'अनुसूचित' शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में, जिन्हें आम तौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यत: वे हिंदू जातियाँ आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेल-जोल नहीं था। 2011 में, देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6 फ़ीसदी और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6 फ़ीसदी था।

जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती। इनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है— इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41 फीसदी है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग दो तिहाई तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग तीन-चौथाई है।

भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी, 2011

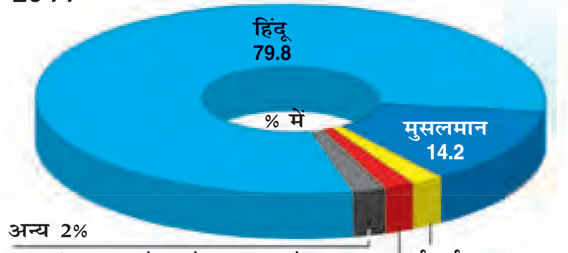

स्रोत : जनगणना, 2011

© NCERT not to be republished

इस पाठ के हटने से बच्चे सामाजिक और धार्मिक संरचना को समझने से वंचित रह जायेंगे

सीता चक 'केतन'
छात्र नेत्री

उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें सिलेबस में की गई चोरियों पर चर्चा नहीं है 20-25 वर्षों तक बहुजन वादी सरकारों ने शासन किया। उनके शिक्षा मंत्री बीएसए के ट्रांसफर-पोस्टिंग और शिक्षाधिकारी टीचरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, एमडीएम और स्कूलों बनाने के ठेकेदार बनने की होड़ में लग गए लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या पढ़ाया जाना चाहिए? इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। काश इस चुनाव में सिलेबस को गायब किया जाना भी एक मुद्दा होता।

इस पाठ में निम्न जातियों के साथ हो रहे भेदभावों को भी खुलकर बताया गया है और यह भी बताया गया है कि उन दलित लोगों का सिर्फ वोट बैंक की तरह प्रयोग हो रहा है।

अगला पाठ जो हटाया गया है वह है ***जन संघर्ष और आंदोलन*** का। यह पाठ पिछले पाठका ही आगे का भाग है। यह पाठ हटाकर संघर्ष और आंदोलन को कमतर करने की कोशिश की गई है।

बच्चों को जन आंदोलनों से दूर कर भविष्य में अगर अपने छिनते अधिकारों के प्रति लड़ना पड़े तो वह इससे अज्ञात रहें। भविष्य में जो अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं परंतु यह तब तक ही संभव हो सकता है जब तक कि बच्चों को यह पता हो कि उनके अधिकार क्या है? आंदोलन क्या है? महत्वपूर्ण आंदोलन कैसे हुए एवं उन्हें सफलता कैसे मिली? तब तक वह सफल आंदोलन नहीं कर पाएंगे और अपने उन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे जो अभी उनके पास हैं। परंतु भविष्य में शायद न हों।

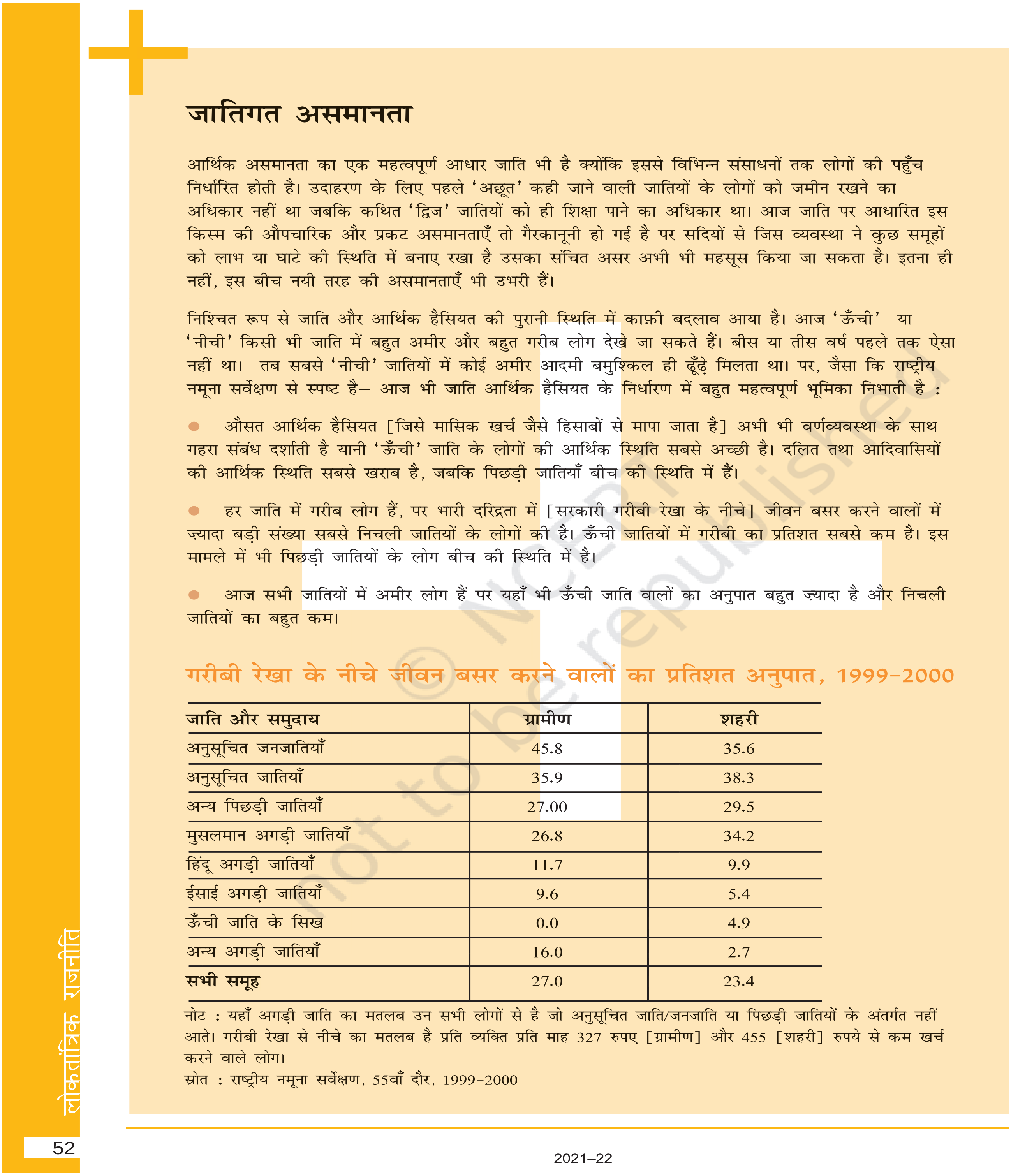

जातिगत असमानता

आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुँच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले 'अछूत' कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था जबकि कथित 'द्विज' जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएँ तो गैरकानूनी हो गई है पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा है उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नयी तरह की असमानताएँ भी उभरी हैं।

निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। आज 'ऊँची' या 'नीची' किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। बीस या तीस वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। तब सबसे 'नीची' जातियों में कोई अमीर आदमी बमुश्किल ही ढूँढ़े मिलता था। पर, जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है– आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है :

- औसत आर्थिक हैसियत [जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों से मापा जाता है] अभी भी वर्णव्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है यानी 'ऊँची' जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियाँ बीच की स्थिति में हैं।

- हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में [सरकारी गरीबी रेखा के नीचे] जीवन बसर करने वालों में ज़्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊँची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। इस मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में है।

- आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं पर यहाँ भी ऊँची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों का प्रतिशत अनुपात, 1999–2000

जाति और समुदाय	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जनजातियाँ	45.8	35.6
अनुसूचित जातियाँ	35.9	38.3
अन्य पिछड़ी जातियाँ	27.00	29.5
मुसलमान अगड़ी जातियाँ	26.8	34.2
हिंदू अगड़ी जातियाँ	11.7	9.9
ईसाई अगड़ी जातियाँ	9.6	5.4
ऊँची जाति के सिख	0.0	4.9
अन्य अगड़ी जातियाँ	16.0	2.7
सभी समूह	27.0	23.4

नोट : यहाँ अगड़ी जाति का मतलब उन सभी लोगों से है जो अनुसूचित जाति/जनजाति या पिछड़ी जातियों के अंतर्गत नहीं आते। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है प्रति व्यक्ति प्रति माह 327 रुपए [ग्रामीण] और 455 [शहरी] रुपये से कम खर्च करने वाले लोग।
स्रोत : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 55वाँ दौर, 1999–2000

© NCERT not to be republished

लोकतांत्रिक राजनीति

52

2021–22

इस पाठ के हटने से बच्चे गरीबी और जाति का अंतर्संबंध नहीं समझ पायेंगे।

अगला पाठ है लोकतंत्र की चुनौतियां। इस पाठ को गायब करना भी पिछले पाठों जितना ही हानिकारक है। यह पाठ हटाकर उन्होंने बच्चों को यह जानने का अवसर ही नहीं देना चाहते कि लोकतंत्र की कोई चुनौती भी हैं। अब छात्रों को यह पता ही नहीं होगा कि चुनौतियां है या नहीं है?या क्या चुनौती है? तो उसके प्रति विरोध कैसे करेंगे?

अप्रकट रंगभेद

इस मुल्क में पैदा होने की ग़लती करने वालों...

चले जाते हैं जो विदेश
बोलते हैं परायी भाषा–पहनते हैं अजनबी पोशाक
और भूल जाते हैं इस मुल्क को,
उन्हें मेरा सलाम!
और, जो नहीं भूलते
सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते
– ऐसे बेग़ैरतों से मैं पूछता हूँ:
क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे–
क्या होता है छुआछूत?
क्या यह ईश्वर की तरह ही अविनाशी है?
कैसा होता है अछूत? किसकी तरह दीखता है?
क्या वह खुद में कोढ़ की तस्वीर होता है,
या फिर, धर्माधीशों का दुश्मन?
क्या वह विधर्मी होता है–एक पापी या फिर नास्तिक?
बताओ मुझे!
क्या ज़वाब होगा तुम्हारा?
क्या तुम बग़ैर हिचकिचाए कह सकोगे:
मैं ही हूँ अछूत?
इसी से मैं कहता हूँ –
इस मुल्क में पैदा होने की ग़लती करने वालो!
तुम्हें अब ग़लती सुधारनी होगी–
या तो देश छोड़ो या युद्ध करो!
– बाबूराव बागुल की कविता का हिंदी अनुवाद

इस पाठ के हटा दिये जाने से बच्चे कभी नहीं जान पायेंगे की देश में छुआ-छूत जैसा कोढ़ भी है। न ही इसके प्रति उनका कोई चिंतन होगा और न ही कोई संवेदना

ये महत्वपूर्ण पाठ थे जिन्हें हटाकर बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान किया गया। इन पाठों को चुराना भविष्य में होने वाली बड़ी चोरियों का प्रथम चरण है। इसी कारण सावधान रहें, अपने उन अधिकारों के प्रति जो संविधान में आपको मिले हैं, लेकिन जल्दी से छीने जा सकते हैं। बसावन इंडिया द्वारा वानगी के तौर पर एक पाठ अपने पाठकों के लिए प्रकाशित किया जा रहा है- जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस पाठ को पढ़कर बाद में इस पर होने वाली चर्चाओं, प्रश्न आदि को भी प्रकाशित किया जायेगा। कृपया अपनी टिप्पणी/प्रतिक्रिया basavanindia@gmail.com पर दें। ▪

फिल्मों में : दक्षिण से आती बयार

फिल्म जय भीम ने ऑस्कर के यूट्यूब चैनल में अपनी जगह बना ली है। इस फिल्म को एकेडमिक अवार्ड के यूट्यूब चैनल पर दिखाया गया है।

▪ **बसावन इंडियन डेस्क**

दक्षिण भारत से अम्बेडकरवाद का सूर्य उदय हो रहा है। जहां एक ओर तामिलनाडु राज्य सरकार एक के बाद एक क्रांतिकारी फैसले ले रही है तो दुसरी तरफ दक्षिण भारत में बनी फिल्म काला, असुरन, जय भीम और पुष्पा की विश्व भर में चर्चा हो रही है। फिल्मी दुनिया में नया बयार बहने को तैयार है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या खान दानी, कपूर, चोपड़ा जौहर वंश जैसे वर्षों से फिल्म सिटी पर काबिज परिवार इससे कुछ सीख लेगा। मसाला फिल्मों में वही कल्पनाओं का दौर, विवाह और प्रेम प्रसंग सहित रक्षार्थ कोई सहाय हो जाए इसी के इर्द गिर्द घुमकर, मनोरंजन के नाम पर फुहड़ता का परोसा जाना आम है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक सरोकार की फिल्में नहीं बनी लेकिन अम्बेडकरवादी विचार को केन्द्र में रखकर फिल्मों को देखेगें तो बमुश्किल इक्का दुक्का मिलेगा, लेकिन इन दिनों दक्षिण भारत में बनी फिल्म जय भीम हो या हाल ही में आई फिल्म पुष्पा इन दोनों फिल्मों की चर्चा विश्व स्तर पर हो रही है।

'जय भीम' के निर्देशक ने नायक वकील को समाज के उच्च जातियों में व्याप्त शोषण की मानसिकता को एक के बाद एक खोल कर रख दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान घूमते हुए नंगे बच्चे और बत्तर हालाता में उसकी मां, आदिवासी पृष्ठभूमि की कहानी में जान डाल दी है। नायक अम्बेडकरवादी है और दूसरी ओर गाँव के शोषक सामंत घोर जातिवादी। फिल्म को कुछ इस तरह से बनाई गई है कि आदिवासी अस्मिता को इस स्वतंत्र भारत में भी एक बार फिर विचार करने पर मजबूर कर देती है। अम्बेडकरवादी समाज को फिल्म अंदर तक झकझोर कर रख देती है। फिल्म में जाति संघर्ष की जटिलता को बड़े पर्दे पर बहुत बारीकी से उकेरा गया है। अक्सर पुलिस अधिकारी को इन्हीं शोषणवादीयों के साथ गलबहियां करती दिखाई जाती है लेकिन जय भीम फिल्म में नायक और आदिवासियों पर हो रहे जुल्म पर पुलिस अधिकारी बने प्रकाश राज ने अपने अदाकारी से फिल्म को जीवंत बना दिया है।

फिल्म में सूर्या वकील चंद्रू और लिजोमोल जोस ने सेनगानी के किरदार को शानदार तरीके से निभाया। निर्देशक टी जे ज्ञानवेल ने कोर्टरूम को अच्छी तरीके से फिल्माया है। फिल्म जय भीम में मणिकंदन, राजीशा विजयन और राव रमेश जैसे कलाकार मुख्य किरदार में नजर आए हैं। यह फिल्म 1993 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें जस्टिस के चंद्रू का लड़ा गया केस दर्शाया गया है।

फिल्म जय भीम ने ऑस्कर के यूट्यूब चैनल में अपनी जगह बना ली है। इस फिल्म को एकेडमिक अवार्ड के यूट्यूब चैनल पर दिखाया गया है।

इस उपलब्धि के साथ ही जय भीम पहली ऐसी तमिल फिल्म बन गई है, जिसे यह मौका मिला है। इससे पहले यह फिल्म गोल्डन ग्लोब्स 2022 में बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में पहले ही ऑफिशियल एंट्री हासिल कर चुकी है।

जय भीम' शोषक वर्ग में हलचल पैदा कर दी है क्योंकि अब तक इनके कारनामें छुपी हुई रहती थी लेकिन निसंदेह तथाकथित बड़ी जाति कहे जाने वाले लोग जब ऐसी करतूतों से रुबरु होते हैं तो सामाजिक विमर्श की जगह मुंह छुपाने की कोशिश करते है। फिल्म अन्याय की सत्य घटना पर आधारित है। ऐसी घटनाएं आज आम है लेकिन क्या बड़े फिल्मी बाज ऐसी जातिय शोषण पर भी फिल्में बनाने की कोशिश करेगें।

एक और फिल्म 17 दिसंबर को 'पुष्पा' रिलीज हुई। ये कहानी है पुष्पा राज नाम के एक लड़के की. जो अपना करियर शुरू करता है एक मज़दूर के तौर पर। मगर उसका तौर तरिका ऐसा है कि वो किसी के सामने झुकता नहीं है। उसे किसी से ऑर्डर लेना ठीक नहीं लगता। वो नौकरी वगैरह छोड़कर सेशाचलम में लाल चंदन के धंधे का हिस्सा बन जाता है। अपनी काम करने के तरीके के चलते वो जल्दी ही इस फील्ड में ऊंचाई पर पहुंच जाता है। एक तरह से वो लोकल लेवल पर रेड सैंडलवुड स्मगलिंग का किंगपिन बन जाता है। फिल्म के केन्द्र में एक आदमी जिसे समाज ने नकार दिया है और वो अपने दम पर एंपायर खड़ा करता है।

'पुष्पा' में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज के नाम के किरदार को जीवंत बना दिया है। नायक का ऐटिट्यूड उसका सबसे बड़ा हथियार है। फिल्म 'पुष्पा' में हीरो ऐसे बात करता है, जैसे वो वाकई किसी से बात कर रहा हो। फिल्म में वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेज़ हैं, जो देखने में बढ़िया लगते हैं। ▪

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

PhonePe
ACCEPTED HERE
Scan & Pay Using PhonePe App

☐ वार्षिक ₹ 300/- ☐ 2 वर्ष ₹ 500/- ☐ 5 वर्ष ₹ 1000/-
☐ 10 वर्ष ₹ 5000/- ☐ आजीवन ₹ 10,000/-

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40640205456
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे पिछले अंकों के बारे में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।

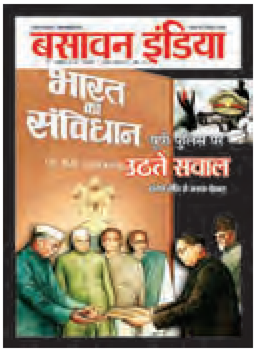

बसावन इंडिया मैगजीन के शुरुआती अंक समझ में नहीं आते थे लेकिन मैगजीन को फिर से पढ़ने पर समझ में आने लगी। गंभीर से गंभीर मुद्दों को बहुत ही हल्के अंदाज में पेश किया गया, जो इसे मनोरंजक बनाता है। मैगजीन में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि यह कहीं से बोझिल न हो। शुरू से अंत तक पढ़ने का आनंद बना रहता है।

अनिल कुमार
गोधना, मिर्जापुर

बसावन इंडिया पत्रिका पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका में है। पत्रिका में बनाए गए ग्राफिक पत्रिका की ओर अनायास ही आकर्षित करते हैं। यदि पत्रिका की एक झलक भर देख ली जाय तो इसकी विषय वस्तु समझ में आ जाती। कंटेंट और डिजाईन के स्तर पर यह बेजोड़ है। पत्रिका को और अधिक गंभीरता से प्रूफ किये जाने की आवश्यकता है। मात्रात्मक त्रुटियाँ चुभती हैं।

चंद्रशेखर
ममफोर्डगंज, प्रयागराज

आज जब मीडिया जनता के मुद्दों से भटक कर किसी एक व्यक्ति की महिमा में अपने मूल कर्तव्य को समर्पित कर चुकी हो इसके बावजूद भी बसावन इंडिया एक सकारात्मक पहल करते हुए जनता के मुद्दों को उठाने का कार्य करती हैं इसके लिए संपादक महोदय का आभार

अनुरूप बलबीर
ग्राम-नवाडेरा, जिला-बक्सर, बिहार

इस मैगजीन में विविधता है। अलग अलग मुद्दों को दिया गया है। सामाजिक चिंतन के वे विषय जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं का करती है। इसमें दिखाई देता है। संपादकगण को बहुत बहुत धन्यवाद

विशाल कुमार
सिविल लाइंस आजमगढ़

मैगजीन प्राप्ति के लिए संपर्क करें-

देशराज एडवोकेट (लखनऊ)
9454411702
परिभाषा (दिल्ली)
8826063330
कृष्णा पैकरा (रायपुर)
9713791376
संजीत बर्मन (बिलासपुर)
9754737875
सुनील कुमार सुनील (कानपुर)
7905051936
श्री कोमल प्रसाद (कुशीनगर)
9565869539
राम सिंह यादव (आजमगढ़)
9415085600, 9454479600
अनिल दीप चौधरी (जौनपुर)
9554687948
प्रमोद कुमार (जौनपुर/खुटहन)
9506473500
प्रदीप चौहान (जौनपुर/सदर)
7985658300
प्रवीन कुमार (गाजीपुर)
9415888054
संजय कुमार (चंदौली)
9415978381
मनोज कुमार (सोनभद्र)
9005800506
विनय कुमार (बलिया)
9415659396
विजय कुमार (वाराणसी)
9506722313
अरविंद कुमार गदर (झूसी प्रयागराज)
7651961448

प्रयागराज में लक्ष्मी चौराहे पर हिना पुस्तक केंद्र पर भी उपलब्ध है।

आधी आबादी : डॉ. लाल रत्नाकर के चित्रों की प्रदर्शनी

मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में डॉ. लाल रत्नाकर के चित्रों की एकल प्रदर्शनी 1 फरवरी से 7 फरवरी 2022 तक लगी, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने किया। मुंबई एवं देश के अनेक गणमान्य लोगों ने प्रदर्शनी में शिरकत की। प्रदर्शनी में मुंबई के कला प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कला प्रदर्शनी में दर्शकों के लिए उत्तर भारत के ग्रामीण चित्रों से आधी आबादी पर आधारित पेंटिंग्स आकर्षित करती रही खास करके महिलाओं के लिए इस तरह की प्रदर्शनी अनोखी प्रदर्शनी थी। तभी तो कलाकार- डॉ. लाल रत्नाकर अपनी आधी आबादी की तस्वीरों के बारे में कहते हैं- दुनिया जिसे आधी आबादी कहती है वही आधी आवादी मेरे चित्रों की पूरी दुनिया बनती है। यही वह आवादी है जो सदियों से सांस्कृतिक सरोकारों को सहेज कर पीढ़ियों को सौंपती रही है वही संस्कारों का पोषण करती रही है। कितने शीतल भाव से वह अपने दर्द को अपने भीतर समेटे रखती है और कितनी सहजता से अपना दर्द छिपाये रखती है। कहने को वह आधी आबादी है लेकिन शेष आधी आबादी यानी पुरूषों की दुनिया में उसकी जगह सिर्फ हाशिऐ पर दिखती है जबकि हमारी दुनिया में दुख दर्द से लेकर उत्सव-त्योहार तक हर अवसर पर उसकी उपस्थिति अपरिहार्य दिखती है जहां तक मेरे चित्रों के परिवेश का सवाल है, उनमें गांव इसलिए ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि मैं खुद अपने आप को गांव के नजदीक महशूस करता हूँ सच कहूँ तो वही परिवेश मुझे सजीव, सटीक और वास्तविक लगता है। बनावटी और दिखावटी नहीं।

जातीय जनगणना रिपोर्ट ग्राम-मुड़ाव, जिला-जौनपुर

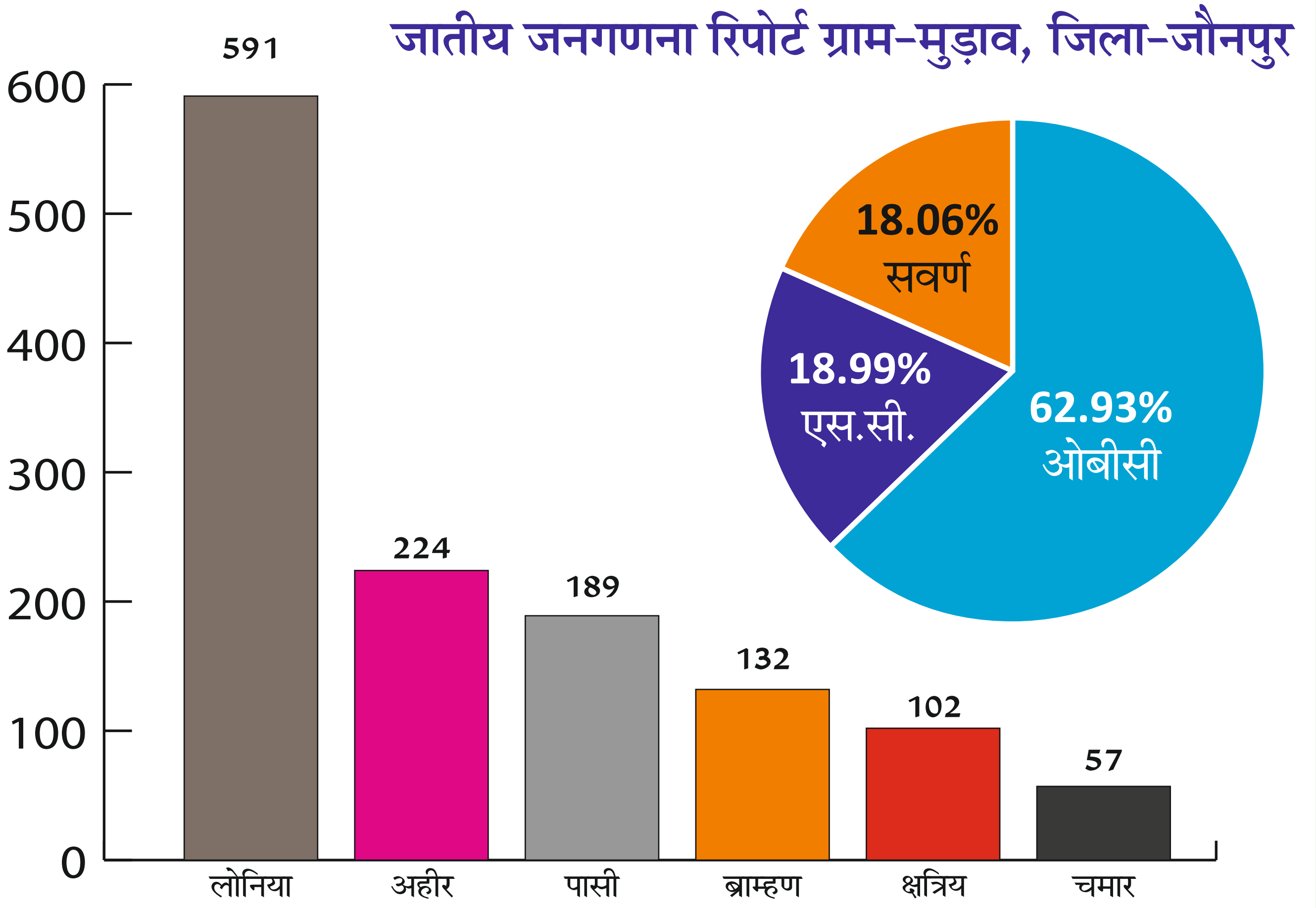

प्रस्तुत ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 21 पढ़ें।

18,M.G Marg, Civil Lines, Opp. Trishul Defence Academy, Prayagraj (U.P.)